चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 03 अप्रैल– 09 अप्रैल 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

प्रशांत किशोर यानि

पीके ने नाक कटाई

रणनीति और राजनीति पर्यायवाची शब्द नहीं हैं. इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है. चाहे वो राजनीति का सबसे बड़ा धुरंधर ही क्यों न हो, जब भी किसी ने रणनीति को राजनीति समझने की गलती की, वो चौपट हो गया. अगर चुनाव सिर्फ रणनीति के सहारे जीते जा सकते, तो पूरी दुनिया में राजनीति शास्त्र के पंडितों व विश्लेषकों की सत्ता होती. फिर राजनीतिक नेता और जननायकों की जरूरत ही नहीं पड़ती, पार्टी की जरूरत नहीं होती, विचारधारा की जरूरत नहीं होती, संगठन व कार्यकर्ताओं की भी जरूरत नहीं पड़ती. फिर कोई भी धनाढ्य व्यक्ति महंगे से महंगे रणनीतिकार को भाड़े पर रख लेता और चुनाव जीत जाता. आज देश के कई राजनीतिक विश्लेषकों को शर्मसार होना पड़ रहा है, क्योंकि वे रणनीति और राजनीति का फर्क भूल गए. राजनीतिज्ञों से श्रेय छीनकर उन्होंने रणनीतिकार को सुपर-हीरो घोषित करने की भूल की. प्रशांत किशोर यानि 'पीके' नाम के प्रसिद्ध पेशेवर चुनावी-रणनीतिकार का महिमामंडन इसी भूल का नतीजा है.

मनीष कुमार

भारतीय राजनीति में आज पीके एक बड़ा नाम बन गए हैं. पीके आमिर खान की फिल्म नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर का शॉर्ट नेम है. सत्ता के गलियारों और पत्रकारों के द्वीपनुमा संसार में इनकी काफी चर्चा होती है. जो लोग प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं, उनके लिए बता दूं कि पीके यानि प्रशांत किशोर पेशे से एक चुनावी-रणनीतिकार हैं. पारिश्रमिक लेकर यानि ठेके पर वे राजनीतिक दल व नेता के चुनाव प्रचार की पूरी व्यवस्था संभालते हैं. ये इनका पेशा है. पीके अब तक भारतीय जनता पार्टी, जदयू और कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं. 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान वे नरेंद्र मोदी के साथ थे. उसके बाद विधानसभा चुनावों में उन्होंने पहले नीतीश कुमार के लिए बिहार में प्रचार किया, उसके बाद से वे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की है. संयुक्त राष्ट्र में काम किया है. यही वजह है कि भारतीय मानसिकता-व्यवस्था में पीके सटीक बैठते हैं. वे अमेरिका-रिटर्न हैं, तो उनमें ज्ञान, अनुभव और कैलिबर होगा और वे ज्यादा समझदार होंगे, यह हर भारतीय सहर्ष स्वीकार कर लेता है. यही प्रशांत किशोर की अपनी ब्रांडिंग है. देश के बड़े-बड़े नेताओं को भी ऐसे लोगों की तलाश होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जो नए जमाने के मुताबिक नई रणनीति तैयार कर सके. यही वजह है कि चुनाव-प्रचार आज एक पेशा बन चुका है. इस पेशे में प्रशांत किशोर का नाम सबसे अव्वल है. मतलब यह कि पीके राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की रणनीति तैयार करते हैं. उनके पास 300 से ज्यादा लोगों की एक टीम होती है, जो कैंपेन के दौरान चौबीसों घंटे हर बात का ध्यान रखते हैं. रैली से लेकर टीवी और सोशल मीडिया, हर जगह उनकी टीम एक सुनियोजित प्रचार का संचालन करती है. इसके बदले में वे बाकायदा पारिश्रमिक भी लेते हैं. वो भी करोड़ों में. एक तरह से यह जायज भी है.

हार के बाद पीके फरार हैं

लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-समाजवादी पार्टी गठबंधन के बावजूद कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के बाद से प्रशांत किशोर लापता हैं. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली हैं. कांग्रेस के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी व शर्मनाक हार है. यही वजह है कि लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर यूपी कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश सिंह ने एक पोस्टर लगाया, जिस पर लिखा था- 'स्वयंभू चाणक्य प्रशांत किशोर को खोजकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन में लाने वाले किसी भी नेता को पांच लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा.' कांग्रेस से जुड़े लगभग हर कार्यकर्ता और नेता की यही राय है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की सेहत के लिए हानिकारक हैं. लेकिन राहुल व प्रियंका से प्रशांत किशोर की निकटता की वजह से कांग्रेस में उन्हें अभयदान प्राप्त है. अपने ड्रॉइंग रूम में कांग्रेसी नेता पीके को कोसते जरूर हैं, लेकिन खुल कर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है. फिर भी, चुनाव नतीजे के बाद से पीके लापता हैं. हैरानी तो इस बात की है कि जिन वरिष्ठ पत्रकारों ने बिहार चुनाव के बाद प्रशांत किशोर को इस युग का चाणक्य घोषित कर दिया था, वे भी लापता हैं. बिहार चुनाव के बाद देश के बड़े-बड़े विश्लेषकों ने पीके को देश का सबसे महान रणनीतिकार साबित करने की गलती की. कई अखबार और पत्रिकाओं ने तो लालू-नीतीश से जीत का श्रेय छीन कर पीके को दे दिया. यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी की हार की वजह सिर्फ पीके की रणनीति है.

पीके का जादू नहीं थी बिहार की जीत

बिहार चुनाव की हकीकत यह है कि अगर प्रशांत किशोर नहीं भी होते, तो भी बिहार का नतीजा जरा सा भी अलग नहीं होता. बिहार में नीतीश-लालू-कांग्रेस गठबंधन की जीत के पीछे पीके की रणनीति नहीं, लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति है. सोशल मीडिया और टीवी पर चलने वाले 'बिहार में बहार हो.. नीतीशे कुमार हो.' जैसे नारों की वजह से महागठबंधन नहीं जीता, बल्कि वोटों का अंकगणित महागठबंधन के पक्ष में था. नरेंद्र मोदी का विजय रथ बिहार में इसलिए रुका, क्योंकि लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी ने एक साथ मिल कर चुनाव लड़ने का राजनैतिक फैसला लिया. लालू यादव और नीतीश कुमार ने जिस तरह से मोहन भागवत के आरक्षण विरोधी बयान को मुद्दा बनाया और जिस तरह से उसे आखिरी दौर तक जीवित रखा, उसी वजह से नतीजा महागठबंधन के पक्ष में आया. बिहार में पीके की रणनीति नहीं, बल्कि लालू-नीतीश की राजनीति जीती. अगर बिहार में महागठबंधन की जीत के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वे लोग हैं जिन्होंने मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए लालू और नीतीश को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए मनाया. जीत का श्रेय उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने प्रशांत किशोर को हीरो बना दिया. लेकिन अब, जब उत्तर प्रदेश

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बिहार से भी लापता हैं प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर की तलाश अब सिर्फ लखनऊ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही नहीं है, बिहार में पूरा विपक्ष उन्हें ढूंढ रहा है. करीब एक साल से प्रशांत किशोर बिहार से गायब हैं. बिहार से उनका लापता होना एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है. प्रशांत किशोर की वजह से नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है. नीतीश कुमार की मुसीबत यह है कि वे प्रशांत किशोर के मामले में कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं. एक तरफ विपक्ष के नेता ताना मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की बेवफाई है.

नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बहुत विश्वास किया था. चुनाव जीतने के बाद ही उन्होंने प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया था. लेकिन वे पिछले एक साल से पटना से लापता हैं. बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने बड़ी आशा के साथ उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी. प्रशांत किशोर आज भी बिहार विकास मिशन के गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं. इस पद के लिए उन्हें कई सहूलियतें मिलती हैं. अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जो यात्राएं करते हैं, क्या उसके खर्च का वहन बिहार सरकार करती है? जब वे बिहार में रहते ही नहीं हैं और न ही बिहार सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या उनको दी गई सहूलियतों को नीतीश कुमार को वापस नहीं ले लेना चाहिए? क्या दूसरे राज्यों में कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए बिहार सरकार प्रशांत किशोर पर खर्च कर रही है? अगर अब तक वे खर्च बिहार सरकार करती रही है, तो क्या प्रशांत किशोर उस पैसे को वापस करेंगे? सवाल तो ये भी है कि क्या नीतीश कुमार की सहमति या आदेश पर प्रशांत किशोर देश भर में कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं?

नीतीश कुमार से इन सवालों को इसलिए पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार के विकास की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी भी प्रशांत किशोर के कंधे पर दे दी. प्रशांत किशोर पर बिहार-2025 विजन डाक्युमेंट तैयार करने की जिम्मदारी है. इसके लिए सिटीजन अलायंस नामक संस्था को 9.31 करोड़ रुपए भी दिए जा चुके हैं. ये पैसे कहां गए? बिहार-2025 विजन डाक्युमेंट तैयार हुआ है या नहीं? इसकी शुरुआत भी हुई है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे लेकर किसी रिसर्च स्कॉलर और प्रोफेसरों को इस काम पर लगा दिया गया है? सवाल तो ये भी है कि क्या एक विजन डॉक्युमेंट को तैयार करने के लिए 9.31 करोड़ रुपए दिए जाने सही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव जितवाने के पारिश्रमिक के रूप में विजन डॉक्युमेंट के नाम पर प्रशांत किशोर को करोड़ों रुपए दे दिए गए? इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पिछले छह महीने से प्रशांत किशोर पटना क्यों नहीं आए हैं? वे बिहार मिशन के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य हैं, फिर भी इसके कामकाज पर वक्त और ध्यान क्यों नहीं देते हैं? ये हैरानी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

योगी का कर्मयोग | P-4

चुटका परमाणु परियोजना : विस्थापित फिर होंगे विस्थापित | P-6

गांधी और हमारा दायित्व | P-7

पीके ने नाक कटाई

पृष्ठ 1 का शेष

और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हो गई है, कशीदे पढ़ने वाले विश्लेषक चुप हैं. हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया?

बिहार चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए काम करते थे. महागठबंधन बनने से पहले से वे नीतीश कुमार की ब्रांडिंग कर रहे थे. नीतीश कुमार ने दिल खोल कर काफी पैसा खर्च किया था, लेकिन ये बात और है कि नीतीश कुमार की होर्डिंग व पोस्टर पटना और उसके 40 किलोमीटर की परिधि में ही लगे. पैसे कहां खर्च हुए, इसका कोई हिसाब नहीं है. कांग्रेस पार्टी भी इस महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन राहुल गांधी को प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं था. चुनाव जीतने के बाद जब नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल पटना आए थे, तब नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को राहुल गांधी से मिलवाया था. नीतीश कुमार ने न सिर्फ राहुल से उन्हें मिलवाया, बल्कि पीके की प्रशंसा में कशीदे भी पढ़े. इसके बाद पीके राहुल गांधी से दिल्ली में भी मिले, लेकिन पूरी तरह से राहुल गांधी का भरोसा नहीं जीत पाए. इसकी वजह ये रही कि राहुल गांधी के पास पहले से ही सलाहकारों और रणनीतिकारों की पूरी टीम मौजूद थी. अलग-अलग जगहों से फीडबैक लेने के लिए राहुल गांधी के पास 40 लोगों की एक टीम है. ये कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि देश भर से चुने गए प्रोफेशनल्स हैं. इन्हें कई बार इंटरव्यू लेकर चुना गया है. यही वो टीम है, जिससे राहुल गांधी फीडबैक लेते हैं. राहुल गांधी को शायद प्रशांत किशोर से ज्यादा अपनी इस टीम पर भरोसा रहा हो, इसलिए शुरुआत में राहुल ने उन पर भरोसा नहीं किया. तब तक मीडिया में लगातार प्रशांत किशोर के बारे में लिखा जाने लगा था. कई लोगों ने उन्हें देश का सबसे बड़ा चुनावी-रणनीतिकार घोषित कर दिया था. लेकिन इसके बावजूद पीके राहुल गांधी का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हुए. इसके बाद, प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी को पकड़ा. प्रियंका गांधी को प्रशांत किशोर भरोसे के आदमी लगे. प्रशांत किशोर द्वारा किए गए चुनाव पूर्व सर्वे ने पीके को प्रियंका का और भरोसेमंद बना दिया. उस सर्वे में प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस द्वारा 72 सीटें जीतने का दावा किया था और उसके तर्क भी दिए थे. यहीं से प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री हो गई. प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव के फीडबैक के लिए अपनी अलग टीम बनाई. प्रियंका गांधी ही यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का वैक-ऑफिस चला रही थीं. वे हर दो-तीन दिन में प्रशांत किशोर से प्रेजेंटेशन लेती थीं. इसमें प्रियंका की पूरी टीम शामिल होती थी. कभी-कभी तो इस प्रेजेंटेशन के दौरान 100 से ज्यादा लोग मौजूद होते थे.

काम बोलता है...

पीके की कार्यप्रणाली का सच

अगर प्रशांत किशोर की कार्यप्रणाली को देखें, तो उनकी पूरी रणनीति में एक पैटर्न नजर आता है. वे कोई राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति नहीं हैं. वे एक अच्छा पीआर कैंपेन चलाने के माहिर हैं. उनकी रणनीति किसी एक नेता की ब्रांडिंग तक ही सीमित है. राजनीति में नेता तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सिर्फ किसी एक नेता के इर्द-गिर्द राजनीति सीमित नहीं होती है. प्रशांत किशोर की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि उनके कैंपेन के केंद्र में एक नेता ही होता है. उसी नेता की छवि के इर्द-गिर्द वे प्रचार-प्रसार का तानाबाना बुनते हैं. साथ ही फिल्मी अंदाज के दो तीन नारों के साथ वे अपनी रणनीति का ढांचा तैयार करते हैं. इस तरह की रणनीति से वे जनता में अपने क्लाइंट के परसेप्शन यानि अवधारणा को मजबूत करते हैं. यहां प्रशांत किशोर का ट्रिक समझना जरूरी है. व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की रणनीति देख कर वो नेता खुश हो जाता है, क्योंकि हर नेता के अंदर महान बनने या महान दिखने की लालसा मौजूद होती है. प्रशांत किशोर इसी का फायदा उठाते हैं. आज के दौर में तो कोई महात्मा गांधी या सरदार पटेल है नहीं, जिनका अपने सिद्धांतों पर हिमालय की तरह अडिग विश्वास हो. आज का दौर अवसरवादी राजनीति और हीन भावना से ग्रसित राजनेताओं का है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं से दूर और महिमामंडन करने वालों के नजदीक होना पसंद करते हैं. इसलिए प्रशांत किशोर की रणनीति हिट है. उनकी रणनीति पार्टी के शीर्ष में बैठे नेताओं का महिमामंडन करने वाली रणनीति होती है. इस तरह के प्रचार से नेता के अहम व अहंकार का पोषण तो होता ही है, साथ ही उन्हें खुद के महान होने का एहसास भी दिलाता है. वो नेता इतना खुश हो जाता है कि पीके उसके घर के बन जाते हैं. यह कोई आश्चर्य नहीं है कि बिहार हो या गुजरात, प्रशांत किशोर हमेशा मुख्यमंत्री निवास में ही रहते थे. जब तक वे मोदी या नीतीश कुमार के साथ रहे, सीधे उनके साये की तरह उनसे ही चिपके रहे. अब वे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं. इसलिए कांग्रेस का कोई भी नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा.

प्रशांत किशोर ने इस मीटिंग में बताया कि लखनऊ में राहुल गांधी की रैली होगी, जिस दौरान यह तय होगा कि किसे टिकट दिया जाए. जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, वे अपने साथ लोगों को लेकर आएं. रैली स्थल पर उनके लोग होंगे, जो हर नेता के साथ आए लोगों की गिनती करेंगे, बसों का हिसाब करेंगे. जो सबसे ज्यादा लोगों को लेकर आएगा, उसे टिकट दिया जाएगा. इस रैली के लिए प्रशांत किशोर ने पार्टी से पैसे भी लिए, लेकिन उसे खर्च नहीं किया.

प्रशांत किशोर ने प्रियंका का भरोसा तो जीत लिया था, लेकिन अब राहुल गांधी का भरोसा जीतना जरूरी था. इसके लिए पीके ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग की. इसमें उत्तर प्रदेश के सभी स्थानीय नेताओं को बुलाया और उन्हें आश्वासन दिया कि सबको टिकट मिल सकता है. प्रशांत किशोर ने इस मीटिंग में बताया कि लखनऊ में राहुल गांधी की रैली होगी, जिस दौरान यह तय होगा कि किसे टिकट दिया जाए. जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, वे अपने साथ लोगों को लेकर आएं. रैली स्थल पर उनके लोग होंगे, जो हर नेता के साथ आए लोगों की गिनती करेंगे, बसों का हिसाब करेंगे. जो सबसे ज्यादा लोगों को लेकर आएगा, उसे टिकट दिया जाएगा. इस रैली के लिए प्रशांत किशोर ने पार्टी से पैसे भी लिए, लेकिन उसे खर्च नहीं किया. कांग्रेस के सारे नेताओं ने अपने पैसे से लोगों को लखनऊ लाकर अच्छी खासी भीड़ जमा की. राहुल गांधी की लखनऊ रैली में 60 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे, जिसका पूरा क्रेडिट प्रशांत किशोर को गया. यहीं से प्रशांत किशोर के प्रति राहुल का भरोसा जगा.

उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू किया. अपनी कार्यप्रणाली के मुताबिक पीके को एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय करना था. ऐसा उम्मीदवार, जिसके इर्द-गिर्द पूरा कैंपेन केंद्रित किया जा सके. प्रशांत किशोर ने अपने सुविधानुसार सबसे पहले राहुल गांधी का नाम सुझाया. इससे पीके के दोनों ही पर्पस सॉल्व हो जाते. एक तो उनको अपनी सुविधा के मुताबिक एक परिचित चेहरा मिल जाता, जिसकी वो ब्रांडिंग कर पाते और दूसरा यह कि वे पहले की भांति पार्टी के सुप्रीम-नेता के खास बने रहते. लेकिन कांग्रेस में इसका जबरदस्त विरोध हुआ. राहुल गांधी को उनके लोगों ने समझाया कि अगर वे मुख्यमंत्री नहीं बन सके, तो 2019 में प्रधानमंत्री की रेस से वे पहले ही बाहर हो जाएंगे. इसलिए प्रशांत किशोर की ये योजना सफल नहीं हुई. (शेष पृष्ठ 3 पर)

बिहार से भी लापता हैं प्रशांत किशोर

पृष्ठ 1 का शेष

की बात है कि अब नीतीश कुमार ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? जो लोग नीतीश कुमार को नजदीक से जानते हैं, उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार इस तरह की चीजों से सख्त नफरत करते हैं.

प्रशांत किशोर को लेकर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का हमला तो सहना ही पड़ता है, साथ ही उनकी ही पार्टी में लोग अब पीके को देखना नहीं चाहते हैं. जदयू के नेताओं को लगता है कि बिहार चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर को जरूरत से ज्यादा भाव दे दिया गया, जिसके वे हकदार नहीं थे. नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियों की वजह से किसी ने भी प्रशांत किशोर के खिलाफ खुल कर कुछ नहीं कहा. लेकिन अब, जदयू के नेता खुले रूप से बोलने लगे हैं. लेकिन सवाल ये है कि वे बिहार से लापता क्यों हैं? नीतीश कुमार के साथ उनकी दूरियां क्यों बढ़ गईं? पटना में राजनीतिक हलकों में ये बात आम है कि नीतीश कुमार के एक मुख्य सलाहकार बनने के कुछ दिन बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को करीब दस करोड़ रुपए का बिल थमा दिया. पीके की टीम ने चुनाव के दौरान अलग-अलग जाकर जो काम किया था, यह बिल उसी से संबंधित था. नीतीश कुमार हैरान थे. उन्होंने ये बिल पार्टी के कुछ वरिष्ठ और भरोसेमंद नेताओं के साथ शेयर किया. उनके साथ इस विषय पर चर्चा की और प्रशांत किशोर को उनके पास भेज दिया. पीके को समझ में आ गया कि ये मामला जानबूझ कर लटकाया जा रहा है. उन्हें यकीन हो गया कि अब पैसा नहीं मिलने वाला है, तब उन्होंने बिहार सरकार से दूरी बना ली और अब वे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 05
03 अप्रैल- 09 अप्रैल 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

पीके ने नाक कटाई

पृष्ठ 2 का शेष

इसके बाद गहन चिंतन के बाद प्रशांत किशोर ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम सुझाया. ये एक ऐसी रणनीति थी, जिससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच निराशा की लहर दौड़ गई. प्रशांत किशोर को ये विश्वास था कि शीला दीक्षित के नाम पर कांग्रेस को ब्राह्मणों का वोट मिल जाएगा. लेकिन ब्राह्मणों का समर्थन मिलना तो दूर, बहुगुणा जैसी पुराने ब्राह्मण नेता पार्टी छोड़ कर बीजेपी में चले गए. प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने के लिए अपनी रणनीति को जमीन पर कार्यान्वित कर रहे थे. सबसे पहले उन्होंने यूपी में यह नारा दिया, '27 साल यूपी बेहाल.' उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार से बिल्कुल अलग थी, लेकिन पीके की रणनीति वही पुरानी थी. पीके की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मुख्यमंत्री का चेहरा होता है. बिहार में पीके का काम आसान था, वहां नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे. पहले से ही उनकी सकारात्मक छवि थी. बिहार में उनके सामने, उनके बराबर के कद का कोई विरोधी नेता नहीं था. इसलिए पीके ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द अपना कैंपेन रखा था, उसी तर्ज पर उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार की ब्रांडिंग की. सच्चाई ये है कि पीके के प्रचार-प्रसार के बिना भी नीतीश कुमार पहले से ही बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता थे. बिहार में नीतीश कुमार के लिए किसी रणनीति की जरूरत नहीं थी. लेकिन यहां तो शीला दीक्षित थीं, जो उत्तर प्रदेश की बहू हैं. चुनाव से पहले वे दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं, जहां उनके नेतृत्व में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई. शीला दीक्षित ने स्वयं अपनी सीट भी गंवा दीं. उस चुनाव में केजरीवाल के हाथों कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था. प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में शीला दीक्षित की ब्रांडिंग करने में पूरी तरह से विफल रहे. यह उनकी काबिलियत पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर है. मोदी और नीतीश कुमार जैसे लोकप्रिय नेता, जिनकी पहले से साख थी, उनकी ब्रांडिंग कर पीके ने तो खूब वाहवाही लूटी, लेकिन शीला दीक्षित की ब्रांडिंग, जो उनकी असली परीक्षा थी, उसमें वे फेल हो गए.

ऐसे पीके ने डुबोई लुटिया

ग़ौर करने वाली बात ये है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर का इस्तेमाल सिर्फ प्रचार-प्रसार में किया. राजनीतिक फैसले इन दोनों ने हमेशा खुद लिए. उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने अपने अनुभवी नेताओं को बेदखल कर राजनीतिक फैसले लेने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर पर छोड़ दी. पीके ने जब राजनीति में दखल दी, तो वे बुरी तरह से विफल हुए. प्रशांत किशोर को लगा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है और प्रदेश में किसानों के हालात ठीक नहीं हैं. इसे मुद्दा बना कर किसानों का समर्थन लिया जा सकता है. प्रशांत किशोर यह समझ नहीं पाए कि चुनाव में किसान कभी भी एक समूह होकर वोट नहीं डालता है. पीके ने सारी शक्ति एक ऐसी मृगतृष्णा के पीछे झोंक दी, जिसका चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलने वाला था. प्रशांत किशोर ने किसान मांग पत्र जारी कर किसानों से समर्थन जुटाने की कोशिश की. उन्होंने दावा किया कि किसान मांग पत्र पर उत्तर प्रदेश के एक करोड़ किसानों ने हस्ताक्षर किए. अब पता नहीं ये कैसे हुआ कि जितने किसानों ने किसान मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसका आधा वोट ही कांग्रेस को पूरे प्रदेश में मिला. पीके ने राहुल गांधी के लिए सबसे पहले खाट सभा और किसान रैली की तैयारी की. इसका मीडिया के जरिए बहुत प्रचार भी किया गया. ब्रांडिंग की गई. प्रशांत किशोर ने किसानों को लुभाने के लिए फिल्मी नारा भी दिया, 'कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब...' लेकिन इन नारों का असर किसानों पर नहीं हुआ. किसान खाट सभा से खाट भी उठा ले गए और वोट भी नहीं मिला. समझने वाली बात यह है कि किसानों का समर्थन सिर्फ इस तरह की सतही रणनीति से नहीं लिया जा सकता है. कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी से इतनी बड़ी गलती इसलिए हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने पार्टी के स्थानीय नेताओं से ज्यादा प्रशांत किशोर पर भरोसा किया. भारत के किसान फेसबुक-ट्विटर पर प्रचार और प्रोपेगंडा के बहाव में बहने वाले मतदाता नहीं हैं. 67 साल से लगातार धोखे खाकर आज का किसान परिपक्व हो चुका है. '27 साल यूपी बेहाल' जैसे नारों का असर गरीब किसान व मजदूरों पर नहीं पड़ता है. लेकिन स्वघोषित चाणक्य ने इसे मुख्य नारा बनाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगाने का दुस्साहस किया.

नारों से नहीं मिलती जीत

लखनऊ की रैली के बाद खाट सभा, किसान सभा और किसान मांग पत्र को प्रशांत किशोर ने प्रियंका और राहुल के सामने एक अपार सफलता के रूप में पेश किया. राहुल गांधी और प्रियंका कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से कटे ही रहे. इसका फायदा प्रशांत किशोर ने उठाया. वे प्रियंका को ये समझाने में सफल हो गए कि उनकी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी कम से कम 72 सीट जीत जाएगी. लेकिन प्रशांत किशोर अब तक समझ चुके थे कि शीला दीक्षित को पार्टी का चेहरा बनाकर वे कांग्रेस की नैया पार नहीं करा सकते हैं. इसलिए उन्होंने प्रियंका गांधी को गठबंधन की सलाह दी. कांग्रेस की तरफ से प्रशांत किशोर सबसे पहले मुलायम सिंह यादव से मिले. कांग्रेस के नेताओं के लिए ये खबर एक झंझावात से कम नहीं थी. टीवी पर हर कांग्रेसी नेता इस खबर को नकारता रहा, क्योंकि ये फैसला किसी भी पार्टी-पदाधिकारी के राय-मशविरा के बगैर लिया गया था. जब प्रशांत किशोर मुलायम सिंह यादव से मिले, तो मुलायम ने उन्हें अखिलेश यादव से मिलने के लिए कहा.

बेबी को बेस पसंद है

इधर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से कह दिया कि वे प्रशांत किशोर की बातें सिर्फ सुन लें, लेकिन कोई निर्णय न लें. इस वक्त तक गठबंधन की कोई बात नहीं हुई थी. अखिलेश यादव ने यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर से बात की, लेकिन कोई वादा नहीं किया. जब समाजवादी पार्टी में मुलायम परिवार का कलह उफान पर था, तब कांग्रेस के साथ गठबंधन पर दो राय थी, इसलिए गठबंधन पर कोई ठोस फैसला टलता रहा. यह राहुल गांधी और प्रियंका की राजनीतिक अनुभवहीनता का परिचायक है कि गठबंधन जैसे महत्वपूर्ण फैसले के लिए उन्होंने पार्टी के अनुभवी राजनीतिज्ञों को दरकिनार कर राजनीति के नौसिखिए पर भरोसा किया. कांग्रेस पार्टी की शर्मनाक हार दिवार पर इबारत की तरह प्रशांत किशोर लगातार लिखते रहे और लोग इसे रणनीति मानते रहे.

ऐसे हुआ सपा-कांग्रेस गठबंधन

उधर कांग्रेस में उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान पूरी तरह से प्रियंका संभाल रही थीं. उन्होंने अखिलेश यादव को दस से ज्यादा बार फोन किया, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका फोन नहीं उठाया. इसके बाद प्रियंका ने अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव को फोन किया. डिम्पल यादव ने अखिलेश से बात की, इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ. गठबंधन का रास्ता खुला. शुरुआत में अखिलेश किसी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे. जब गठबंधन पर राजी हुए, तो भी वे अजित सिंह की पार्टी को एक भी सीट देने के हक में नहीं थे. हैरानी की बात ये है कि जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात चल रही थी, तब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ जबरदस्त धोखा किया. गौरतलब है कि प्रशांत किशोर को राहुल गांधी से मिलवाने वाले नीतीश कुमार ही थे. चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में जाकर रैलियां की थीं. उनकी रैलियों को अच्छा समर्थन भी मिला था. वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल देना चाह रहे थे. लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से गठबंधन की पहल हुई, तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को साफ-साफ कहा कि अखिलेश को अजित सिंह से बात करनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार से कोई बात न करें. अब तक प्रशांत किशोर प्रियंका का भरोसा जीतने में कामयाब रहे थे. वे प्रियंका की टीम के साथ मिल कर रणनीति बना रहे थे. इस बीच नोटबंदी हो गई. नोटबंदी होने के करीब एक हफ्ते के बाद एक खबर उड़ी कि नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ही नीतीश कुमार ने नोटबंदी के समर्थन में बयान दिया. सूत्र बताते हैं कि ये झूठी खबर प्रशांत किशोर द्वारा फैलाई गई थी. प्रशांत किशोर के इस धोखे और विश्वासघात की वजह से ही नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर जाना पड़ा.

गठबंधन की पूरी बातचीत में राजबब्बर और गुलाम नबी आजाद को बाहर रखा गया. मतलब यह कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि अंदरखाने क्या चल रहा है. प्रशांत किशोर ने प्रियंका को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि राजबब्बर और गुलाम नबी आजाद ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने की प्रशांत किशोर की रणनीति की वजह से चुनाव के साथ-साथ संगठन को भी भारी नुकसान हुआ. राजबब्बर और गुलाम नबी आजाद जिन लोगों को टिकट देना चाहते थे, उन्हें हटा दिया जाता, क्योंकि प्रशांत किशोर और प्रियंका की टीम उससे बेहतर उम्मीदवार प्रियंका के सामने लाकर रख देते थे. उदाहरण के तौर पर, आगरा में राजबब्बर और गुलाम नबी आजाद द्वारा चुने हुए एक पुराने कांग्रेसी नेता का नाम काट कर प्रियंका ने एक बीजेपी के पूर्व-विधायक को टिकट दे दिया, जो उसी दिन कांग्रेस में शामिल हुए थे. बताया जाता है कि उनके कांग्रेस में शामिल होने से पहले ही उन्हें टिकट का भरोसा दे दिया गया था. यानि वे बीजेपी नेता कांग्रेस में इसी शर्त पर शामिल हुए कि उन्हें टिकट दिया जाएगा.

प्रियंका का पूरा विश्वास, प्रशांत किशोर द्वारा किए गए इस वादे पर टिका था कि कांग्रेस 72 सीट जीत रही है. लेकिन पहले व दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अलग-अलग सूत्रों से फीडबैक मिलने लगा. तब प्रियंका का विश्वास टूट गया और उन्होंने कैंपेन करने से मना कर दिया. इस बीच उनके परिवार के अत्यंत ही प्रिय बालक को चोट लगी, जिससे उनका मन चुनाव-प्रचार से और भी उठ गया. पहले दो चरणों के चुनाव से ही यह पता चल चुका था कि कांग्रेस-समाजवादी पार्टी गठबंधन एक शर्मनाक हार के मुंह पर खड़ी है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाने के बाद भी अनुभवहीनता की वजह से कई चीजें ऐसी हुईं, जो नहीं होनी चाहिए थीं. मसलन, टिकट और उम्मीदवारों को लेकर आखिरी वक्त तक उहापोह की स्थिति बनी रही. गांधी परिवार के संसदीय क्षेत्र में भी अगर सामंजस्य नहीं बन सका, तो यह बताता है कि कांग्रेस के डिसीजन-मेकर्स और रणनीतिकार यानि पीके को अभी कितना सीखने की जरूरत है. इन समस्याओं के बावजूद स्थिति इतनी खराब नहीं होती, अगर प्रशांत किशोर को राजनीति की समझ होती. गठबंधन की रणनीति का पूरा कमान प्रशांत किशोर के हाथ में था. समाजवादी पार्टी के मास्टर-रणनीतिकार शिवपाल सिंह यादव वैसे भी रूठे हुए थे. वे एक तरह से चुनाव से बाहर थे. जमीनी कार्यकर्ता और बुजुर्ग वोटर भी अखिलेश से नाराज थे. जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, तो इस पार्टी में सायकोफैंसी की हालत ये है कि बड़े-बड़े अनुभवी नेता राहुल के चेहरे को देखकर अपनी राय देते हैं. अगर राहुल गांधी खुश हैं, तो माना जाता है कि सबकुछ सही चल रहा है और राहुल नाराज, तो प्रलय. इसलिए कांग्रेसी नेताओं ने अब सच बोलना ही बंद कर दिया. यही वजह है कि प्रशांत किशोर को जो मन आया वो करते गए और कांग्रेस के स्थानीय नेता तो दूर, वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी जुबान नहीं खोली और न अब खोल रहे हैं. प्रशांत किशोर ने फिर उसी फिल्मी अंदाज में नारे दिए. आजकल एक प्रचलित गाना है- 'बेबी को बेस पसंद है.' इसी तर्ज पर प्रशांत किशोर ने नारा दिया- 'यूपी को ये साथ पसंद है.' रणनीति के नाम पर राजनीति का तमाशा अगर किसी से सीखना हो, तो उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर के क्रियाकलापों से सीखना चाहिए. इसके अलावा 'यूपी के लड़के' और 'काम बोलता है', जैसे असरहीन नारों के जरिए प्रशांत किशोर ने बची-खुची कमी पूरी कर दी. अब इन महान-रणनीतिकारों को कौन समझाए कि चुनाव नारों से नहीं, वोट से जीता जाता है. अच्छा नारा वो होता है, जिसका असर वोटर के दिमाग पर होता है. उत्तर प्रदेश में काम की जगह कारनामे की आवाज बुलंद हो गई और यूपी के लड़कों को वहां के बुजर्गों ने सबक सिखा दिया. लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये कैसी रणनीति थी, जिसमें मुसलमानों की समस्या और उनकी आवाज को दरकिनार कर दिया गया. मायावाती खुल कर मुसलमानों से वोट की अपील कर रही थीं. वहीं, राहुल और अखिलेश के एजेंडे से मुसलमान गायब था. यह कारनामा एक रणनीतिकार ही कर सकता था, कोई राजनीतिक व्यक्ति सपने में भी इतनी बड़ी भूल नहीं करता. यही वजह है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट का बंटवारा हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने झाड़ू चला दी.

चुनाव में हार और जीत लगी रहती है. लेकिन जिस तरह से सपा-कांग्रेस गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव हारा है, वो अविश्वसनीय है. इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर ने ही राहुल और अखिलेश की नैया डुबोई है. ये अलग बात है कि राहुल हार से सीखना नहीं चाहते. पिछले चुनाव यानि 2012 में उत्तर प्रदेश में मिली हार से उन्होंने कुछ नहीं सीखा. 2012 में भी उन्होंने बाहर से आए नेताओं को कांग्रेस संगठन के माथे पर बिठाने की गलती की थी. राहुल ने दिग्विजय सिंह और परवेश हाशमी की तीन साल की मेहनत को दरिया में फेंक दिया था. इस बार भी राहुल और प्रियंका ने वही गलती दोहराई. अपने पुराने व अनुभवी नेताओं के बजाय उन्होंने एक बाहरी पर भरोसा कर लिया. प्रशांत किशोर एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं. वे किसी अच्छी साख वाले लोकप्रिय नेता की ही ब्रांडिंग कर सकते हैं. उन्होंने अभी तक किसी भी अलोकप्रिय और बिना साख वाले नेता की छवि नहीं चमकाई है. ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की अनुभवहीनता ही कही जाएगी कि उन्होंने एक रणनीतिकार से राजनीति कराने का जोखिम उठाया. नतीजा सबके सामने है. प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए कब तक काम करेंगे ये एक रोचक प्रश्न है, क्योंकि अब तक प्रशांत किशोर ने जिसके साथ भी काम किया, उसे धोखा देकर आगे निकल गए. ■

लखनऊ की रैली के बाद खाट सभा, किसान सभा और किसान मांग पत्र को प्रशांत किशोर ने प्रियंका और राहुल के सामने एक अपार सफलता के रूप में पेश किया. राहुल गांधी और प्रियंका कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से कटे ही रहे. इसका फायदा प्रशांत किशोर ने उठाया. वे प्रियंका को ये समझाने में सफल हो गए कि उनकी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी कम से कम 72 सीट जीत जाएगी. लेकिन प्रशांत किशोर अब तक समझ चुके थे कि शीला दीक्षित को पार्टी का चेहरा बनाकर वे कांग्रेस की नैया पार नहीं करा सकते हैं. इसलिए उन्होंने प्रियंका गांधी को गठबंधन का सलाह दिया. कांग्रेस की तरफ से प्रशांत किशोर सबसे पहले मुलायम सिंह यादव से मिले. कांग्रेस के नेताओं के लिए ये खबर एक झंझावात से कम नहीं थी. टीवी पर हर कांग्रेसी नेता इस खबर को नकारता रहा, क्योंकि ये फैसला किसी भी पार्टी-पदाधिकारी के राय-मशविरा के बगैर लिया गया था.

manishbph24@gmail.com

योगी का कर्मयोग

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश में योगी का कर्मयोग बोलने और दिखने लगा है. शासन व्यवस्था दुरुस्त करने की तेज रफ्तार कवायद में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख कर उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी 'स्पीड' में आ गए हैं. मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करते ही सड़क से लेकर सत्ता गलियारे तक व्यवस्था चाक-चौबंद होती दिख रही है. पान-गुटखा से होने वाली पारिवेशिक गंदगी और छेड़खानी-लुच्चेबाजी से होने वाली सामाजिक गंदगी साफ करने की प्राथमिकता में किसानों के हित का काम भी उपेक्षित नहीं हो रहा है.

सांगठनिक तौर पर भाजपा परिवार में जिस तरह 'घुसपैठार्थियों' को टिकट देने में तरजीह दी गई, उसी तरह मंत्री बनाने में भी इसका ध्यान भले ही रखा गया, लेकिन काम में योगी किसी मंत्री को बख्शने वाले नहीं हैं, ऐसा लोगों को अभी से लगने लगा है. भाजपा के अपने पुराने पारिवारिक सदस्यों को यह मलाल जरूर है कि उन्हें यथोचित सम्मान नहीं मिला, जबकि उनका अधिकार अधिक था. भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से परामर्श लेकर ही मंत्रिमंडल का गठन किया. भाजपा के वरिष्ठ नेता यह जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने फैसले खुद लेने वाले आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं. वे नेता भी कहते हैं कि मंत्रिमंडल की पहली खेप का गठन भले ही केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में हुआ हो, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा. कई ऐसे विधायक जिनका मंत्री बनना पक्का माना जा रहा था, उनका नाम नदारद होना आश्चर्यजनक तो है, लेकिन इसे लेकर अभी सत्ता गलियारे में खास चुप्पी है. सबसे उपेक्षित मुजफ्फरनगर को माना जा रहा है, जहां से छह सीटें जीतने के बाद भी कोई विधायक मंत्री नहीं बना. भाजपाई यह आशंका भी जताते हैं कि योगी की सरकार कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की सरकार न बनकर रह जाए.

भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में जुटने वाली भीड़ और गहमागहमी में इस बात को लेकर चर्चा है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सरधना विधानसभा सीट से जीते संगीत सोम को मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिली! इसी तरह मुजफ्फरनगर की ही मीरापुर विधानसभा सीट से जीते अवतार सिंह भड़ाना को भी मंत्री नहीं बनाए जाने से लोगों में क्षोभ है. नोएडा विधानसभा सीट से जीते पंकज सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना लोगों को हैरत दे गया. हालांकि भाजपाई यह भी मानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बेटे को अभी फिलहाल मंत्री बनाए जाने से मना किया होगा. लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के धर्म सिंह सैनी, सुरेश राणा और अतुल गर्ग को मंत्री बनाए जाने के बावजूद भाजपाइयों को खास तौर पर संगीत सोम और भड़ाना को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर अफसोस है. भाजपा नेताओं को इस बात पर भी असंतोष है कि नौ 'घुसपैठार्थियों' को मंत्री पद दिया गया, लेकिन अपने सदस्यों की उपेक्षा कर दी गई. सपा, कांग्रेस और बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नौ नव-निर्वाचित विधायकों में कांग्रेस छोड़ कर आईं रीता बहुगुणा जोशी, नंदगोपाल नंदी, बसपा छोड़ कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, दारा सिंह चौहान, चौधरी लक्ष्मी नारायण, धर्म सिंह सैनी और समाजवादी पार्टी से आए एसपी सिंह बघेल और अनिल राजभर शामिल हैं, जिन्हें मंत्री का पद प्राप्त हुआ है.

उत्तर प्रदेश में बनी भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य व डॉ. दिनेश शर्मा उपमुख्यमंत्री के साथ 44 मंत्री शामिल हैं. इनमें पांच महिलाएं भी हैं. योगी मंत्रिमंडल में 22 कैबिनेट, नौ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 13 राज्यमंत्री शरीक हुए हैं. पेशे के दृष्टिकोण से योगी मंत्रिमंडल में 13 व्यापारी, 11 किसान, सात समाजसेवी, पांच वकील, चार शिक्षक, दो खिलाड़ी और एक डॉक्टर शामिल किए गए हैं. योगी मंत्रिमंडल में पिछड़ों को अधिक तरजीह देते हुए अन्य जातियों का समीकरण-संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में सबसे अधिक नौ पिछड़ों (ओबीसी) को स्थान दिया है. राजपूत और ब्राह्मण जाति के सात-सात विधायक मंत्री बने हैं. अति पिछड़ा समुदाय के भी छह विधायक मंत्री बने हैं. पिछड़ा कोटे से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, एसपी सिंह बघेल, धर्मपाल सिंह, कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी वगैरह शामिल हैं. जाट समुदाय के दो नेताओं लक्ष्मी नारायण चौधरी (कैबिनेट) और भूपेंद्र सिंह चौधरी (राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार) को मंत्रिमंडल में जगह मिली है. वैश्य समुदाय से आने वाले चार लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, जिनमें नंद कुमार गुप्ता 'नंदी' (कैबिनेट), राजेश अग्रवाल (कैबिनेट), अनुपमा जायसवाल (राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार) और अतुल गर्ग (राज्यमंत्री) शामिल हैं. कायस्थ जाति के भी एक विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह (कैबिनेट) को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली है. कुर्मी समुदाय के तीन विधायकों को मंत्री बनाया गया. इनमें मुकुट बिहारी वर्मा (कैबिनेट), स्वतंत्र देव सिंह (राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार) और जय कुमार सिंह 'जैकी' (राज्यमंत्री) को मंत्रिमंडल में जगह मिली है. यादव जाति से आने वाले गिरीश यादव को राज्यमंत्री बनाया गया है. योगी मंत्रिमंडल में दलितों और अति पिछड़ों को भी सम्मानजनक जगह दी गई है. कोरी समुदाय के मनोहर लाल पंथ उर्फ मन्नू कोरी (राज्यमंत्री), राजभर समुदाय से ओम प्रकाश राजभर (कैबिनेट), अनिल राजभर (राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार), बिंद-निषाद-नोनिया समुदाय से दारा सिंह चौहान (कैबिनेट) और जय प्रकाश निषाद (राज्यमंत्री) को मंत्री बनाया गया है. दलित समुदाय में चर्मकार जाति के रमापति शास्त्री, धोबी समुदाय की गुलाबो देवी (राज्यमंत्री) और पासी समुदाय के सुरेश पासी (राज्यमंत्री) को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है. सिख समुदाय के बलदेव सिंह ओलख (राज्यमंत्री) और मुस्लिम समुदाय के मोहसिन रज़ा (राज्यमंत्री) को मंत्रिमंडल में जगह मिली है.

योगी के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश की नौकरशाही में हड़कंप जैसा मच गया. शीर्ष सत्ता गलियारे से लेकर सरकारी विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव पद को लेकर नौकरशाहों की गतिविधियां शुरू हो गईं. मुख्य सचिव और डीजीपी की नई तैनाती की संभावनाओं पर जोड़तोड़ शुरू हो गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए तमाम नौकरशाहों की वीवीआईपी मेस्र हाउस में लाइन लगने लगी. सपा कार्यकाल में सत्ता गलियारे में लगे नौकरशाहों के जमावड़े को साफ करने की कवायद में सेंध लगाने की कोशिश वे नौकरशाह भी कर रहे हैं, जो माायावती या अखिलेश, दोनों के शासनकाल में बड़े प्रभावी रहे.

राजपूत समुदाय से आने वाले राजेंद्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' (कैबिनेट), जय प्रकाश सिंह (कैबिनेट), चेतन चौहान (कैबिनेट), डॉ. महेंद्र सिंह (राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार), सुरेश राणा (राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार), स्वाति सिंह (राज्यमंत्री) और रणवेंद्र प्रताप उर्फ 'धुन्नी सिंह' (राज्यमंत्री) मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं. ब्राह्मण जाति के भी सात विधायकों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली है. इनमें डॉ. दिनेश शर्मा (उपमुख्यमंत्री), रीता बहुगुणा जोशी (कैबिनेट), बृजेश पाठक (कैबिनेट), सत्यदेव पचौरी (कैबिनेट), श्रीकांत शर्मा (कैबिनेट), अर्चना पांडेय (राज्यमंत्री) और नीलकंठ तिवारी (राज्यमंत्री) शामिल हैं. खत्री समुदाय के तीन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिनमें सुरेश खन्ना (कैबिनेट), आशुतोष टंडन 'गोपाल' (कैबिनेट) और सतीश महाना (कैबिनेट) शामिल हैं. भूमिहार समुदाय के दो नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है. सूर्य प्रताप शाही (कैबिनेट) और उपेंद्र तिवारी को राज्य मंत्री बनाया गया है.

योगी मंत्रिमंडल में लखनऊ के सात मंत्री, डॉ. दिनेश शर्मा, बृजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी, आशुतोष टंडन, स्वाति सिंह, महेंद्र कुमार सिंह और मोहसिन रजा शामिल हैं. योगी मंत्रिमंडल की औसत उम्र 54 साल है. योगी खुद कह चुके हैं कि वे राहुल गांधी से एक साल छोटे और अखिलेश यादव से एक साल बड़े हैं. योगी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को राज्यमंत्री बनाया है, जिनकी उम्र 26 वर्ष है. पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद चेतन चौहान करीब 70 साल के हैं. योगी कैबिनेट के सबसे कम उम्र के मंत्री श्रीकांत शर्मा हैं. मंत्रिमंडल के पांच सदस्य उत्तर प्रदेश के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सांसद हैं. डॉ. दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर थे. स्वतंत्रदेव सिंह और मोहसिन रजा भाजपा संगठन से जुड़े हैं. अब इन लोगों को छह महीने के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा.

मंत्रिमंडल गठन के पूर्व 19 मार्च को राजधानी लखनऊ के स्मृति उपवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शहरी विकास आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन व सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महेश शर्मा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई आर. रूपानी, राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, नारायण दत्त तिवारी, अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉ. निर्मल कुमार सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और भारी जनसमूह की मौजूदगी में राज्यपाल राम नाईक ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के सहयोगियों को शपथ दिलाई.

योगी ने कहा सपा-बसपा के भ्रष्टाचार का हिसाब लेंगे तो वे बुरा मान गए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे सपा और बसपा के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेंगे और घोटालों का पूरा हिसाब-किताब लेंगे, तो सपा और बसपा के नेता बुरा मान गए. दोनों पूर्ववर्ती सत्ताधारी पार्टियां भ्रष्टाचार पर किए गए योगी के हमले के जवाब में पेशबंदियां करने लगीं.

योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है. इस अवधि में सत्ता पर काबिज रही सरकारें (सपा और बसपा) के भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ-साथ बदहाल कानून-व्यवस्था ने राज्य का और राज्य की जनता का भारी नुकसान किया. इसलिए मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार के तमाम पुराने अध्याय खोलेगी, उसकी जांच कराएगी

शेष पेज 5

योगी का कर्मयोग

पेज 4 का शेष

और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. इसके अलावा आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए प्रभावी कार्रवाई शुरू की जाएगी. योगी ने कहा कि भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर सजग रहेगी. मुख्यमंत्री ने चुनाव के पहले जारी भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र को शत-प्रतिशत लागू करने का संकल्प लिया और कहा कि लोक कल्याण के प्रति समर्पित प्रदेश सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी. योगी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और निर्देश में सबका साथ, सबका विकास लागू करने का दृढ़ निश्चय दोहराया और कहा कि शासन-प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा.

मुख्यमंत्री के इस बयान पर निवर्तमान सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी बौखला गई. सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने फौरन बयान दिया कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ ने समाजवादी सरकार के भ्रष्टाचार और नाकारेपन के बारे में जो बयान दिए हैं, वे तथ्यहीन और निराधार हैं. चौधरी ने योगी के बयान को दुष्प्रचार बताया और कहा कि संघ को ऐसे दुष्प्रचार की विशेषज्ञता हासिल है, योगी को उससे बचना चाहिए. बसपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी काम कम, दिखावा अधिक कर रहे हैं.

योगी की सख्ती गुटखागीरी, रोमियोगीरी से बूचड़गीरी तक

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही वो सारे मसले योगी-एक्शन के दायरे में आते दिखने लगे, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में मुद्दा बनते रहे हैं. योगी ने सत्ता संभालते ही प्रदेशभर में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया. बिजली की स्थिति दुरुस्त करने की कवायदें होने लगीं और लड़कियों के खिलाफ संरेआम होने वाली छेड़खानियों को रोकने के लिए लुच्चों पर सख्त कार्रवाइयां होने लगीं. प्रदेश के 11 जिलों में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन भी हो गया. प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए नौकरशाहों को कसमें तक खिलाई गईं. मुख्यमंत्री ने खुद सचिवालय के विभिन्न कक्षों का दौरा शुरू कर दिया और पान व गुटखा की गंदगी पर भड़क उठे. उन्होंने सरकारी परिसर में पान व गुटखा पर तत्काल रोक लगा दी और फाइलों पर अंटे पड़े धूल-गर्द को देख कर त्वरित गति

से फाइलों के निस्तारण का फरमान जारी किया. मुख्यमंत्री ने कार्यभार ग्रहण करने के दूसरे ही दिन हजरतगंज कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया और पुलिस को सुधर जाने की ताकीद की. उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का निर्देश दिया और कहा कि थाने पर फरियाद लेकर आने वाले शिकायतकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए. प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर तत्काल दर्ज करने को कहा गया है. एक तेजाब पीड़िता के साथ हुई बदसलूकी की खबर आते ही मुख्यमंत्री का उस युवती से मिलने अस्पताल पहुंच जाना भी आम लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग अभी से योगी की संवेदनशीलता की चर्चा करते मिल जाएंगे. मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही गौ तस्करी पर अविलम्ब पूर्ण प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दिए और इस अवैध धंधे में लगे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा. उन्होंने विभिन्न शहरों और कस्बों में संचालित अवैध बूचड़खानों और मांस की अवैध दुकानों को बंद करने के लिए तत्काल एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया.

योगी ने नौकरशाहों से साफ-साफ कहा कि जनता ने 'गुड गवर्नेंस' के लिए भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया है, लिहाजा जनता को चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामायण संग्रहालय के लिए 25 एकड़ जमीन देने की भी घोषणा कर दी. आपको याद होगा कि इस परियोजना के लिए मोदी सरकार पहले ही 154 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है.

योगी को याद है किसानों का हित, दिए सख्त निर्देश

किसानों के हित का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई न हो. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों के बकाये के त्वरित भुगतान के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं. पेराई सत्र 2015-16 की बकायेदार चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे किसानों के सम्पूर्ण बकाये का भुगतान एक माह के अंदर कर दें. मौजूदा पेराई सत्र 2016-17 की उन चीनी मिलों के मालिकों को भी निर्देश दिया गया कि जिन्होंने निर्धारित अवधि के अन्तर्गत किसानों को भुगतान नहीं दिया है, वे भी एक महीने में बकाये का भुगतान हर हाल में कर दें. योगी ने इस बारे में मुख्य सचिव राहुल भटनागर को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का समय से भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर सम्बन्धित मिल मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गन्ना आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 में प्रदेश की चीनी मिलों पर 22 मार्च तक 4,160 करोड़ रुपए बकाया हैं. इसके पहले के पेराई सत्र (2015-16) का भी 223 करोड़ रुपए बकाया है, यानि चीनी मिलों पर किसानों का 4,383 करोड़ रुपए का बकाया है.

अब कौन बनेगा यूपी भाजपा का अध्यक्ष!

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के यूपी का उप मुख्यमंत्री बन जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली होने वाला है. इसके साथ ही प्रदेश संगठन के कई पद खाली होंगे, जिसे जल्दी ही भरा जाना है. प्रदेश अध्यक्ष का पद किसे मिलेगा इसे लेकर कयास से ज्यादा छीना-झपटी शुरू हो गई है. जाति और परिवारवाद के खिलाफ तमाम सियासी तकरीरें पढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे से लेकर मंत्रिमंडल के बंटवारे तक जाति और परिवार को ही आधार बनाया. अब इसी आधार पर प्रदेश अध्यक्ष का पद झपटने की भी तैयारी है. प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर ब्राह्मणों में कुछ अधिक ही दावेदारी है. अधैर्य इतना है कि एक खेमे ने विजय बहादुर पाठक का नाम भी नए प्रदेश अध्यक्ष के बतौर चलवा दिया. पाठक के शरीर की भाषा भी अध्यक्षीनुमा बोली बोलने लगी. दूसरी तरफ दलित समुदाय के लोगों में यह मांग बढ़ी कि पिछड़ी जाति के अध्यक्ष के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उस दलित समुदाय के नेता को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, जिसकी राजनीतिक ताकत अधिक है और जिसने मायावती के खिलाफ अधिक लोहा लिया है और भाजपा का खुला साथ दिया है. राज्य की करीब बीस फीसदी दलित आबादी में 16 फीसदी वाली पासी जाति दूसरी सबसे बड़ी दलित उपजाति है. इस आधार पर पासी समुदाय के लोगों का दावा अधिक मजबूत है. अभी इस बारे में भाजपा आलाकमान ने स्पष्ट तौर पर तय नहीं किया है, लेकिन प्रदेश संगठन के कई नेताओं के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद खाली हुए महत्वपूर्ण पदों के लिए फौरन ही तमाम नेताओं ने जोर आजमाईश शुरू कर दी. आलाकमान ने अगर दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया, तो आगरा के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया, लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह, कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर, पूर्व विधायक मुंशीलाल गौतम और विद्याशंकर सोनकर के नामों पर विचार किया जा सकता है. कौशल किशोर पासी समुदाय से आते हैं. यूपी विधानसभा के चुनाव में मलिहाबाद सीट से उनकी पत्नी जय देवी चुनाव जीत कर आई हैं, लिहाजा इस रेस में कौशल की दावेदारी मजबूत मानी जा सकती है. लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक

आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जावीद अहमद को हटाने की चुनाव आयोग से मांग की थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. अब प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद दोनों शीर्ष अधिकारियों का स्थानान्तरण तय माना जा रहा है. मुख्य सचिव ने बसपा खेमे से सम्बन्ध बनाने के प्रयास शुरू कर दिए थे, लेकिन बसपा कहीं की नहीं रही. भाजपा के साथ अपने समीकरण प्रगाढ़ करने में पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल और वरिष्ठ आईएएस संजय अग्रवाल भी लगे हुए हैं. संजय अग्रवाल के भाई अनिल अग्रवाल गुजरात काडर में आईपीएस अफसर हैं, तो वे भी अपने भाई के लिए गुजरात-लाइन ठीक कर रहे हैं.

प्रधान की है, जिनके अथक प्रयास से मायावती के दलित वोट में सेंध लगी और भाजपा को बड़ी संख्या में दलित मत मिले.

इसी तरह प्रदेश संगठन के विभिन्न पदों पर भी मनोनयन होना है. टिकट वितरण में कई प्रतिबद्ध और प्रबल दावेदारों को टिकट नहीं मिला. कई क्षेत्रीय मंत्रियों तक को टिकट नहीं मिला जबकि कई जूनियरों को टिकट दे दिया गया. भाजपा नेतृत्व के इस रवैये के खिलाफ संगठन में अंदर-अंदर जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए उन सभी दावेदारों को प्रदेश संगठन में सांगठनिक पद दिए जाने की तैयारी हो रही है. इसके लिए खास तौर पर प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी गई है कि वे संगठन के खाली होने वाले पदों के लिए योग्य पदाधिकारियों का चयन करें.

इस सत्ता में भी गोटी लाल करने में लगे हैं नौकरशाह

योगी के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश की नौकरशाही में हड़कंप जैसा मच गया. शीर्ष सत्ता गलियारे से लेकर सरकारी विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव पद को लेकर नौकरशाहों की गतिविधियां शुरू हो गईं. मुख्य सचिव और डीजीपी की नई तैनाती की संभावनाओं पर जोड़तोड़ शुरू हो गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए तमाम नौकरशाहों की वीवीआईपी गेस्ट हाउस में लाइन लगने लगी. सपा कार्यकाल में सत्ता गलियारे में लगे नौकरशाहों के जमावड़े को साफ करने की कवायद में सेंध लगाने की कोशिश वे नौकरशाह भी कर रहे हैं, जो मायावती या अखिलेश, दोनों के शासनकाल में बड़े प्रभावी रहे. डीजीपी पद पर जावीद अहमद बने रहें, इसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं, तो मुख्य सचिव पद पर बने रहने के लिए राहुल भटनागर कोशिश में लगे हुए हैं. मुख्यमंत्री सचिवालय में जगह पाने के लिए नौकरशाहों का नया लॉट तैयार हो रहा है. अखिलेश सरकार के दौरान हाशिए पर रखे गए अफसरों को मुख्यधारा में लाने पर भी काम हो रहा है. खबर लिखे जाने से लेकर प्रकाशित हो जाने की अवधि तक शीर्ष सत्ताई गलियारे में नौकरशाहों के तमाम चेहरे फिट हो जा सकते हैं.

कई अफसर इस प्रतीक्षा में भी हैं कि नया मुख्य सचिव तय हो, तो वे उस मुताबिक अपने कार्ड खोलें. प्रदेश की शीर्ष नौकरशाही में तिकड़म के अवयव नेताओं से अधिक हैं. अब तो हाल यह है कि कोई भी बड़ा अफसर बड़ी आसानी से पहचान लिया जाता है कि वह किस पार्टी या किस नेता का चहेता है. कुछ अफसर आलू की तरह हर पार्टी में घुल जाते हैं और उनका स्वाद बन जाते हैं. जो अफसर तटस्थ और ईमानदार होते हैं, उन्हें सत्ताधारी पार्टी हाशिए पर डाल देती है. कई अफसर तो चुनाव परिणाम आने के पहले ही तमाम बड़े नेताओं और उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों के चक्कर लगाने लगे थे. इसी का नतीजा था कि चुनाव परिणाम आने के पहले ही मायावती-काल की तमाम प्रतिमाएं धुलने-पुछने लगी थीं और सारे पत्थर के हाथियों को नहला-धुला कर धूल-गर्द से मुक्त कर दिया गया था. चुनाव परिणाम आने के पहले ही बसपाई काल के सारे स्मारकों की साफ-सफाई हो गई थी. तब अखिलेश यादव की सरकार थी. प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे स्वनामधन्य अफसरों को लग रहा था कि अब तो मायावती ही आ रही हैं. प्रदेश की नौकरशाही का स्तर यही है.

आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जावीद अहमद को हटाने की चुनाव आयोग से मांग की थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. अब प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद दोनों शीर्ष अधिकारियों का स्थानान्तरण तय माना जा रहा है. मुख्य सचिव ने बसपा खेमे से सम्बन्ध बनाने के प्रयास शुरू कर दिए थे, लेकिन बसपा कहीं की नहीं रही. भाजपा के साथ अपने समीकरण प्रगाढ़ करने में पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल और वरिष्ठ आईएएस संजय अग्रवाल भी लगे हुए हैं. संजय अग्रवाल के भाई अनिल अग्रवाल गुजरात काडर में आईपीएस अफसर हैं, तो वे भी अपने भाई के लिए गुजरात-लाइन ठीक कर रहे हैं. प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी सदाकांत और अनूप चंद पांडेय की भी सक्रियता देखी जा रही है. सदाकांत कल्याण सिंह के खास अफसर रहे हैं. अनूप चंद पांडेय कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में सूचना निदेशक थे. पांडेय उमा भारती के निजी सचिव भी रह चुके हैं. दूसरी तरफ मुख्य सचिव से रिटायर होने के बाद अखिलेश यादव के मुख्य सलाहकार बने आलोक रंजन ने योगी सरकार के आते ही इस्तीफा दे दिया. उस पद के लिए भी कई पूर्व नौकरशाहों में प्रतियोगिता है. आलोक रंजन यूपीएसआईडीसी और फिल्म एवं टीवी इंस्टीट्यूट से भी हटेंगे, लिहाजा वहां भी स्थान पाने की कई अफसरों में अभिलाषा है.

प्रतिनियुक्ति पर गए कई अफसर भी अब वापस लौटने की जुगाड़ में हैं. बसपा और सपा सरकार में कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे. 1981 बैच के राजीव कुमार (प्रथम), 1982 बैच के जेएस दीपक, नीरज गुप्ता, प्रभाष झा, 1984 बैच के दुर्गा शंकर मिश्रा, 1986 बैच के प्रभात कुमार सारंगी, 1987 बैच के अरुण सिंघल, जीवेश नन्दन, 1988 बैच के आलोक कुमार (प्रथम), 1989 बैच के शशि प्रकाश गोयल समेत कई अधिकारियों की यूपी वापसी की चर्चा नौकरशाही गलियारे में तेज है. अखिलेश सरकार में मुख्यमंत्री के खास नौकरशाहों में आमोद कुमार, पार्थसारथी सेन शर्मा, पंधारी यादव, अमित गुप्ता, जीएस नवीन कुमार, अरविंद सिंह देव, अरविंद कुमार, राजीव कुमार (द्वितीय), रामरमण, प्रांजल यादव, कामरान रिजवी और संजय अग्रवाल वगैरह शामिल रहे हैं. जैसा आपको बताया कि इनमें से कई अधिकारी योगी के 'गुड-बुक' में आने के लिए हलकान हैं. बसपा और सपा के कार्यकाल में सत्ता का केक आपस में बांटने वाले नौकरशाहों की वाकायदा शिनाख्त हो चुकी थी. मायावती की सरकार में उनकी जाति के फतेहबहादुर के साथ-साथ नवनीत सहगल, अनिल सागर, कुमार कमलेश, दिनेश चंद्र, एसएम बोबड़े, सुधीर गर्ग, नेतराम और डीएस मिश्रा जैसे अधिकारियों की तूती बोलती थी. उन्हीं अधिकारियों में से कुछ की अखिलेश सरकार में भी तूती बोलती रही. अब वे योगी सरकार में भी अपनी तूती फिट करने की कोशिश में लगे हुए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

मध्य प्रदेश : चुटका परमाणु परियोजना

विस्थापित फिर होंगे विस्थापित नर्मदा का बढ़ेगा प्रदूषण

विकास के नारे के नीचे जल-जंगल-जमीन को खोखला करना कोई नई बात नहीं है. बेहतरी का सपना दिखा कर वर्तमान को बदरंग बनाना व्यवस्था का पुराना शगल रहा है. हालांकि ये सिर्फ पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए ही खतरा नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में रहने वाले लोगों के विनाश की पटकथा भी है. विनाश की एक ऐसी ही आहट से आज दो-चार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंडला और होशंगागद के लोग. एक तरफ मंडला के चुटका में जहां परमाणु प्लांट लोगों में दहशत का कारण बना हुआ है, वहीं होशंगाबाद के बाबई के लोग प्रस्तावित कोका कोला फैक्ट्री से डरे हुए हैं.

शशि शेखर

शिवराज सिंह चौहान ने 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की. लेकिन प्रदूषण, अवैध रेत खनन और जल में लगातार कमी से नर्मदा को बचाने के लिए सरकार के पास रोडमैप क्या है? अवैध रेत खनन और प्रदूषण का बढ़ता स्तर इतना खतरनाक रूप ले चुका है कि इसे सरकार कैसे रोक पाएगी, कहना मुश्किल है. इसके साथ हम दो और मुद्दों पर चर्चा करेंगे. मध्य प्रदेश में इस वक्त चल रहे दो आंदोलनों की भी बात करेंगे. इन दोनों आंदोलनों पर बात करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इनका संबंध भी नर्मदा प्रदूषण से है. ये दोनों मुद्दे इसलिए अहम हैं, क्योंकि इनका संबंध विस्थापन से भी है.

सबसे पहले बात चुटका परमाणु प्लांट की. मंडला जिले के चुटका में परमाणु प्लांट (बिजली) का प्रस्ताव पास हो चुका है. इसकी क्षमता 1,400 मेगावाट की है. इसके लिए दो परमाणु संयंत्र लगाने की बात कही जा रही है. लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है. लोग किसी भी कीमत पर यहां परमाणु प्लांट नहीं लगने देना चाहते हैं. ये लोग पूरी ताकत से इसका विरोध कर रहे हैं. लोगों को मालूम है कि ये प्लांट उनके लिए दुबारा विस्थापन का दर्द ले कर आएगा. मंडला क्षेत्र के डेढ़ सौ से ज्यादा गांव 90 के दशक में बरगी बांध से उजड़ चुके हैं. उन्हें आज तक न तो पर्याप्त मुआवजा मिला है, न ही ज़मीन. पहाड़ और जंगलों में रहने वाले ये लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं. नर्मदा नदी और बरगी बांध के किनारे रहने के बावजूद आज भी इनके खेतों को पानी नहीं मिल पाता. जाहिर है, खेती से जब इनका गुजारा नहीं होगा तो पलायन करना पड़ेगा. इसलिए जीवनयापन के लिए यहां के लोगों को बड़ी संख्या में पलायन भी करना पड़ता है.

परमाणु प्लांट की वजह से एक बार फिर इनके सिर पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है. लेकिन ये लोग फिर से विस्थापित होने का खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं. चुटका परमाणु प्लांट से तीन गांव विस्थापित होंगे. यहां तक कि एक गांव को आवासीय कॉलोनी के लिए उजाड़ा जाएगा. करीब 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कई गांव इससे प्रभावित होंगे.

प्रस्तावित परमाणु प्लांट के विरोध के लिए चुटका परमाणु संघर्ष समिति का गठन किया गया है. जनता विरोध प्रदर्शन व धरना कर रही है. चुटका, कुन्डा व टाटीघाट की ग्राम पंचायतों ने भी प्रस्ताव पारित कर इसके प्रति विरोध जताया है. चुटका परमाणु प्लांट के विरोध में स्थानीय आदिवासी समुदाय लगातार संघर्षरत है. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 17 फरवरी, 2014 को यहां पर्यावरणीय जन-सुनवाई हुई. स्थानीय समुदाय ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर विरोध दर्ज कराया. दूसरी तरफ, चुटका परमाणु प्लांट को आज तक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली है. इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का अवार्ड पारित किया गया है, जिसकी समस्त प्रक्रियाओं के प्रति ग्रामसभा द्वारा लिखित रूप में आपत्ति दर्ज कराया गया है. संविधान की पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को संविधान में सर्वोच्च स्थान दिया गया है तथा ग्रामसभा की अनुमति से ही भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है. लेकिन सरकार द्वारा ग्राम सभाओं के प्रस्ताव की भी अवहेलना की जा रही है. इसकी वजह से आदिवासियों की संस्कृति, संसाधन एवं सामाजिक पहचान खत्म होती जा रही है. गौरतलब है कि बरगी बांध से प्रभावित परिवारों का आज तक आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास नहीं हो सका है. विस्थापितों ने राष्ट्रपति से लेकर संबंधित विभागों तक से इस परमाणु बिजली-घर की योजना रद्द करने का आग्रह किया है.

सवाल है कि जब दुनिया के कई देशों में परमाणु बिजली-घर बंद किए जा रहे हैं, तब भारत के लिए यह कितना उचित है? गौर करने वाली बात यह भी है कि इस क्षेत्र में भूकंप का खतरा है. सरकार की आपदा प्रबंधन संस्था, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश की भूकंप संवेदी क्षेत्रों का जो विवरण तैयार किया गया है, उसमें इस बात का जिक्र है कि मंडला व जबलपुर भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र हैं. लेकिन न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर द्वारा तैयार रिपोर्ट में इस तथ्य को छुपाया गया है. 1997 में इस क्षेत्र में भूकंप आ चुका है, जिससे बड़े स्तर पर तबाही मची थी. यह प्रस्तावित परमाणु प्लांट हर एक दिन करीब 8 करोड़ घन मीटर पानी का इस्तेमाल करेगा. इससे बरगी बांध की सिंचाई क्षमता घटेगी और फिर प्रदूषण युक्त पानी से बांध और अधिक प्रदूषित होगा.

चुटका परमाणु बिजली संयंत्र का प्रभाव

विस्थापित ग्राम चुटका, विकास खण्ड नारायणगंज, जिला मण्डला, म.प्र. में है. यह पूर्व में नर्मदा घाटी में निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में बरगी बांध, रानी अवंतीबाई लोधीसागर परियोजना से विस्थापित हैं. 1984 में परमाणु ऊर्जा आयोग का विशेष दल स्थल निरीक्षण एवं जांच हेतु आया था. केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2009 में इसकी मंजूरी प्रदान की गई. न्यूक्लीयर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस परमाणु बिजली घर का निर्माण किया जाएगा. जमीन, पानी और बिजली आदि के लिए म.प्र. पॉवर जेनरेटींग कंपनी को नोडल एजेंसी बनाया गया है. 700 मेगावाट की दो यूनिट से 1400 मेगावाट बनाने के बाद जल्द ही इनका विस्तार कर 2800 मेगावाट बिजली बनाने का प्रस्ताव है. वर्तमान में शासन की मंशा है कि इस परियोजना से बरगी बांध के विस्थापित ग्राम चुटका, टाटीघाट एवं कुण्डा के लगभग 350 परिवारों को दुबारा विस्थापित होने पर मजबूर किया जाय. इस परियोजना के लिए 650 हेक्टेयर भूमि तथा 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित ग्राम सिमरिया के पास टाऊनशिप के लिए 75 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है. इस योजना की प्रारंभिक लागत 16,500 करोड़ की है. इस संयंत्र में नेचुरल यूरेनियम तथा कुछ मात्रा में थोरियम का उपयोग किया जाएगा. संयंत्र हेतु बरगी जलाशय से 128 क्युसेक पानी लिया जाएगा. इस संयंत्र के कारण 11 वर्ग कि.मी. के दायरे में 54 आदिवासी गांव में विकिरण का खतरा उत्पन्न हो गया है. इस संयंत्र के कारण जलाशय के जरिए जीविकोपार्जन करने वाले 2000 मछुआरों के परिवार की जिन्दगी पर संकट खड़ा हो गया है.

बरगी बांध से 162 गांव विस्थापित हुए हैं, जिसमें मंडला के 95, सिवनी के 48 तथा जबलपुर जिले के 19 गांव शामिल हैं. सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु बनी बरगी परियोजना में विस्थापितों को कम मात्रा में मुआवजा देकर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया और किसी प्रकार की पुनर्वास एवं पुनर्बसाहट योजना लागू नहीं की गई. इस परियोजना से प्रभावित होने वाले 70 प्रतिशत लोग गोण्ड आदिवासी समुदाय के हैं. इस परियोजना के विरोध को लेकर पांचवीं अनुसूची वाले ग्राम टाटीघाट, चुटका, कुण्डा, पाठा, पिण्डरई, सिंगोधा, झांझनगर एवं माने गांव विकास खण्ड नारायणगंज, जिला मण्डला, म.प्र. की ग्रामसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है. इसी प्रकार पिपरिया, पीपाटोला एवं धुमा विकास खण्ड घंसौर, जिला सिवनी, म.प्र. की ग्रामसभा और मानिक सराय, लालपुर एवं सांगवा वि.ख. बीजाडांडी, जिला मंडला, म.प्र. की पंचायत ने भी परियोजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है. इसी विरोध के कारण 24 मई एवं 31 जुलाई, 2013 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर द्वारा आयोजित पर्यावरणीय सुनवाई स्थगित करनी पड़ी थी. दूसरी बार, शासन द्वारा भारी पुलिस बल के साये में 17 फरवरी, 2014 को जन-सुनवाई आयोजित करवाई गई, जिसमें स्थानीय आदिवासी समुदाय ने भारी संख्या में विरोध दर्ज कराया.

सिर्फ सेवा यात्रा काफी नहीं है...

एक रिपोर्ट के अनुसार नर्मदा में लगभग 100 नाले मिलते हैं. नालों में प्रदूषित जल के साथ-साथ शहर का गंदा पानी भी बहकर नदी में मिल जाता है. इससे नर्मदा जल प्रदूषित हो रहा है. मुख्यमंत्री ने नागरिकों से जल प्रदूषण रोकने की अपील तो की, लेकिन ये अपील काम नहीं आ रही है. एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश के 16 जिलों से गंदे नालों का प्रदूषित पानी नर्मदा में गिरता है. होशंगाबाद में 29 नाले हैं, मंडला में 16 और जबलपुर जिले में 12 बड़े नाले हैं. ये नाले नर्मदा को प्रदूषित कर रहे हैं. गंदे पानी के साथ ही रासायनिक अवशिष्ट को भी नर्मदा में बहाया जाता है. राज्य सरकार ने नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के लिए पैसे भी खर्च किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ.

दूसरी तरफ, इस वक्त मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई के मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में कोका कोला कंपनी के मेगा प्लांट की आधारशिला रखी गई है. ये दावा किया जा रहा है कि इस प्लांट से 500 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा. लेकिन नर्मदा के निकट इस प्लांट के स्थापित होने से स्थानीय लोग नर्मदा के संभावित प्रदूषण की भी बात कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि नर्मदा को किसी भी कीमत पर प्रदूषित नहीं होने देंगे. कोका कोला कंपनी को 110 एकड़ जमीन दी गई है. कंपनी नर्मदा से प्रतिदिन लाखों लीटर पानी निकालेगी जिससे नर्मदा के पानी में कमी आएगी. साथ ही फैक्ट्री का प्रदूषित पानी, रासायनिक पदार्थ आदि नर्मदा में जाएंगे. इससे नर्मदा प्रदूषित होगी. स्थानीय स्तर पर इसका विरोध शुरू हो गया है. यहां के मोहासा और गुराड़िया मोती पंचायत में कंपनी के विरोध में प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं. मुहासा के 10 गांवों में लोगों का विरोध सामने आने लगा है. लोगों का तर्क है कि इसमें नर्मदा नदी से पानी लिया जाएगा और प्रतिदिन 18 लाख लीटर पानी का उपयोग किया जाएगा. एक लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में पांच लीटर पानी की बर्बादी होगी. बचे हुए रसायनिक पानी को बहा दिया जाएगा. इससे क्षेत्र की खेती और नर्मदा नदी दोनों प्रभावित होंगे. कई साल पहले भोपाल के पास पीलूखेड़ी में भी कोका कोला का प्लांट लगा था, वहां आज पार्वती नदी सूख चुकी है. सवाल है कि परमाणु बिजली का विकल्प क्या है? जाहिर है, देश में सौर उर्जा, पवन उर्जा जैसे विकल्प भी हैं. आज देश में जितना बिजली उत्पादन होता है, उसमें परमाणु बिजली का योगदान सिर्फ तीन फीसदी ही है. बहरहाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार इसी तरीके से नर्मदा नदी को प्रदूषण रहित बनाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

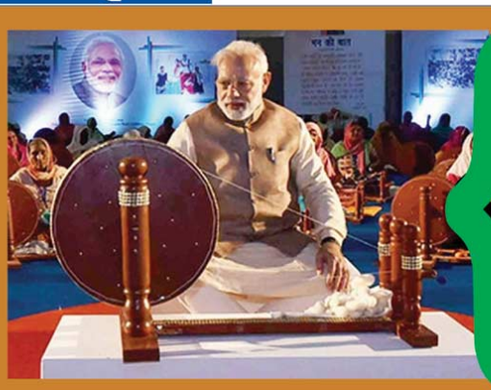

मेरे चले जाने के बाद कोई भी एक व्यक्ति मेरा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा, परंतु मेरा थोड़ा-थोड़ा अंश तुममें से अनेक में रहेगा. यदि तुममें से प्रत्येक व्यक्ति ध्येय को प्रथम और स्वयं को अंतिम स्थान देगा, तो मेरे रिक्त स्थान की बहुत कुछ पूर्ति हो जाएगी.
- गांधी.

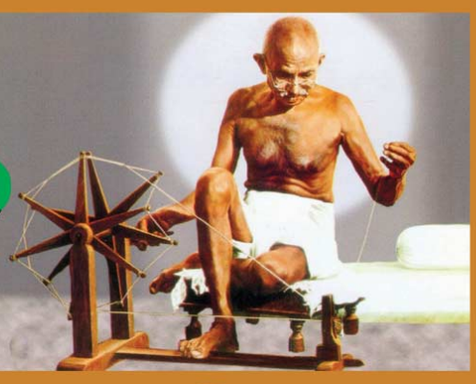

गांधी और हमारा दायित्व

गिरिराज किशोर

उपरोक्त उद्धरण 'बापू की शहादत' शीर्षक से सर्वोदय जगत संख्या-40, में प्यारे लाल जी के लेख के आरंभ मे उद्धृत है. मुझे इस उद्धरण ने झकझोर दिया. बापू को अपने और अपने लोगों पर कितना गहरा विश्वास था. यह तो सही है कि उनके जाने के बाद कोई उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया. क्षमा कीजिए, संत विनोबा जी भी उनके संपूर्ण प्रतिनिधि नहीं थे, यद्यपि थे. मैं न एक एक्टिविस्ट हूं, न उस तरह से दीक्षित गांधीवादी हूं. एक लेखक हूं. उसी के चलते मैंने उनके बारे में लिखने का साहस किया. लेकिन मैं उनके वक्तव्य के दूसरे अंश के बारे में भारी हृदय से कहने की अनुमति चाहता हूं कि उनके इस विश्वास पर शायद हम खरे नहीं उतरे, उनका थोड़ा बहुत भी जो अंश है, उसको प्रमाणित करने में असफल रहे. उनके रिक्त स्थान की पूर्ति तो पूर्ति, उनके सम्मान की यथोचित रक्षा तक नहीं कर पाए. हालांकि मैं यह जानता हूं कि हम जैसे नगण्य लोग, ध्येय को अपने से आगे नहीं रख पाए. इसके अनेक कारण हो सकते हैं, शायद वे व्यक्तिगत अधिक हैं. बापू समष्टिवादी थे और हैं, हम में से अधिकतर व्यक्तिवादी और स्वार्थी हैं. मैं अंदर ही अंदर यह मानता हूं कि हम बापू के सम्मान की या उनके इस संकल्प की रक्षा नहीं कर सके, वैसे उन्हें हमारे सहारे की आवश्यकता थी भी नहीं. जो यह समझते हैं कि हमारे किए उनका सम्मान बढ़ेगा या वे लोग जो सदा से विरोधी रहे, उनका अवमूल्यन कर देंगे, वे सब भ्रम में हैं. गांधी सेवा, त्याग, अहिंसा और समानता, शांति, समता और समन्वय की सामर्थ्य से संपन्न हैं. वे लोग जो उनके गुणों के प्रति नकारात्मक रुख़ रखते हैं, जानते हैं कि वे चाहे जितनी ऊंची प्रतिमाएं गढ़वा लें, पर बापू का कृतित्व उन सब प्रतिमाओं से निरंतर ऊंचा होता जाएगा.

शायद माउंटबेटन हमसे अधिक जानते थे. जिस दिन बापू की हत्या हुई थी, वे उसी दिन मद्रास से लौटे थे. सीधे बिड़ला भवन पहुंचे थे, जहां बापू का शव था. इतनी भीड़ थी कि मुश्किल से अंदर जा सके थे. जब अंदर गए तब उनके चारों तरफ़ भीड़ इकट्ठी हो गई. एक युवक ने गुस्से से कहा, जिसने गांधी की हत्या की वह मुसलमान था. किसी कट्टरवादी का वाक्य रहा होगा. माउंटबेटन का जवाब था, 'मूर्ख, सब कोई जानता है कि जिसने गांधी को मारा वह हिन्दू था.' उनके स्टाफ़ में से किसी ने पूछा, 'सर आप कैसे जानते हैं कि वह हिन्दू था?' माउन्टबेटन का जवाब था, 'ज़रूर वह हिन्दू ही होगा, मुसलमान होता तो सत्यानास हो जाता.' माउन्टबेटन ने बिना सूचना के यह समझ लिया था कि हत्यारा हिन्दू था. यह बात देश के तब की हालत को पूरी तरह रेखांकित करती है.

1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफ़े दे दिए थे. ब्रिटिश सरकार बिना भारतीयों की सहमति के उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में झोंक देना चाहती थी. तब हिन्दू महासभा और लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी. 1942 में हिन्दू महासभा और संघ ने गांधी जी के आह्वान, 'अंग्रेज़ों भारत छोड़ो' का विरोध किया था. दरअसल, हमें उस मानसिकता को समझना होगा, जो गांधी की हत्या के पीछे सक्रिय थी. वही मानसिकता आज भी गांधी के अवमूल्यन और नीतियों के विरोध के पीछे सक्रिय है. आज गांधी की हत्या का महिमामंडन करने वाले, पूंजीवाद और पूंजी के वैश्विकरण के प्रबल समर्थक, इस साज़िश के पीछे हैं. इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. मुझे यह कहने में ज़रा संकोच नहीं कि गांधी की नीतियों का समर्थन कांग्रेस ने भी नहीं किया. अगर किया होता, तो शायद ग़रीब, किसान और अंतिम जन की यह दशा न होती. सुना है गांधी स्मृति से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'अंतिम जन' अर्थाभाव के कारण काफ़ी समय से नहीं निकल रही. संस्कृति मंत्रालय को फाइल देखने की फ़ुर्सत नहीं. अंतिम जन को मारने की यह सरकारी विधि गांधी पर नपुंसक आक्रमण है. दरअसल, गांधी का आत्मावलंबन का मंत्र अब देश के लिए तो मृत हो ही गया. हमारे देश की समस्त गांधी संस्थाएं भी सरकार आश्रित हो गईं. उनकी दुकानें सरकार की कृपा पर चलती हैं. आत्मावलंबन वहां भी नहीं बचा. स्वाभाविक है उनके कारकुनों को संस्थाओं के हित में अपना मुंह बंद रखना पड़ता है. न रखें तो उन संस्थाओं में ताले पड़ जाएं या उनका बाज़ारीकरण अथवा वैश्वीकरण हो जाए. जो गांधी की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के हिमायती थे, अब वे उनके नाम पर चलने वाली संस्थाओं पर निर्भर हैं. यह पर-निर्भरता सरकारों के आने जाने पर निर्भर करती है. जन-भागीदारी न व्यक्तियों में है और न संस्थाओं में. गांधी जी ने जब कोचरब में मकान लेकर पहला आश्रम आरंभ किया था. एक अंत्यज दूधा भाई, अपनी पत्नी दीना बहन और गोद की बेटी लक्ष्मी के साथ, आश्रमवासी के रूप में आ गए थे. गांधी जी ने आत्मकथा में लिखा है, 'इससे सहायक मित्र-मंडली में बड़ी खलबली मची. आर्थिक सहायता बंद हो गई. मगनलाल ने नोटिस दिया कि अगले महीने ख़र्च के लिए रुपए नहीं रहेंगे. गांधी जी ने कहा, हम लोग अछूतों के मोहल्ले में जाकर रहने लगेंगे. नोटिस के कुछ दिन बाद एक रोज़ सुबह किसी बालक ने आकर सूचित किया कि बाहर एक मोटर खड़ी है, एक सेठ आपको बुला रहे हैं. मैं गया, सेठ जी ने पूछा आपको कुछ मदद देना चाहता हूं, आप लेंगे? मैंने कहा, आप देंगे तो ज़रूर लूंगा... मुझे ज़रूरत भी है.' वे अगले दिन आए और गांधी जी के हाथ में 13000 रुपए देकर चले गए.

गांधी जी ने अछूतों के मोहल्ले में जाना स्वीकार किया, पर सरकार आश्रित होना नहीं.... वे चाहते तो सरकार उनको आर्थिक सहायता अवश्य दे देती. सेठ के पूछने पर कि आप मदद स्वीकार करेंगे, उन्होंने कहा, आप देंगे तो ज़रूर स्वीकार करूंगा. उसमें कहीं न कहीं ध्वनि थी- मांगूगा नहीं, हालांकि ज़रूरत है. संस्थाओं का सरकार से आर्थिक सहायता लेना अनुचित नहीं, पर उसके लिए अपना सच कहने की स्वतंत्रता समर्पित कर देना चिंता का विषय बनता जा रहा है. मैं यहां 'द हिन्दू' में 30.1.17 को छपे लेख "Gandhi for our troubled times' से एक उद्धरण प्रस्तुत है- "This is where Gandhi's conception of democracy becomes relevant to us and significant to contemporary democratic theory. Needless to say, Gandhi's approach to politics in terms of 'resistance' and 'protest' beyond conception of domination over others provides antidote to contemporary crisis of democracy. '

यह बात देश की वर्तमान हालात में दिशा निर्देश करती है. बाहर और अंदर सब जगह धीरे-धीरे भय व्याप्त होता जा रहा है. जैसे पहले कभी शहंशाह तख्त से कुछ भी कह सकते थे, वैसी ही स्वतंत्रता आज राजनीति के सर्वोच्च मंच ने कुछ भी कहने के लिए प्राप्त कर ली है, कहने की ही नहीं करने की भी. मुझे एक कथा याद आती है. एक राजा नाटा भी था और अहंकारी भी. उसने घोषणा की, कोई भी वज़ीर या दरबारी लंबाई में राजा से ऊंचा न हो. सबने राजा से कहा कि जो लंबे हैं, छोटा कैसे कर सकते हैं. राजा ने कहा मैं दो दिन का समय दे सकता हूं. दो दिन बाद अपने क़द छोटे करके आएं. यह आप पर निर्भर करता है कि ऊपर से करें या नीचे से. सबने सोचा कि बेहतर हो कि हम ऊपर से कर लें. कम से कम दो बातों से बच जाएंगे, मुंह नहीं होगा तो चुप रहेंगे, राजा को गर्दन कटवाने की ज़हमत नहीं उठानी पड़ेगी. ऐसे में गांधी जी का याद आना ज़रूरी है. यहां मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि गांधी के सत्ता से लड़ने के उपकरण अहिंसा, उपवास और अनशन आदि अपने आप में रेडिकल थे. उन्हीं के कारण संसार का युवा वर्ग उनकी तरफ़ आकर्षित हुआ था. आज भी हैं, परंतु एक कठिनाई हैं. प्रयोग में न आने के कारण वे सब ठूंठे पड़ गए हैं. हम उन्हें समयातीत बताकर अनावश्यक बना रहे हैं. दरअसल, जब तक उन्हें पुनः सक्रिय नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी प्रासंगिकता और समयानुकूलता का पता नहीं चलेगा. उसके लिए मानसिकता भी बनानी पड़ेगी और प्रतिबद्ध भी होना पड़ेगा. साथ ही अपने अभ्यारणों से भी बाहर निकलना पड़ेगा.

पिछले दिनों, देखने में छोटी पर गंभीर घाव करने वाली घटना घटी. शासन का गांधी के गांधीपन पर आक्रमण था, यह देखने के लिए लोग किस तरह उसे लेते हैं. के वी आई सी द्वारा अपने कलेंडर पर चर्ख़ा कातते गांधी की तस्वीर की जगह प्रधानमंत्री की फ़ोटो (शूट करके) लगा दी गई थी. खादी ग्रामउद्योग के कर्मचारी आहत हुए थे. देश में भी शोर मचा था. लखनऊ में हैदराबाद, राजस्थान आदि से आए विचारक और चिंतकों ने विरोध में सभा की थी. मैंने कई गांधी संबंधी संस्थाओं के नायकों से संपर्क किया था, यह जानने के लिए कि क्या कुछ समान सोच वाले लोग 30 जनवरी को सामूहिक उपवास रख सकते हैं. शायद मुझे नहीं करना चाहिए था. केवल जस्टिस धर्माकारी जी ने इस विषय पर लिखा मेरा लेख लगभग पचास लोगों को मेल किया था. वह लेख 30 जनवरी को 'चौथी दुनिया' में भी छपा है. समाचार पत्रों ने सरकार की राय से भिन्नता रखने वाले आलेख छापना लगभग बंद कर दिया है. कलेंडर पर से गांधी जी का चित्र हटाकर मोदी जी के छापने के पीछे जो तर्क दिया गया है, वह विचारणीय है. उन्होंने पांच सौ चर्खे बांटे थे तथा उन्हीं की वजह से खादी की बिक्री बढ़ी है. बिक्री बढ़ाना और पांच सौ चर्खे बांटना मोदी जी को गांधी जी के समकक्ष ही खड़ा नहीं करता, हरियाणा के एक मंत्री के अनुसार, उनका स्टेटस गांधी जी से बड़ा हो गया. सत्ता ही शायद किसी को छोटा और बड़ा बनाने की क्षमता रखती है, काम नहीं.

गांधी जी ने कितने चर्ख़े बांटे इसका हिसाब मेरे पास नहीं है. लेकिन कुछ तथ्य हैं, मैं यह भी नहीं कह सकता कि वे तथ्य गांधी जी के स्टेटस को दूसरों की नज़र मे बदल पाएंगे या नहीं. गांधी जी ने चर्ख़ों का नाम ही सुना था. बिना देखे ही उन्हें लगने लगा था, अगर चर्ख़े का पता चल जाए, तो महिलाओं और निम्न आर्थिक समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर की जा सकती है. गंगा बहिन नाम की एक महिला की मदद से बड़ौदा के पास किसी गांव से चर्खा खोज निकाला. उसमें मगन भाई की सहायता से परिवर्तन किए और सौ वर्ष पहले 1917 में चर्ख़ा अवतरित हो गया. वास्तव में 2017 चर्ख़े की शताब्दी के साथ खादी की भी शताब्दी है. खादी के माध्यम से स्वालंबन शताब्दी है, जिसे गांधी का चित्र हटाकर मोदी जी का चित्र लगाकर खादी ग्राम उद्योग मुंबई में मना गई है. यहां यह बता देने में कोई धृष्टता नहीं होगी, अगर कहूं कि खादी आंदोलन की मज़बूती के बाद ही उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाने का आह्वान किया था.

खादी का भाग्य भी विचित्र था. लार्ड विलिंग्डन वायसराय थे. उन्होंने गांधी जी को लंदन में होने वाली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के सिलिसले में शिमला बुलाया था. कस्तूरबा भी उनके साथ गईं. अगले दिन वायसरायिन ने बा की अगवानी की. बा का भी पहला मौक़ा था, वायसरायिन से मिलने का और उसका भी पहला मौक़ा था किसी भारतीय नेता की पत्नी को आमंत्रित करने का. वायसरायिन ने कस्तूरबा से कहा 'क्या आप हथबनी खादी, जिसे मि. गांधी ने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रचारित किया है, मुझे उपलब्ध करा सकती हैं?' बा ने कहा, 'मुझे बहुत ख़ुशी होगी, पर आप क्या करेंगी?' वायसरायिन ने कहा, 'उसके माध्यम से मैं भारतीय जनता के निकट आना चाहती हूं. क्या बैंजनी खादी भेज सकती हैं?' बा ने जवाब दिया, 'मैं आपके लिए बहुत सारी खादी भेज दूंगी. पर एक सवाल है, आप खादी के माध्यम से जनता के निकट कैसे जा पाएंगी? बेहतर हो अगर इन पहाड़ियों से उतर कर मैदान में आएं, जहां लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, तो आप उन्हें बेहतर जान सकती हैं.' कस्तूरबा को जनता, खादी और गोरों के बीच का अंतर मालूम था. यह भी पता चलता है कि खादी की यात्रा कहां से कहां पहुंची थी और आज कहां है.■ *(शेष अगले अंक में जारी है...)*

खादी का भाग्य भी विचित्र था. लार्ड विलिंग्डन वायसराय थे. उन्होंने गांधी जी को लंदन में होने वाली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के सिलिसले में शिमला बुलाया था. कस्तूरबा भी उनके साथ गईं. अगले दिन वायसरायिन ने बा की अगवानी की. बा का भी पहला मौक़ा था, वायसरायिन से मिलने का और उसका भी पहला मौक़ा था किसी भारतीय नेता की पत्नी को आमंत्रित करने का. वायसरायिन ने कस्तूरबा से कहा 'क्या आप हथबनी खादी, जिसे मि. गांधी ने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रचारित किया है, मुझे उपलब्ध करा सकती हैं?' बा ने कहा, 'मुझे बहुत ख़ुशी होगी, पर आप क्या करेंगी?' वायसरायिन ने कहा, 'उसके माध्यम से मैं भारतीय जनता के निकट आना चाहती हूं. क्या बैंजनी खादी भेज सकती हैं?' बा ने जवाब दिया, 'मैं आपके लिए बहुत सारी खादी भेज दूंगी. पर एक सवाल है, आप खादी के माध्यम से जनता के निकट कैसे जा पाएंगी?'

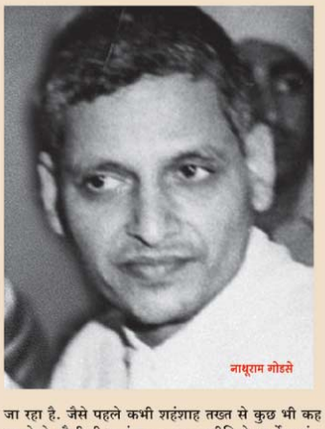

नाथूराम गोडसे

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

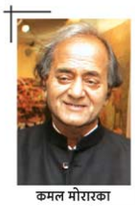

कमल मोरारका

योगी की परीक्षा अभी बाकी है

योगी की दूसरी परीक्षा होगी, जिसके बारे में मैं अभी कह सकता हूं कि वे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. जैसे, रोजगार सृजन करना. उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रोजगार सृजन का काम लगभग असंभव होगा. वे अगर बेरोज़गारी का जिलावार डाटा तैयार करवा लेते हैं, तो यह एक बेहतर काम होगा. इस डाटा में वे पाएंगे कि पूर्वी यूपी की हालत पश्चिमी और मध्य यूपी के मुकाबले ज्यादा खराब है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोज़गार देने के लिए कौन सी विशेष नीति अपनाई जाती है, यह देखना बाक़ी है. प्रधानमंत्री हर तरह के फैंसी स्कीमों में विश्वास रखते हैं. नौकरी मांगो नहीं, नौकरी पैदा करो, उनका ये कथन, कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल. दरअसल, यहां कृषि क्षेत्र को संकट से निपटना है. कृषि क्षेत्र की हालत ठीक नहीं है. यह कहना बहुत आसान है कि छह साल में हम किसानों की आमदनी को दोगुनी कर देंगे, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पांच साल में पैदावार दोगुनी नहीं हो सकती, समर्थन मूल्य उस स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है.

यूपी चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर से पांच बार के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुना. ये कहा गया कि विधायकों ने योगी को चुना, ये कहने की बात है. नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संकेत दिया था कि वे योगी को सीएम के तौर पर चाहते हैं. दूसरी तरफ, कुछ लोग यह भी कहते नजर आए कि सरकार चलाने के लिए भगवा वस्त्रधारी योगी का चयन सही नहीं है. लेकिन याद रखना चाहिए कि आरएसएस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पीछे रही है और इसकी नीतियों को मध्य युग में ले जाने के लिए डट के भाजपा के पीछे खड़ी रही है.

हालांकि कुछ बिन्दुओं को नोट करना चाहिए. पहला बिन्दु ये है कि महंत अवैद्यनाथ गोरखपुर मठ के मुखिया थे, वे कभी आरएसएस या भाजपा से नहीं जुड़े थे. वे अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे. भाजपा ने उन्हें टिकट की पेशकश की. वे चुनाव लड़े और सांसद बने. उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया. योगी आदित्यनाथ 5 बार से सांसद हैं. वे मुझे नहीं मालूम कि वे भाजपा के सदस्य हैं या नहीं हैं, लेकिन वे भाजपा के टिकट पर भाजपा सांसद हैं, इसलिए भाजपा से जुड़े हैं. जो थोड़ी बहुत जानकारी है या जितनी जानकारी मैं इकट्ठा कर पाया हूं, उसके मुताबिक यदि आरएसएस को मुख्यमंत्री चुनना होता, तो योगी आदित्यनाथ उसकी पसन्द नहीं होते. बहुमत हासिल करने के बाद आरएसएस किसी हार्डलाइनर को पसन्द करता, जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की तरह या उनके जैसे व्यक्ति की तरह, जो आरएसएस की लाइन पर काम कर सके. योगी के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं. वे यह भी दावा करते हैं कि गोरखपुर मठ में बहुत सारे मुस्लिम उनके साथ काम करते हैं और अपने इस संसदीय क्षेत्र में वे सभी समुदायों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि उनका सीएम चुना जाना सही है या नहीं. उनके काम को यदि एक साल नहीं, तो कम से कम 6 महीने तक देखना चाहिए. उन्होंने अपनी शुरुआत भयप्रद तरीके से बूचड़खाने बंद करवाने से की. उनके मंत्री स्पष्ट करते हैं कि केवल अवैध बूचड़खाने ही बंद किए जाएंगे, वैध बूचड़खाने चलते रहेंगे. अगर यह सही है, तो इस पर कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं कर सकता. इसके अलावा उन्होंने कुछ लोक-लुभावन कदम उठाए हैं, जैसे सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखा बैन करना और मंत्रियों की गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगवाना. इससे पहले अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली में इस तरह की घोषणा की थी. अभी अमरिंदर सिंह ने पंजाब में भी ऐसी ही घोषणा की. ये सब भी छोटे लोक-लुभावन कदम हैं. दो ऐसे असल मुद्दे हैं, जिनके आधार पर योगी का आकलन हो सकता है. पहला है, कानून-व्यवस्था. अखिलेश यादव के शासनकाल में आधे से अधिक पुलिस स्टेशन में यादव एसएचओ थे. ये सब आम लोगों के बीच कोई बहुत अच्छी तस्वीर पेश नहीं करते हैं. इससे विश्वास का माहौल नहीं बनता. जाहिर है, अगर किसी यादव एसएचओ के मन में यादव के लिए सॉफ्टवेयर कॉर्नर हो, तो वह किसी अन्य जाति को गंभीरता से नहीं लेगा. अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना में योगी क्या करते हैं, उसको ध्यान से देखा जाना चाहिए. प्रतिभा के आधार पर अगर आप ईमानदारी से अधिकारियों का चयन करते हैं, तो यह एक बेहतर शुरुआत होगी. आखिरकार, सब जानते हैं कि कानून-व्यवस्था का काम जितना हिंसक समूह से जुड़ा होता है, उतना ही पुलिस अधिकारियों के प्रभावी कार्य प्रणाली से जुड़ा होता है. पुलिस का मुख्य काम है कि गुंडागर्दी न हो. यह योगी की पहली परीक्षा होगी.

योगी की दूसरी परीक्षा होगी, जिसके बारे में मैं अभी कह सकता हूं कि वे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. जैसे, रोजगार सृजन करना. उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रोजगार सृजन का काम लगभग असंभव होगा. वे अगर बेरोज़गारी का जिलावार डाटा तैयार करवा लेते हैं, तो यह एक बेहतर काम होगा. इस डाटा में वे पाएंगे कि पूर्वी यूपी की हालत पश्चिमी और मध्य यूपी के मुकाबले ज्यादा खराब है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोज़गार देने के लिए कौन सी विशेष नीति अपनाई जाती है, यह देखना बाक़ी है. प्रधानमंत्री हर तरह के फैंसी स्कीमों में विश्वास रखते हैं. नौकरी मांगो नहीं, नौकरी पैदा करो, उनका ये कथन, कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल. दरअसल, यहां कृषि क्षेत्र को संकट से निपटना है. कृषि क्षेत्र की हालत ठीक नहीं है. यह कहना बहुत आसान है कि छह साल में हम किसानों की आमदनी को दोगुनी कर देंगे, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पांच साल में पैदावार दोगुनी नहीं हो सकती, समर्थन मूल्य उस स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है. कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए सरकार को इनोवेटिव स्कीम के बारे में सोचना चाहिए. बेशक कृषि राज्य का विषय है, मोदी भले ही कुछ भी कहें, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है. यहां लोग ज़मीन के ऊपर आश्रित हैं, गंगा यहां से गुज़रती है, यहां की ज़मीन उपजाऊ है. यहां बहुत कुछ किया जा सकता है, यदि वे कृषि क्षेत्र के लिए काम करना चाहें. ऐसा करने से बेरोज़गारी का दबाव कम होगा.

तीसरी चीज़ जो दिमाग में आती है, वो है बिजली. उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है. यदि यही एक वादा वो पूरा कर देते हैं, तो उन्हें इतिहास में याद किया जायगा, क्योंकि उर्जा के बिना कुछ भी संभव नहीं है. चाहे कृषि हो, उद्योग हो, घरेलू ज़रुरत हो, हम बिजली पर बहुत अधिक निर्भर हैं. उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति बहुत खस्ता है. मुझे लगता है कि योगी पर कोई राय कायम करने के लिए हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए. यदि वे कुछ बहुत ही गलत काम करते हैं और समुदायों के बीच नफ़रत पैदा कर

मैं समझ सकता हूं कि आरएसएस अपनी आस्था के मुताबिक वहां मंदिर बनाना चाहता है. लेकिन यह ऐसा मसला नहीं है, जिस पर न्यायालय से निर्णय लिया जाए. इस पर फैसला देने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट अच्छा करेगी यदि वो हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दे. लेकिन मैं समझ सकता हूं कि मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट से बाहर न्यायोचित समाधान निकालने के लिए कहा है. मैं अपने पाठकों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा कोर्ट से बाहर यह मामला सुलझा लिया गया था. जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों एक फॉर्मूले पर राज़ी हो गए थे. जब समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला था, उसी समय राजीव गांधी ने उनकी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था. चंद्रशेखर जी ने उन्हें फ़ोन कर के कहा कि आप दो तीन दिन तक रुक जाइए, मैं इस मसले को निपटाने वाला हूं. लेकिन राजीव गांधी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई. उन्होंने ऐसा क्यों किया, अब वे नहीं बता सकते, क्योंकि वे इस दुनिया में नहीं हैं.

यदि वो हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दे. लेकिन मैं समझ सकता हूं कि मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट से बाहर न्यायोचित समाधान निकालने के लिए कहा है. मैं अपने पाठकों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा कोर्ट से बाहर यह मामला सुलझा लिया गया था. जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों एक फॉर्मूले पर राज़ी हो गए थे. जब समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला था, उसी समय राजीव गांधी ने उनकी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था. चंद्रशेखर जी ने उन्हें फ़ोन कर के कहा कि आप दो तीन दिन तक रुक जाइए, मैं इस मसले को निपटाने वाला हूं. लेकिन राजीव गांधी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई. उन्होंने ऐसा क्यों किया, अब वे नहीं बता सकते, क्योंकि वे इस दुनिया में नहीं हैं. हां शरद पवार अभी जिंदा हैं, वे शायद इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें. तो अब वो फॉर्मूला क्यों लागू नहीं हो सकता?

उसके बाद आरएसएस और संघ परिवार से निष्ठा रखने वाले गुंडा तत्वों ने 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया. जिसने मुसलमानों को चोट पहुंचाया. रिकॉर्ड बताएंगे कि उसके बाद मुसलमानों में मिलिटेंसी आई थी, नाराज़गी बढ़ी थी. दाऊद इब्राहीम, जो उस वक़्त तक एक आर्थिक अपराधी था, उस दंगों के बाद एक क्रिमिनल बन गया. लिहाज़ा, अगर इस मसले पर वाकई कोई सार्थक प्रक्रिया शुरू करनी है, तो हिन्दुओं को मुसलमानों के साथ बैठना चाहिए और बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए हिन्दुओं को बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए. हां हम वहां मंदिर बनाना चाहते हैं, हम वो जगह चाहते हैं, हम जायज तौर पर यह महसूस कर सकते हैं कि वो जगह हमारी है, लेकिन किसी ईमारत को गिरा देना असंवैधानिक है. एक बार जब आप माफ़ी मांग लेंगे और मुसलमान सहमत हो जाएंगे, क्योंकि जिस मस्जिद में नमाज़ नहीं होती है, वो मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती. उस लिहाज़ से देखा जाए तो बाबरी मस्जिद में बहुत पहले से नमाज नहीं हो रही थी. इसीलिए वे चंद्रशेखर से सहमत हो गए थे कि मस्जिद को दूसरी जगह हटा दी जाए और ज़मीन दे दी जाए. लेकिन उसके साथ उनकी शर्त थी कि आज के बाद काशी, मथुरा और दूसरी जगहों पर मामले दुबारा नहीं खुलने चाहिए. एक कानून पास होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो मंदिर है, वो मंदिर रहेगा और जो मस्जिद है, वो मस्जिद रहेगी. मैं समझता हूं कि सरकार के रिकॉर्ड में वो समझौता होगा. पीएमओ या गृह मंत्रालय में वो कागजात होंगे. यदि वे इस मसले पर वाकई गंभीर हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत करते हुए समझदार लोगों को हिन्दुओं और मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए और इस झगड़े को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए. देखते हैं क्या होता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ताक़तवर मोदी और उनकी चुनौतियां

शुजात बुख़ारी

पांच राज्यों के चुनाव के नतीजों में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों में, कई चौंकाने वाले तथ्य रहे. इन नतीजों के बाद के जोश और उल्लास ने दो और राज्यों मणिपुर और गोवा, जहां भाजपा को बहुमत नहीं थी, को भी उसकी झोली में डाल दिया. हालांकि एग्जिट पोल्स ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए बहुमत की भविष्यवाणी तो की थी, लेकिन इतनी प्रचंड बहुमत की भविष्यवाणी नहीं की थी. भाजपा ने राज्य में खुद को पुनःस्थापित करने में जुटी कांग्रेस के साथ-साथ सपा और बसपा जैसी मज़बूत पार्टियों को भी धराशाई कर दिया.

इसमें कोई शक नहीं कि 2014 के लोकसभा चुनाव की ज़बरदस्त कामयाबी को दुहरा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं. मोदी के प्रबंधक और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी पार्टी की शानदार जीत के लिए श्रेय दिया गया है. अब जबकि एक लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा की झोली में आ गया है, यह 2019 के आम चुनावों की दिशा भी निर्धारित करेगा, जो मोदी और उनकी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

दरअसल, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया गया. मोदी की बहुचर्चित कब्रिस्तान और श्मशान की टिप्पणी ने संतुलन का झुकाव उनकी तरफ करने में काफी योगदान दिया, लेकिन जिस तरह से परिणाम सामने आए, उनसे यह भी ज़ाहिर होता है कि शायद धर्म का कार्ड आने से पहले ही ज्यादातर वोट बैंक का काफी हद तक हृदय परिवर्तन हो चुका था. (गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की रैली में उन्होंने कहा था कि गांव में कब्रिस्तान बनता है, तो श्मशान भी बनना चाहिए. यानि यदि मुसलमानों के लिए एक कब्रिस्तान बनाया गया है, तो हिंदुओं के लिए श्मशान बनना चाहिए). 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले 42 प्रतिशत वोटों ने भाजपा को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता साफ़ किया था.

इस बार भाजपा को एक अतिरिक्त फायदा यह था कि उत्तर प्रदेश चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अलग-अलग जातियों ने समान रूप से पार्टी के लिए वोट किया. जातिगत रूप से देखा जाए, तो 41 प्रतिशत अनुसूचित जातियों ने, 42 प्रतिशत ओबीसी ने, 44 प्रतिशत सामान्य श्रेणी ने, 45 प्रतिशत जाटों ने और 38 प्रतिशत यादवों ने भाजपा को वोट दिया. यदि मुस्लिमों के मतदान के विश्लेषण को अक्षरशः स्वीकार कर लिया जाए, तो

कश्मीर को कैसे निपटाना है, यह मोदी के लिए एक परीक्षा है. हालांकि अभी तक उन्होंने अपनी पार्टी की पहलक़दमी की प्रतिबद्धता को नकार दिया है, जो पीडीपी के साथ उसके अलायन्स के एजेंडे में शामिल था. उन्हें केवल अपनी प्रतिबद्धता पूरी करनी है, कोई नई पहल नहीं करनी है. उन्हें करना यह चाहिए कि वे सामान्य नौकरशाही दृष्टिकोण, जो कश्मीर को केवल कानून और व्यवस्था के चश्मे देखता है, को छोड़ दें. कश्मीर तक पहुंचने और कुछ ठोस कदमों की नींव रखने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे राजनीतिक रूप से देखा जाए. अब तक कोई अन्य विकल्प कारगर नहीं साबित हुआ है.

चुनाव नतीजों का अनुमान चुनाव से बहुत पहले लगाया जा सकता था.

कुल मिला कर यह लोकतंत्र की जीत है और इसका जश्न मनाया जा रहा है. लेकिन पिछले दो सालों में बीजेपी ने जिस तरह से सत्ता का संचालन किया है, उससे यह ज़ाहिर होता है कि शायद अत्यधिक शक्तिशाली सरकार भारत के लिए ठीक नहीं है. भारत अपनी विविधता पर गर्व करता रहा है. अल्पसंख्यक यहां की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं और भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं का जो व्यवहार रहा है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यकों के लिए एक सुविधाजनक जीवन वापस का दायरा और सिकुड़ जाएगा. चुनावों से पहले ही भाजपा ने यह ज़ाहिर कर दिया था कि उसे मुसलमानों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारा था. लगभग 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुलसमानों का प्रतिनिधित्व इतना कम कभी नहीं था. पिछले विधानसभा में 71 मुस्लिम सदस्यों की तुलना में इस बार केवल 24 सदस्य चुने गए हैं. 24 मुस्लिम विधायकों में से 15 एसपी के टिकट पर, 7 बसपा के टिकट पर और 2 कांग्रेस के टिकट पर चुने गए हैं.

अब जबकि मोदी एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, तो उनके सामने देश चलाने की एक बड़ी चुनौती है. इस तरह की भविष्यवाणियां कि विमुद्रीकरण जैसे नीतिगत फैसले उन्हें ले डूबेंगे, गलत साबित हुई हैं. दरअसल, विमुद्रीकरण ने गरीबों को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए मोदी को यूपी में चुनाव में नुकसान होना चाहिए था, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट.

उसी तरह कई अन्य फैसले उनके लिए 'सकारात्मक' साबित हो रहे हैं. हालांकि लंबे समय के बाद उन्हें उसका नकारात्मक पक्ष भी दिखाई दे सकता है. वामपंथियों के दृश्य से गायब होने के साथ-साथ मोदी इफेक्ट ने कांग्रेस को इतना कमज़ोर कर दिया है कि वे दूसरे राज्यों में अपनी जीत का जश्न नहीं मना सकते. यह हकीकत है कि उत्तर प्रदेश से 80 सांसद चुने जाते हैं. वे सांसद दिल्ली की सत्ता हासिल करने का ख्वाब देखने वाले किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत का फैसला करते हैं. कांग्रेस नेतृत्व की अंतर्निहित कमजोरी ने भी मोदी के लिए रास्ता आसान कर दिया. साथ ही साथ ये परिणाम ज़ाहिर करते हैं कि वंशवादी राजनीति अपनी धार खो रही है.

मोदी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमे सबसे महत्व-पूर्ण चुनौती होगी, अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा की भावना बहाल करना. आर्थिक विकास सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना उनकी दूसरी अहम चुनौतियां हैं. गरीबों को मोदी से अधिक अपेक्षाएं हैं, क्योंकि स्वयं उनकी साधारण पृष्ठभूमि की वजह से गरीब खुद को उनके साथ जोड़ लेते हैं. बहरहाल, उनके सामने एक सबसे बड़ा मुद्दा यह भी होगा कि वे कश्मीर समस्या और पाकिस्तान से कैसे निपटते हैं. मोदी ने 25 दिसंबर, 2015 को गैर निर्धारित रूप से लाहौर जाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन विभिन्न कारणों से उस प्रक्रिया में एकरूपता बरक़रार नहीं रह सकी. उन्होंने यह स्टैंड लिया कि 'आतंक और वार्ताएं एक साथ नहीं चल सकतीं' और यही चीज़ उनकी पार्टी भी चाहती थी. शायद पाकिस्तान विरोधी नीति ने यूपी चुनावों में भाजपा को फायदा पहुंचाया, लेकिन यदि मोदी कश्मीर को लेकर कुछ करने के बारे में गंभीर हैं, तो पाकिस्तान से बातचीत करना अपरिहार्य है. वे इतने ताक़तवर हैं कि न तो उनकी पार्टी के अन्दर और न ही बाहर कोई उनके रोडमैप पर सवाल खड़े कर सकता है. पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं, हालांकि उसमें से अभी तक कुछ ठोस उभर कर सामने नहीं आया है. केवल मोदी ही हैं, जो दोनों देशों के संबंधों को बदल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण में कुछ बदलाव किए हैं.

कश्मीर को कैसे निपटाना है, यह मोदी के लिए एक परीक्षा है. हालांकि अभी तक उन्होंने अपनी पार्टी की पहलक़दमी की प्रतिबद्धता को नकार दिया है, जो पीडीपी के साथ उसके अलायन्स के एजेंडे में शामिल था. उन्हें केवल अपनी प्रतिबद्धता पूरी करनी है, कोई नई पहल नहीं करनी है. उन्हें करना यह चाहिए कि वे सामान्य नौकरशाही दृष्टिकोण, जो कश्मीर को केवल कानून और व्यवस्था के चश्मे देखता है, को छोड़ दें. कश्मीर तक पहुंचने और कुछ ठोस कदमों की नींव रखने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे राजनीतिक रूप से देखा जाए. अब तक कोई अन्य विकल्प कारगर नहीं साबित हुआ है. चाहे वो सैन्य विकल्प हो या वित्तीय विकल्प. आने वाले महीनों में उनकी ताकत की परीक्षा होगी और यदि वे बदलाव लाने में सफल हो जाते हैं, तो वे और अधिक मजबूत हो जाएंगे. यदि ऐसा नहीं होता, तो भले ही वे शक्तिशाली रहें, लेकिन अपने देश को कमज़ोर करेंगे. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.
feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

लोगों की आशाओं को पूरा करना योगी आदित्यनाथ की ज़िम्मेदारी है

योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना बहुतों को पसंद नहीं आया. लोग यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उस कारनामे को दोहराना चाहती है, जो उसने 2014 में 73 सांसदों के रूप में किया था. भारतीय जनता पार्टी के इस विश्वास को इस बात से और बल मिला, जब 2017 में विधानसभा चुनावों में उसे 325 सीटें मिल गईं. भारतीय जनता पार्टी को अवश्य इस बात का विश्वास होगा कि वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर न केवल इस करिश्मे को दोहराएगी, बल्कि और ज्यादा सांसदों को, भले ही वो दो ज्यादा हों, उत्तर प्रदेश से संसद में लेकर आएगी, ताकि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी का पुन: प्रधानमंत्री बनना निश्चित हो सके.

यह भारतीय जनता पार्टी का सोचना हो सकता है और उसका सपना भी हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों का सपना दूसरा है. उत्तर प्रदेश के लोग बार-बार कभी सपा तो कभी बसपा की सरकारों में अपने आस-पास हुए परिवर्तन को देख चुके हैं. उन्हें अब इस बात की अपेक्षा है कि सरकार उनके जीवन को बदलने वाले काम शुरू करे. योगी के आने से उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा वर्ग ये सोच रहा है कि योगी अपनी समझदारी से उन सारी योजनाओं को जल्दी से-जल्दी लागू करेंगे, जो योजनाएं तो थीं, लेकिन धरती पर उतर नहीं रही थीं. हर वर्ग के लोगों में योगी को लेकर आशाएं जगी हैं. अब इन आशाओं को पूरा करना सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर है.

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर हो गई थी. अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार यह कहते रहे कि घटनाएं दूसरे प्रदेशों में ज्यादा होती हैं. वे विभिन्न अपराध के आंकड़े इकट्ठे करने वाली एजेंसियों का हवाला भी देते रहे और यह कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम होते हैं, प्रचार ज्यादा होता है. अब सवाल है कि आप मुख्यमंत्री थे. अगर अपराधों का प्रचार होता है तो आपने उसका मुक़ाबला करने के लिए क्या किया? ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव के पक्ष में मीडिया ने प्रचार नहीं किया या अखिलेश यादव के साथ के लोग इस तथ्य से परिचित नहीं थे. दूसरी तरफ़ उत्तर प्रदेश के साधारण लोग पुलिस थानों से परेशान थे. लोगों ने यह मान लिया था कि यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी इसलिए शिकायत करने का क्या फायदा? मायावती जी के ज़माने में अपराधों के ऊपर नियंत्रण लगा था. कानून व्यवस्था भी सुधरी थी, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है. यह पहला कदम होता है. मायावती ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए विकास के बुनियादी कार्यों को प्राथमिकता में नहीं रखा. शायद इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का वोट देने का निर्णय लेने में कई सारे तथ्यों के साथ यह तथ्य भी प्रमुख रहा. योगी आदित्यनाथ के सिर पर पहली बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को सुधारने की है. अक्सर यह देखा गया है कि अगर मुख्यमंत्री कड़ा हो या कभी-कभी मंत्री कड़ा हो तो चीज़ें सुधरती हैं क्योंकि व्यवस्था का संचालन शिखर से होता है. योगी आदित्यनाथ ने पिछले 15 वर्षों में ऐसी बहुत सी शिकायतें सुनी हैं. लोगों से मिले हैं, लोगों का दर्द जाना है. अब योगी आदित्यनाथ उनका निवारण नहीं कर सकते, जबकि पूरी सत्ता उनके हाथ में है, फैसले उनके हाथ में हैं और उनके मंत्रिमंडल में कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो इस शक्ति का दूसरा केन्द्र बन सके या उन्हें रोक सके. तब भी अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छी कानून व्यवस्था और विकास के बुनियादी काम नहीं मिलते हैं तो यह जितना भारतीय जनता पार्टी या योगी का दुर्भाग्य होगा, उतना ही उत्तर प्रदेश की जनता का भी दुर्भाग्य होगा.

उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें लोगों ने प्रयोग किए हैं. उत्तर प्रदेश में अब प्रयोगों की गुंजाइश कम और धरती पर काम करने की गुंजाइश ज्यादा है. बिजली, जिसमें सोलर सबसे प्रमुख है, पानी जो समाप्त होता जा रहा है और पीने का पानी खतरनाक स्तर से भी ऊपर पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांव पानी के लिए तरस रहे हैं. यह समस्या सरकारों और लोगों द्वारा भी खुद बनाई गई है. उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में पीने का पानी अवश्य होना चाहिए, चाहे इसके लिए पुरानी बावड़ी, वाटर हार्वेस्टिंग या फिर पानी इकट्ठा करने की तकनीक हो, इसे गांव-गांव में अपनाया जाना ज़रूरी है. अगर योगी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके. सिंचाई के पानी की भी कमी है. देखना है कि योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में कानून व्यवस्था के बाद पीने का पानी आता है या नहीं. योगी आदित्यनाथ को यह कोई नहीं बताएगा कि उत्तर प्रदेश के सारे ब्लॉक के केन्द्र में अगर वो वहां उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर उद्योग स्थापित करा देते हैं, तो वो कितने ज्यादा रोज़गार खड़े कर देंगे. इसमें सरकार को पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर सरकार बिना लालफीताशाही और भ्रष्टाचार के सिर्फ लोगों को लाइसेंस दे दे, तब उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में, हर विकास खंड में, वहां कच्चे माल पर आधारित उद्योग लग सकते हैं. अब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो रही है कि जहां कच्चा माल है, अगर वहीं वो परिष्कृत या प्रोसेस होता है तो उसके खरीदार वहीं पहुंच जाते हैं. उत्तर प्रदेश में स्थानीय कच्चे माल पर आधारित छोटे उद्योगों की श्रृंखला लगाना योगी आदित्यनाथ की तीसरी प्राथमिकता हो सकती है.

उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें लोगों ने प्रयोग किए हैं. उत्तर प्रदेश में अब प्रयोगों की गुंजाइश कम और धरती पर काम करने की गुंजाइश ज्यादा है. बिजली, जिसमें सोलर सबसे प्रमुख है, पानी जो समाप्त होता जा रहा है और पीने का पानी खतरनाक स्तर से भी ऊपर पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांव पानी के लिए तरस रहे हैं. यह समस्या सरकारों और लोगों द्वारा भी खुद बनाई गई है. उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में पीने का पानी अवश्य होना चाहिए, चाहे इसके लिए पुरानी बावड़ी, वाटर हार्वेस्टिंग या फिर पानी इकट्ठा करने की तकनीक हो, इसे गांव-गांव में अपनाया जाना ज़रूरी है. अगर योगी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके. सिंचाई के पानी की भी कमी है. देखना है कि योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में कानून व्यवस्था के बाद पीने का पानी आता है या नहीं. योगी आदित्यनाथ को यह कोई नहीं बताएगा कि उत्तर प्रदेश के सारे ब्लॉक के केन्द्र में अगर वो वहां उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर उद्योग स्थापित करा देते हैं, तो वो कितने ज्यादा रोज़गार खड़े कर देंगे. इसमें सरकार को पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है.

योगी आदित्यनाथ की चौथी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की होनी चाहिए. अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरता है, तो यह योगी आदित्यनाथ का उस उत्तर प्रदेश को उनका ऋण चुकाने जैसा होगा, जिसने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक अपार बहुमत दिया है.

योगी आदित्यनाथ अगर अपने मंत्रियों द्वारा किए गए कामों का नियमित विश्लेषण करते रहेंगे, तो उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अवश्य कुछ करती दिखाई देगी. लेकिन अगर उन्होंने अपने मंत्रियों को ढीला छोड़ दिया या सिर्फ वैचारिक भाषणबाज़ी के लिए छोड़ दिया, तब शोर तो मचेगा, लेकिन विकास नहीं होगा. अगर विकास नहीं होगा तब उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सब कुछ बेकार हो जाएगा. योगी आदित्यनाथ से आशाएं हैं, वो आशाएं योगी आदित्यनाथ पूरी करें, अभी तो यह विश्वास करना चाहिए. ■

editor@chauthiduniya.com

आर या पार

हवा में ज़हर

इस बात से क्यों इनकार किया जा रहा है कि वायु प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल लाखों लोग और ख़ास तौर पर ग़रीब मर रहे हैं?

कल्पना शर्मा

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे इंकार की मुद्रा में हैं. वे इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि वायु प्रदूषण भारत में एक गंभीर समस्या बन गई है, इसके साथ ही वे यह भी नहीं चाहते कि यह बात देश के बाहर कोई कहे. बोस्टन की हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, 2017 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है. इसमें बताया गया है कि वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत चीन से बहुत पीछे नहीं है. इस पर दवे ने कहा कि हम भारतीय लोग बाहर की चीजों से बहुत प्रभावित होते हैं. उन्होंने कहा कि हमें अपने विशेषज्ञों पर भरोसा करना चाहिए, उसी तरह जिस तरह हम अपनी सेना पर भरोसा करते हैं. पर्यावरण मंत्री द्वारा की गई यह तुलना हैरान करने वाली है. वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों की जो संख्या इस रिपोर्ट में दी गई है, उसे लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है कि वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गई है. इससे काफी लोगों को जान गंवानी पड़ रही है.

वायु प्रदूषण पर सरकारी आंकड़ों और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज यानी जीबीडी रिपोर्ट के आधार पर इसे तैयार किया गया है. जीबीडी में 1990 से 2015 तक 195 देशों के विस्तृत आंकड़े हैं. इसके आधार पर वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के आंकड़े निकाले जाते हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 में पूरी दुनिया में 42 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई है. इनमें से 52 फीसदी मौतें भारत और चीन में हुईं. हालांकि, चीन ने इस दिशा में जो कदम उठाए हैं उसकी वजह से इन मौतों की संख्या स्थिर हो गई है.

> दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़े इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि यहां इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा मौजूद है. जबकि वाराणसी में सिर्फ तीन जगहों पर प्रदूषण मापा जाता है. इनमें से भी सिर्फ एक जगह ही पीएम 2.5 का स्तर मापा जाता है. जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी देने वाला कोई उपकरण वाराणसी में नहीं है. दिल्ली में 13 जगहों पर पीएम 2.5, पीएम 10 और एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूचना देने वाले उपकरण लगे हैं. अगर हम अपने शहरों में वायु प्रदूषण का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसकी वजह से सेहत पर पड़ने वाले कुप्रभावों का अंदाज हम कैसे लगा पाएंगे.

जबकि भारत में अभी यह संख्या लगातार बढ़ रही है.

इसका वजह कोई रहस्य नहीं है. भारत में सरकारों ने वायु प्रदूषण को कभी गंभीरता से ही नहीं लिया. वायु प्रदूषण कम करने की कोशिशें भी दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही केंद्रित रही. हमने छोटे शहरों को नजरंदाज किया है. 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की है, जिनमें से 10 भारत के हैं. भारत में सबसे बुरी स्थिति इलाहाबाद, कानपुर, फिरोजाबाद और लखनउ की है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में वाराणसी को सबसे अधिक प्रदूषित तीन शहरों में रखा है. दवे को कम से कम यह रिपोर्ट माननी चाहिए क्योंकि इसे हमारे अपने वैज्ञानिकों ने ही जारी किया है.

दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़े इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि यहां इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा मौजूद है. जबकि वाराणसी में सिर्फ तीन जगहों पर प्रदूषण मापा जाता है. इनमें से भी सिर्फ एक जगह ही पीएम 2.5 का स्तर मापा जाता है. जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी देने वाला कोई उपकरण वाराणसी में नहीं है. दिल्ली में 13 जगहों पर पीएम 2.5, पीएम 10 और एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूचना देने वाले उपकरण लगे हैं. अगर हम अपने शहरों में वायु प्रदूषण का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसकी वजह से सेहत पर पड़ने वाले कुप्रभावों का अंदाज हम कैसे लगा पाएंगे. हमारे यहां इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के अभाव की स्थिति में विदेशी अध्ययनों पर भरोसा करने के अलावा और क्या विकल्प बचता है? क्या पर्यावरण मंत्री की बात मानकर हमें भारतीय विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार करते रहना चाहिए? अगर हमने ठीक से अपने शहरों और गांवों से प्रदूषण के आंकड़े जुटा लिए, तो तय मानिए हकीकत इस विदेशी रिपोर्ट से कहीं अधिक भयावह होगी.

हम आसानी से जिस हकीकत को भूल जाते हैं, वो यह है कि जहरीली हवा से सबसे अधिक प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ता है. अमीर लोग तो एसी कार में चलकर और घरों में हवा साफ करने वाली मशीन लगाकर दुष्प्रभावों से बच जाते हैं. गरीबों के सामने जहरीली हवा में अपना हर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है. गरीब लोग लकड़ी और गाय के गोबर से बनने वाले उपलों पर खाना बनाते हैं. उनके घरों में हवा की आवाजाही की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए उन्हें जहरीली हवा का दंश और झेलना पड़ता है. सरकार स्रोत का हवाला देकर स्थिति की गंभीरता को खारिज कर रही है. इससे पहले से ही खराब सेहत और पोषण में कमी का सामना कर रहे लाखों लोगों को सरकार और बुरी स्थिति में धकेल रही है. ■

लेखिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली की सलाहकार संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

योगी के रंग से सराबोर होगा बिहार

उत्तर प्रदेश की आज की राजनीति और एक युवा संन्यासी के राजतिलक के बाद बिहार के हालात तो बदले-बदले से लग ही रहे हैं. उत्साह केवल भाजपा या एनडीए तक ही सीमित नहीं है, यह महागठबंधन में भी दिख रहा है. एनडीए का हाल भी कुछ ऐसा ही है. घटक दलों के कुछ लोग एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के राजनीतिक कदमों के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. वे सियासी दोस्त-दुश्मनों के ठिकानों का नए सिरे से पता लगा रहे हैं, अपने नए आशियाने की तलाश में लगे हैं. हिन्दी पट्टी की प्रखर राजनीतिक चेतना के इस भू-खंड में नए उथल-पुथल की हरसूरत संभावना है, हालांकि इसके लिए कुछ सब्र कीजिए.

सरोज सिंह

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत बिहार की राजनीति में गरमाहट लाने के लिए काफी थी, लेकिन उसे मिले प्रचंड व ऐतिहासिक जनादेश से यहां सियासी समीकरणों में उलट-फेर होना तय है. अब आदित्यनाथ योगी (या योगी आदित्यनाथ) के सत्तारोहण से पूरे माहौल को नया रंग मिल गया है. इस नए रंग से बिहार की राजनीति ही नहीं, यहां के सामाजिक बुनावट में भी बदलाव की आशंका व्यक्त की जा रही है. हालांकि यह जल्द शुरू होगा या इसकी प्रक्रिया तुरंत दिखने लगेगी, यह मान लेना अभी अपरिपक्वता होगी. यह दिल्ली से चले राजनीतिक संदेशों और भौगोलिक सुविधा के साथ-साथ आकार ग्रहण करेगा. यह इस पर भी निर्भर करेगा कि सूबे की राजनीति इसके लिए कितना वक्त देती है. बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन के लिए असली परीक्षा का दौर अब आनेवाला है- राजनीतिक एकता व प्रशासनिक कौशल के लिहाज से भी. इसी तरह, उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक तख्ता-पलट से एनडीए भी बेअसर नहीं रहेगा. उसके भीतर भी उथल-पुथल होनी है. अगले कुछ महीनों में कई स्तरों पर कई बातें साफ होंगी.

बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन के लिए अब नई चुनौतियों का दौर शुरू होगा. इसकी राजनीतिक एकता की तो अग्निपरीक्षा होनी ही है, सरकार के नेतृत्व के प्रशासनिक कौशल को भी नए संकटों से निपटना होगा. महागठबंधन में सबसे बड़ा दल राजद है, लेकिन सत्ता में वह दूसरे नम्बर की पार्टी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपने सहज ही नहीं, पुराने व मधुर रिश्ते की बात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद या उनके परिवार के लोग पिछले डेढ़ साल से करते आ रहे हैं, नीतीश कुमार और उनके राजनीतिक खास भी इसे दुहराने में कतई पीछे नहीं रहते. ये दोनों जब एक राग में एक बोल को गाते हैं, तो भला कांग्रेस क्यों पीछे रहेगी, वह भी साथ देती है. सवाल है: राजनीतिक एकता और मेल-मिलाप वाकई में इस स्तर की है? यह सही है कि सरकार चलाने में नीतीश कुमार को अब तक राजद से किसी बड़ी परेशानी का औपचारिक तौर पर सामना नहीं करना पड़ा है. मुख्यमंत्री, जब जो चाहते हैं, करते दिख रहे हैं- बस राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से अनौपचारिक बातचीत भर जरूरी समझी जाती है. हालांकि महागठबंधन के तीसरे घटक कांग्रेस में इसे लेकर काफी रोष रहता है. यह भी सही है कि महागठबंधन को बड़े जनादेश के बावजूद कोई डेढ़ साल से मुख्यमंत्री और उनका जद (यू) महागठबंधन में सहज नहीं महसूस कर रहा है. जद (यू) के नेताओं का मानना है कि राजनीति व प्रशासन में सहजता विकसित नहीं हो पा रही है. राजद सुप्रीमो के पुत्रों व उसके कई मंत्रियों के विभागों के कामकाज में 'ऊपर के निर्देश' सर्वोपरि होते रहे हैं. सूबे में सत्ता का एक 'समानान्तर और मजबूत' केंद्र विकसित हो गया है. सरकार के दैनंदिन कामकाज में यह कई परेशानियों को जन्म दे रहा है, जिसका संदेश, उनके हिसाब से, सकारात्मक तो कतई नहीं है. फिर, अनेक राजद नेताओं के सरकार विरोधी बयानात भी असहज हालात पैदा कर देते हैं. ऐसे अनेक राजनीतिक आचरण के कारण जद (यू) में कई बार दबाव महसूस किया गया है. हालांकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक ही राजनीतिक धारा की उपज हैं और दोनों का राजनीतिक वैपटिज्म भी समान विचार के राजनेताओं की छत्रछाया में हुआ है. सूबे के कुछ खास समूहों को अलग कर दें तो दोनों के लक्षित सामाजिक समूह-सामाजिक मतदाता समूह-भी एक हैं. लेकिन कोई दो दशक के विलगाव और विपरीत राजनीतिक-शैली दोनों नेताओं को सहज नहीं होने दे रही है या यूं कहें कि 1990 के दशक के जनता दल के दौर में नहीं पहुंचने दे रही है. इस असहजता का लाभ किसी को तो मिलना ही है. इस

राजनीतिक माहौल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले, चुनाव अभियान के दौरान और परिणाम की घोषणा व आदित्यनाथ योगी के सत्तारोहण के बाद भाजपा और इसका केन्द्रीय नेतृत्व अपने तरीके से खूब हवा दे रहा है. प्रधानमंत्री सहित केन्द्र के अनेक गैर-बिहारी मंत्री नीतीश सरकार के कामकाज की सार्वजनिक तारीफ कर रहे हैं और लालू प्रसाद, उनके परिजन व राजद पर निशाना साध रहे हैं. यह सुनिश्चित रणनीति के तहत हो रहा है.

भाजपा या केन्द्र सरकार का अगला निशाना अब बिहार ही है, यह सूबे की गैर भाजपाई राजनीति जानती है. हिन्दी पट्टी में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा अपने समन्वित विरोधी (लालू प्रसाद- नीतीश कुमार की एकजुट ताकत) की राजनीति के सामने काफी कमजोर दिख रही है. हालांकि भाजपा के लिए रणनीतिक तौर पर काफी राहत है कि आज देश के सबसे बड़े राजनेता नरेन्द्र मोदी और सबसे बड़े आक्रामक हिन्दुत्ववादी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों (वाराणसी और गोरखपुर) से महागठबंधन सरकार के प्रभाव क्षेत्र को सीधे निशाने पर ले रखा है. लेकिन भाजपा की रणनीति में परोक्ष राजनीति ज्यादा महत्व रखती है. लिहाजा वह लालू-नीतीश को अलग करने के साथ-साथ गैर भाजपाई मतदाता समूहों की एकता को कमजोर करने का हरसंभव उपाय करेगी. भाजपा के दिल्ली से पटना वाया लखनऊ तक के नेतृत्व की यह रणनीति बिहार के प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन सकती है. सूबे के कई हिस्से सामाजिक और सांप्रदायिक तौर पर काफी संवेदनशील हैं. शासन की निष्क्रियता से उत्पन्न असंतोष को इनके बीच भुनाना आसान होता है. प्रशासन की परिणाम-मुखी सक्रियता माहौल को सहज बनाने में सबसे ज्यादा मददगार होती है. संयोग से इस फ्रंट पर बिहार के हालात बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं. ऐसे हालात में सत्ता-समूह के अंतर्विरोध व आंतरिक राजनीतिक अविश्वास भी अपनी भूमिका निभाते हैं. हाशिये पर फेंके गए सामाजिक समूह सत्ता में अपना हिस्सा चाहते हैं, अपनी सुनिश्चित भूमिका की अपेक्षा रखते हैं. शीर्ष पर पकड़ ढीली पड़ने से ये हालात अपना रंग दिखाते हैं. इसके अलावा शासन की विफलताएं भी होती हैं. ये सब कुछ न कुछ तो असरकारी होंगे ही. ये महागठबंधन की एका को तो प्रभावित करेंगे ही, सूबे में सत्ता के इकबाल को भी कमजोर करेंगे.

एनडीए के भीतर भाजपा के प्रति उसके सहयोगी, मगर छोटे दलों, का नजरिया चुनाव परिणाम आने के साथ ही बदला दिखने लगा. बिहार में भाजपा के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा), राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी (रालोसपा) और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) एनडीए में शामिल है. पिछले कई महीनों से इन दलों की ओर से दबे स्वर में भाजपा के नेतृत्व के प्रति आक्रोश तो जताया ही गया, साथ ही उन पर वर्चस्ववादी राजनीतिक

> **भाजपा या केन्द्र सरकार का अगला निशाना अब बिहार ही है, यह सूबे की गैर भाजपाई राजनीति जानती है. हिन्दी पट्टी में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा अपने समन्वित विरोधी (लालू प्रसाद- नीतीश कुमार की एकजुट ताकत) की राजनीति के सामने काफी कमजोर दिख रही है. हालांकि भाजपा के लिए रणनीतिक तौर पर काफी राहत है कि आज देश के सबसे बड़े राजनेता नरेन्द्र मोदी और सबसे आक्रामक हिन्दुत्ववादी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों (वाराणसी और गोरखपुर) से महागठबंधन सरकार के प्रभाव क्षेत्र को सीधे निशाने पर ले रखा है. लेकिन भाजपा की रणनीति में परोक्ष राजनीति ज्यादा महत्व रखती है. लिहाजा वह लालू-नीतीश को अलग करने के साथ-साथ गैर भाजपाई मतदाता समूहों की एकता को कमजोर करने का हरसंभव उपाय करेगी.**

आचरण का परोक्ष आरोप भी लगा है. विधान परिषद के हालिया चुनाव के दौरान तो ये बातें खुल कर कही जा रही थीं. लोजपा के प्रादेशिक नेतृत्व ने तो ऐसा किया भी. हम के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी विभिन्न अवसरों पर अपनी नाराजगी जताने में परहेज नहीं की. केन्द्रीय राज्य मंत्री व रालोसपा सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा ने तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वाराणसी में हुए रोड शो के लिए भाजपा नेतृत्व को ही कठघरे में खड़ा कर दिया था. चुनाव परिणाम के साथ- 11 मार्च के पूर्वाह्न से ही- एनडीए के इन दलों के सुर बदल गए. प्रधानमंत्री व भाजपा नेतृत्व की प्रशंसा के कसीदे पढ़े जाने लगे. मंदिर-मस्जिद विवाद को छोड़ दें तो इन दलों ने भगवा और हिन्दुत्व को लेकर भी कुछ खास कहने से परहेज करना शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक जीत से भाजपा के भीतर - पटना से लेकर प्रखंड स्तर तक- जश्न का माहौल था, पर योगी आदित्यनाथ के सत्तारोहण ने तो इसे और गहरा भगवा रंग दे दिया. भाजपा के नेता-कार्यकर्ता ही नहीं, इसके समर्थक और कुछ अर्थों में वोटर भी इस जीत से उत्साहित हैं. हालत यह है कि इसके समर्थक सरकारी परिसरों में जबर्दस्ती पार्टी का झंडा फहरा दे रहे हैं. पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा कर इस मनोबल का राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है. लिहाजा बिहार में भी अभियान की शुरुआत हो चुकी है. सवाल ये है कि क्या बिहार में पार्टी इस जीत का पूरा राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए हर तरह से तैयार है? इस सवाल का उत्तर देना किसी भी गैर भाजपाई के लिए सहज नहीं है. अनौपचारिक तौर पर भाजपा के नेता भी 'अगर-मगर' के साथ ही इसका जवाब दे रहे हैं. वस्तुतः बिहार में एनडीए- किसी बड़े उलट-फेर न होने पर- ठीक है, पर भाजपा के लिए ऐसी बात विश्वासपूर्वक कहना फिलहाल कठिन है. प्रदेश भाजपा में अनौपचारिक तौर पर मान लिया गया है कि सुशील कुमार मोदी युग का अवसान निकट है, लेकिन संकट यह है कि उन्हें रिप्लेस करने के लिए सक्षम नेतृत्व गढ़ा नहीं गया है. केन्द्रीय नेतृत्व जिन नेताओं पर दांव खेल रहा है, उनमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार- संयुक्त या अलग-अलग-की आक्रामक राजनीति के मुकाबले की क्षमता नहीं दिखती है. बिहार के राजनीतिक- सामाजिक समीकरण की गंभीर समझ का तो उनमें अभाव है ही, विभिन्न सामाजिक समूहों में उनकी स्वीकृति भी सीमित है. इसके बाद भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व किस हद तक जोखिम मोल लेगा, यह बड़ा सवाल है. संसदीय चुनावों के लिए व्यावहारिक तौर पर अब दो साल का भी वक्त नहीं बचा है. हालांकि हाल के महीनों में लगभग हर नाजुक मौकों पर सुशील कुमार मोदी दरकिनार किए जाते रहे हैं. ऐसे में पार्टी किस हद तक कोई जोखिम लेती है, यह देखना है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में केन्द्रीय नेतृत्व क्या चाहता है? केन्द्रीय नेतृत्व के राजनीतिक आचरण से इतना तो तय है कि सत्तारूढ़ महागठबंधन को विभाजन की सीमा तक जाते देखना उसकी बिहार की कार्य-नीति में सबसे ऊपर है. देखना है कि इस संदर्भ में उसका रोड मैप क्या होता है?

यह सब साफ होने में अभी वक्त लगेगा, पर उत्तर प्रदेश की आज की राजनीति और एक युवा संन्यासी के राजतिलक के बाद बिहार के हालात तो बदले-बदले से लग ही रहे हैं. उत्साह केवल भाजपा या एनडीए तक ही सीमित नहीं है, यह महागठबंधन में भी दिख रहा है. एनडीए का हाल भी कुछ ऐसा ही है. घटक दलों के कुछ लोग एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के राजनीतिक कदमों के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. वे अपने राजनीतिक दोस्त-दुश्मन के ठिकानों का नए सिरे से पता लगा रहे हैं, अपने नए आशियाने की तलाश में लगे हैं. हिन्दी पट्टी की प्रखर राजनीतिक चेतना के इस भू-खंड में नए उथल-पुथल की हरसूरत संभावना है. इसके लिए कुछ सब्र कीजिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.vastuvihar.org
वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 63 शहरों में 117 आवासीय परियोजनाओं की श्रृंखला
Call : 95340 95340

नई करवट लेगी मुस्लिम सियासत

इरशादुल हक

यूपी चुनाव परिणाम के बाद पटना में सेक्युलर सोच रखने वाले दो गैर राजनीतिक समूहों की अलग-अलग मीटिंग हुई. इन दोनों मीटिंग में से एक विशुद्ध रूप से मुस्लिम बुद्धिजीवियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की थी. तो दूसरी मीटिंग में हिंदू-मुस्लिम व ईसाई-तीनों धर्मों के बुद्धिजीवी शामिल थे. इन दोनों मीटिंग में आए विचारों पर बारी-बारी से गौर करें तो यूपी चुनावों के बिहार पर पड़ने वाले प्रभावों को समझा जा सकता है. आइए इन दो मीटिंग में उभरे विचारों पर गौर करते हैं.

पहले मुस्लिम बुद्धिजीवियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग पर गौर करते हैं. मीटिंग में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि यूपी में सांप्रदायिक शक्तियां उम्मीदों से ज्यादा मजबूत हुई हैं. जब सेक्युलरिज्म को मजबूत करने जैसे मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ी तो बैठक में लोगों की दो तरह की राय सामने आई. पहली राय यह थी कि बिहार में 2015 के विधान सभा चुनाव में मुसलमानों ने जो टैक्टिकल वोटिंग की थी और जिस तरह से महागठबंधन को जिताया था, वह एक सधा हुआ तरीका था. इस तरीके को आगे बनाए रखने की जरूरत है. दूसरी राय पहले से एक दम मुख्तलिफ थी. कुछ युवा और उत्साही बुद्धिजीवियों का तर्क था कि सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमान जिन राजनीतिक समूहों को वोट करते हैं, वे मुसलमानों की ताकत से सत्ता में चले तो जाते हैं, पर कयादत (नेतृत्व) के स्तर पर मुसलमानों का कोई भला नहीं होता. यही कारण है कि सत्तर सालों में बिहार में मुस्लिम लीडरशिप का बिल्कुल विकास नहीं हुआ. लिहाजा, दूसरी राय पेश करने वालों का तर्क था कि मुसलमानों को अपनी सियासत करनी है, तो अपनी कयादत (लीडरशिप) भी विकसित करनी पड़ेगी. सेक्युलरिज्म के कथित अलमबरदारों के चंगुल से मुसलमानों को निकालना पड़ेगा. अगर मुसलमानों के राजनीतिक व्यवहार में यह परिवर्तन लाया जा सका, तो मुस्लिम नेतृत्व इतना ताकतवर हो सकेगा, जितने मजबूत बिहार में लालू प्रसाद हैं. तर्क यह भी था कि आखिर 12 प्रतिशत से कम आबादी वाले यादवों की एकजुटता से लालू जैसे ताकतवर नेता उभर सकते हैं तो क्या वजह है कि 17 प्रतिशत आबादी वाले मुसलमानों की एकजुटता से कोई मुस्लिम रहबर नहीं उभर सकता? इस विचार को पेश करने वाले बुद्धिजीवियों का राजनीतिक दृष्टिकोण उस पारम्परिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है, जो असदुद्दीन ओवैसी ब्रांड राजनीति का पक्षधर रहा है. इस मीटिंग के बुद्धिजीवियों की स्पष्ट मान्यता है कि राजनीतिक नेतृत्व तो मुसलमानों के हाथ में हो पर राजनीति का केंद्र बिंदु पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो. मुस्लिम

नेतृत्व वाली यह राजनीति असम के बदरुद्दीन अजमल के ब्रांड की राजनीति हो. असम में बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाला एआईयूडीएफ (ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) पिछले एक दशक में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है और उसकी राजनीति धर्मनिरपेक्षता के उसूलों पर आधारित है. बुद्धिजीवियों का तर्क था कि बिहार में जब मुस्लिम कयादत वाली ऐसी राजनीति उभरेगी तब सेक्युलर राजनीति करने वाले दलों के साथ समानता के आधार पर गठबंधन किया जा सकता है. ऐसे में लालू व नीतीश जैसे नेताओं की मजबूरी होगी कि वे उनसे गठबंधन करें. याद रखने की बात है कि बिहार में 2015 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन ओवैसी की कट्टर राजनीतिक पहचान के कारण कोई भी दल उनसे गठबंधन को तैयार नहीं हुआ. यहां तक कि मुसलमानों ने भी ओवैसी की पार्टी को वोट नहीं दिया था. उत्तर प्रदेश के हालिया चुनाव में भी पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने ओवैसी की पार्टी को नकार दिया.

अब आइए यूपी चुनाव के बाद बिहार में जो दूसरा मंथन हुआ उसका उल्लेख करते हैं. इस मंथन कैम्प में सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर, सत्यनारायण मदन, ईसाई मिशनरी से जुड़े फादर मंथरा, पत्रकार सुरूर अहमद, मोहम्मद जाहिद, कंचन बाला, महेंद्र सुमन सरीखे लगभग तीन दर्जन लोग मौजूद थे. सबकी चिंता स्वाभाविक तौर पर यूपी में साम्प्रदायिक शक्तियों के सशक्त होने को लेकर थी. इस मीटिंग में चर्चा से उभरे मुद्दों का सार यह था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सेक्युलर शक्तियों को एकजुट करना और गांव-गांव में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रचार-प्रसार के साथ युवाओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी करना. इस मीटिंग में लोगों का मत था कि बिहार ने जो प्रदर्शन 2015 के विधानसभा चुनाव में किया है उसे आगे भी बनाए रखने के लिए काम करना है.

अब इन दो मीटिंग से स्पष्ट है कि यूपी चुनाव ने बिहार में गैरभाजपा राजनीतिक संस्कृति को मजबूत करने की प्राथमिकता तय कर दी है. लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि बिहार में यूपी के चुनाव परिणामों का व्यापक प्रभाव आम जन के मन-मस्तिष्क पर हुआ है. उधर स्वाभाविक तौर पर भाजपा खेमे में काफी उत्साह है. इसकी दो मिसाल यही है कि यूपी चुनाव परिणाम के दिन बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और दूसरा जश्न तब मना जब आदित्यनाथ योगी ने यूपी के मुख्यमंत्री की कमान संभाल ली. उधर बिहार भाजपा के नेताओं के लगातार आ रहे बयानों में इस बात का उल्लेख किया जाना कि अब बिहार की बारी है, यह सोचने के लिए पर्याप्त है कि भाजपा की जीत से उसका मनोबल काफी बढ़ा है.

यहां यह कहना मुश्किल है कि मुस्लिमों और सेक्युलर सोच रखने वाले बुद्धिजीवियों के मंथन के बाद उनके विचारों को व्यावहारिक बनाने में कितनी पहलकदमी की जाएगी. हालांकि ये तय है कि यूपी चुनाव के बाद बिहार की तीनों बड़ी गैरभाजपा पार्टियों के कान जरूर खड़े हो गए हैं. खास तौर पर तब, जब यूपी में गैर जाटव और गैर यादवों के भाजपा की तरफ शिफ्ट होने से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, इसमें दो राय नहीं है. हालांकि यूपी चुनाव को लेकर राजद, जद यू और कांग्रेस के लिए सुखद स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के बरक्स बिहार में गैरभाजपा दलों का गठबंधन मजबूत है. वहां मायावती का अलग चुनाव लड़ना ही सपा, कांग्रेस और बसपा के लिए हार का कारण बना था. लालू और नीतीश इस तर्क को अपने लिए सकारात्मक मान सकते हैं कि यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस का मत प्रतिशत भाजपा से ज्यादा था. स्वाभाविक तौर पर बिहार की सेक्युलर आइडियोलॉजी की राजनीति करने वाले दलों के लिए एक सबक यह है कि आने वाले चुनाव में अपने गठबंधन को और मजबूत करें.

जहां तक यूपी के मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न की बात है तो आंकड़ों को देखने से यह साफ हो जाता है कि मुस्लिम मतों का विभाजन सपा-कांग्रेस और बसपा के बीच हुआ. यूपी में 19.9 प्रतिशत मुस्लिम वोटर हैं. इस प्रकार देखें तो सपा की भारी पराजय के बाद भी उसके कुल चुने गए 47 विधायकों में 18 मुस्लिम हैं, जो कुल प्रतिनिधित्व का 38.3 प्रतिशत होता है. सपा के इतिहास में मुसलमान विधायकों की यह रिकॉर्ड नुमाइंदगी है. इसी तरह बसपा के कुल जीते 19 विधायकों में 5 मुस्लिम हैं जो प्रतिशत के लिहाज से 26 से ज्यादा हैं. बसपा के लिए भी मुस्लिम विधायकों का यह प्रतिशत अब तक का सबसे ज्यादा है. वहीं ओवैसी की पार्टी के एक भी उम्मीदवार का न जीत पाना यह साबित करता है कि मुसलमानों ने उन्हें वहां भी नकार दिया, जहां मुसलमानों की आबादी 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है.

यूपी में मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न भी बिहार के सेक्युलर-समाजवादी राजनीति के पुरोधाओं के लिए एक नसीहत है, जो बताता है कि बिहार में भाजपा से टक्कर लेने के लिए यह अनिवार्य है कि गैरभाजपा दलों का गठबंधन बना और बचा रहे. चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अभी ढाई साल का वक्त है इसलिए यह संभव है कि आने वाले दिनों में राजनीति कई करवटें लेंगी. कई उतार-चढ़ाव आएंगे. हमने ऊपर मुसलमानों की मीटिंग का जिक्र किया है. उस मीटिंग में उभर कर सामने आने वाले विचारों पर अगर फिर से गौर करें तो यह संभव है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों का वैकल्पिक नेतृत्व अपनी मजबूती के लिए संघर्ष कर सकता है. इसके लिए वह असम के बदरुद्दीन अजमल की राजनीति का अनुसरण करने की कोशिश कर सकते हैं. यह संभव है कि इसके लिए बदरुद्दीन अजमल के एआईयूडीएफ से सम्पर्क साधा जाए. वैसे बिहार चुनाव पर नजर रखने वालों को याद होगा कि अफाकत रहमान के नेतृत्व वाले जनता दल राष्ट्रवादी (जेडीआर) ने 2015 में अपने चालीस उम्मीदवार मैदान में उतारे थे. जेडीआर अपनी सियासत और अपनी कयादत के नारे के साथ मैदान में उतरा था. हालांकि तब इस नारे ने मुसलमानों को आकर्षित करने में कोई कामयाबी हासिल नहीं की थी, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार के मुसलमान इस नारे से प्रभावित हों और अपने लिए राजनीति में एक नयी राह बनाने की कोशिश करें. ऐसे हालात में सेक्युलर पार्टियों के लिए एक नई चुनौती भी सामने आ सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

खुली सुनवाई में महिला पंच की भागीदारी

डॉ. चंद्रशेखर प्राण

एक अगस्त, 2016 को तीसरी सरकार अभियान के एक कार्यक्रम के सिलसिले में बिहार में प्रवास के दौरान वहां की पंचायती सरकार व्यवस्था के अंतर्गत संचालित न्याय पंचायत की न्यायिक कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला. यहां महिला पंच ग्राम कचहरी में खुली सुनवाई में हिस्सा लेती दिख जाएंगी. ग्राम कचहरी के अनुभव को आप के साथ बांटना चाहता हूं.

तारीख *– एक अगस्त, 2016. स्थान – बिहार में समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड स्थित धर्मपुर ग्राम पंचायत.*

मुझे बताया गया कि पिछले दस वर्षों में यहां की ग्राम कचहरी में लगभग 400 विवाद दाखिल हुए. सभी विवादों का निपटारा ग्राम कचहरी द्वारा किया गया. एक भी विवाद गांव से बाहर नहीं गया है. अधिकांश विवादों में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ है. कुछ में 500 रुपए तक का जुर्माना हुआ है, जिसे दोषी व्यक्ति द्वारा भरा गया. मैंने यहां ग्राम कचहरी के प्रति ग्रामीणों में गहरी आस्था देखी. उल्लेखनीय है कि यहां के वर्तमान सरपंच मनीष कुमार झा युवा हैं और लगातार तीसरी बार सरपंच के रूप में भारी मतों से चुने गए हैं. झा ने एमए, एलएलबी की पढ़ाई की है. लोगों ने बताया कि झा बहुत उत्साहित, समझदार तथा ईमानदार व्यक्ति हैं. संभवतः यह भी एक वजह है कि यहां के ग्रामीणों में ग्राम कचहरी के प्रति गहरा विश्वास है .

एक अगस्त को जो विवाद इस ग्राम कचहरी में सुना गया, वह दलित वर्ग के दो परिवारों के बीच हुए झगड़े से संबंधित था. रुपए के लेन-देन को लेकर एक परिवार की महिला का दूसरे परिवार के पुरुष से झगड़ा हुआ था. झगड़े में गाली-गलौच तथा साधारण मारपीट भी हुई थी. महिला ने ग्राम कचहरी में शिकायत दर्ज कराई थी. यह विवाद ग्राम कचहरी की पूर्ण पीठ द्वारा सुना गया. सुनवाई में सरपंच और उपसरपंच के अतिरिक्त सात अन्य पंच शामिल थे. इनमें से 06 पंच महिला थीं. ग्राम कचहरी में इस मामले की विधिवत सुनवाई हुई. उस दौरान गांव के भी काफी लोग मौजूद थे. इस खुली सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सभी पंचों ने न्यायमित्र की सलाह के साथ-साथ सरपंच से भी चर्चा की. पंचों के अनुसार दोनों पक्ष दोषी पाए गए. दोनों पक्षों को उनकी गलतियों से अवगत कराते हुए ग्राम कचहरी ने उनके बीच समझौते का प्रस्ताव रखा. दोनों पक्षों ने सहजता से इसे स्वीकार किया और पूरी रजामंदी के साथ ख़ुशी-ख़ुशी समझौते के पेपर पर हस्ताक्षर किए.

ग्राम कचहरी : एक ज़रूरत

मैंने सोचा कि यदि बिहार में ग्राम कचहरी सक्रिय न होती, तो क्या होता? जाहिर है कि ऐसे में उक्त विवाद थाने में जा सकता था. थानों में क्या होता है, हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं. यह भी हो सकता था कि यह विवाद धीरे-धीरे और बड़ा रूप ले लेता और फिर जिला अदालत या उससे भी आगे जाता. उनके बीच का परस्पर भाईचारा और सद्भाव सदैव के लिए नष्ट हो जाता.

बिहार के सन्दर्भ में ग्राम कचहरी में अब तक जो विवाद दाखिल हुए हैं और जिन पर कार्रवाई हुई है, उनके सम्बन्ध में अब तक हुए अध्ययनों से जो तथ्य निकलते हैं, उसमें जमीन संबंधी विवाद 58 प्रतिशत तथा घरेलु विवाद 20 प्रतिशत है. इसमें से 85 प्रतिशत विवाद दलित एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित है. बिहार में ग्राम कचहरी में आए इन विवादों का 90 प्रतिशत समझौते द्वारा तय हुआ है. अन्य 10 प्रतिशत मामलों में 100 से 1000 रुपए जुर्माना लगाया गया है. ज्यादातर मामलों में दोषी ने सहज रूप से जुर्माना भरा है. लगभग तीन प्रतिशत विवाद ही ऊपर की अदालतों में अपील हेतु गए हैं. इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बिहार में ग्राम कचहरी के माध्यम से गांव के दलित और कमजोर वर्ग के लोगों के आपसी विवाद गांव में सुलझ रहे हैं. उन्हें थाने और जिला कचहरी के चक्कर लगाने तथा बहुत सारा अनावश्यक धन खर्च करने से फुर्सत मिल गई है. गांवों में इसका प्रभाव भी दिखाई पड़ता है.

विचारणीय तथ्य

यहां गौर करने लायक बात यह है कि इस समय देश में तीन करोड़ से अधिक मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं. इसमें से 66 प्रतिशत मुकदमे जमीन व संपत्ति से संबंधित हैं. दस प्रतिशत पारिवारिक विवाद से जुड़े हैं. इन 76 प्रतिशत विवादों का एक बड़ा हिस्सा गांव से जुड़ा है. इनमें भी 90 प्रतिशत विवाद ऐसे लोगों के हैं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम है. ये ज्यादातर दलित और पिछड़ी जाति के लोग हैं. वर्तमान न्याय व्यवस्था बहुत ही खर्चीली तथा विलम्ब से न्याय देने वाली हो गई है. एक केस औसतन 10 साल चलता है और एक केस में तीन लाख से अधिक व्यय होता है.

इन आंकड़ों के संदर्भ में ग्राम कचहरी यानी हमारी पंचायती राज प्रणाली में न्याय पंचायत का होना और ज़रूरी तथा महत्वपूर्ण हो जाता है. ■

(लेखक तीसरी सरकार अभियान के मूल विचारक एवं संचालक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

बच्चों में भूख न लगना

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
SAMARTH CHIELD HEALTH CARE, Near Canara Bank, Nawada
डॉ. सुनिल कुमार
M.D PEDIATRICS

नवादा सामर्थ चाइल्ड हेल्थ केयर के डॉ. सुनिल कुमार से हुई बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत है जिसमें उन्होने बच्चों में भूख की कमी के बारे में प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि यदि मां-बाप को लगे कि बच्चों में भूख की कमी है तो आप चिकित्सक से जरूर सम्पर्क करें और जैसा वो इलाज करें उसके अनुसार चलें। उन्होंने बताया कि बच्चों में भूख नहीं लगने के मुख्य कारणों में पेट में कीड़ा, खून की कमी, लिवर आदि की समस्या है। आगे उन्होंने बताया कि जिन बच्चों मे मिट्टी खाने की आदत होती है उनमें भी भूख न लगने की समस्या आती है। बच्चों के होने वाले डायरिया के सम्बन्ध में बात करने पर उन्होंने बताया कि जिन बच्चों को बचपन में डायरिया होता है उनमें पूर्ण विकास की संभावना कम रहती है। चाहे वो शारिरीक हो या मेन्टल ग्रोथ। उन्होंने आगे नवजात बच्चों में पूर्ण विकास के लिए मां के दूध को सर्वोत्तम माना और बताया कि मां का दूध ही बच्चे के पूरे भोजन का काम करता है। शुरुआत में दो-तीन महीने बच्चा दूध पीकर अगर उल्टी कर देता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक बच्चा मां का दूध पीता है तब तक दूध को हजम करने के लिए बच्चे को किसी घुट्टी या ग्राइप वाटर की जरूरत नहीं है। जब तक बच्चा मां का दूध पीए, तब तक मां को चाहिए कि वह खाना खाने के बाद पानी न पीए, बल्कि बच्चे को दूध पिलाने से 15 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी लें, इसके बाद ही बच्चे को स्तनपान कराएं। ऐसा करने से बच्चे को उल्टी-दस्त नहीं होते हैं। मां को सदा खुश होकर और हर दो से तीन घंटे के अंतर पर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ■ भारती

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxidant
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Capi/Syp.

NOKSIRA
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of Ariskon Pharma

योगी का शपथ ग्रहण

उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद बनी भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के मौके पर मंच का विहंगम दृश्य... इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम महत्वपूर्ण अतिथियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगी मंत्री दिख रहे हैं

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक 19 मार्च, 2017 को लखनऊ के स्मृति उपवन में योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक 19 मार्च, 2017 को लखनऊ के स्मृति उपवन में केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए.

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक 19 मार्च, 2017 को लखनऊ के स्मृति उपवन में डॉ. दिनेश शर्मा को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए.

मुख्यमंत्री बनने के बाद क्रमशः राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

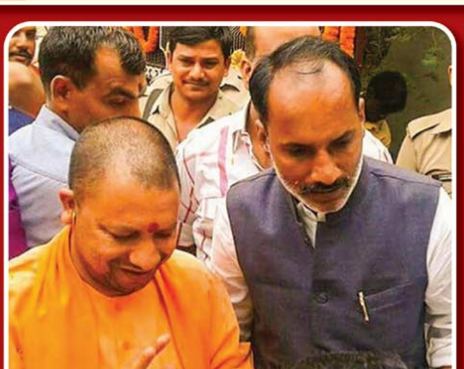

योगी आदित्यनाथ का एयरपोर्ट पर स्वागत करते गोरखपुर के क्षेत्रीय मंत्री अजय सिंह गौतम

जनता का अभिवादन स्वीकार करते अमित शाह और योगी आदित्यनाथ

सचिवालय का मुआयना करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

फोटो : विनय लॅस कुमार

शपथ ग्रहण समारोह में दर्शक दीर्घा में प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद साक्षी महाराज व अन्य

सचिवालय के विभिन्न कक्षों में धूल-गर्द में पड़ी फाइलें देखते मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री

शपथ ग्रहण के बाद प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में हैं दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉ. दिनेश शर्मा

शपथ ग्रहण में मोदी और मुलायम मिले तो कान में कुछ गुफ्तगू होने लगी. इसे लेकर जनता में खूब हास-परिहास हुआ कि कटप्पा ने बाहुबली से क्या कहा और मुलायम ने मोदी से क्या कहा?

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ डॉ. महेंद्र सिंह, रीता बहुगुणा जोशी और सिद्धार्थनाथ सिंह

योगी मंत्रिमंडल पर एक नज़र...

1. योगी आदित्यनाथ	मुख्यमंत्री	गृह, आवास व शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य व रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन, अर्थ व संख्या, भूतत्व व खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबंधन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, समन्वय, भाषा, बाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता व पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप विभाग.
2. केशव प्रसाद मौर्य	उपमुख्यमंत्री	लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम विभाग.
3. डॉ. दिनेश शर्मा	उपमुख्यमंत्री	माध्यमिक व उच्च शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.
4. सूर्य प्रताप शाही	कैबिनेट मंत्री	कृषि, कृषि शिक्षा व कृषि अनुसंधान विभाग.
5. सुरेश खन्ना	कैबिनेट मंत्री	संसदीय कार्य, नगर विकास और शहरी समग्र विकास विभाग.
6. स्वामी प्रसाद	कैबिनेट मंत्री	श्रम एवं सेवा योजना, नगरीय रोजगार व गरीबी उन्मूलन.
7. सतीश महाना	कैबिनेट मंत्री	औद्योगिक विकास.
8. राजेश अग्रवाल	कैबिनेट मंत्री	वित्त विभाग.
9. रीता बहुगुणा जोशी	कैबिनेट मंत्री	महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ व शिशु कल्याण और पर्यटन विभाग.
10.दारा सिंह चौहान	कैबिनेट मंत्री	वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान और उद्यान विभाग.
11.धरमपाल सिंह	कैबिनेट मंत्री	सिंचाई विभाग.
12.एसपी सिंह बघेल	कैबिनेट मंत्री	पशुधन, लघु सिंचाई और मत्स्य विभाग.
13.सत्यदेव पचौरी	कैबिनेट मंत्री	खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग.
14.रमापति शास्त्री	कैबिनेट मंत्री	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग.
15.जय प्रकाश सिंह	कैबिनेट मंत्री	आबकारी व मद्यनिषेध.
16.ओम प्रकाश राजभर	कैबिनेट मंत्री	पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग जन विकास विभाग.
17.बृजेश पाठक	कैबिनेट मंत्री	विधि एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत और राजनीतिक पेंशन विभाग.
18.लक्ष्मी नारायण चौधरी	कैबिनेट मंत्री	दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.
19.चेतन चौहान	कैबिनेट मंत्री	खेल एवं युवा कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग.
20.श्रीकांत शर्मा	कैबिनेट मंत्री	ऊर्जा विभाग.
21.राजेन्द्र प्रताप सिंह	कैबिनेट मंत्री	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा.
22.सिद्धार्थनाथ सिंह	कैबिनेट मंत्री	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य.
23.मुकुट बिहारी वर्मा	कैबिनेट मंत्री	सहकारिता.
24.आशुतोष टंडन	कैबिनेट मंत्री	प्राविधिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा विभाग.
25.नंद कुमार नंदी	कैबिनेट मंत्री	स्टाम्प और न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक उड्डयन विभाग.
26.अनुपमा जायसवाल	राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार	बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व एवं वित्त विभाग.
27.सुरेश राणा	राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार	गन्ना विकास व चीनी मिलें, औद्योगिक विकास विभाग.
28.उपेन्द्र तिवारी	राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार	जल सम्पूर्ति, भूमि विकास व जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन व पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान और सहकारिता विभाग.
29.डॉ. महेन्द्र सिंह	राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार	ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.
30.स्वतंत्र देव सिंह	राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार	परिवहन, प्रोटोकॉल और ऊर्जा
31.भूपेन्द्र सिंह चौधरी	राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार	पंचायती राज व लोक निर्माण विभाग.
32.धरम सिंह सैनी	राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार	आयुष, अभाव सहायता व पुनर्वास विभाग.
33.अनिल राजभर	राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार	सैनिक कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा.
34.स्वाति सिंह	राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार	एनआरआई, बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ व शिशु कल्याण विभाग का कार्य आवंटित किया गया है.
35.गुलाबो देवी	राज्यमंत्री	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग.
36.जय प्रकाश निषाद	राज्यमंत्री	पशुधन व मत्स्य, राज्य सम्पत्ति व नगर भूमि विकास विभाग.
37.अर्चना पांडेय	राज्यमंत्री	खनन, आबकारी और मद्यनिषेध विभाग.
38.जय कुमार सिंह जैकी	राज्यमंत्री	कारागार और लोक सेवा प्रबंधन विभाग.
39.अतुल गर्ग	राज्यमंत्री	खाद्य-रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप, खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग.
40.रणवेन्द्र प्रताप सिंह	राज्यमंत्री	कृषि, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान विभाग.
41.नीलकंठ तिवारी	राज्यमंत्री	विधि-न्याय, सूचना, खेल व युवा कल्याण विभाग.
42.मोहसिन रजा	राज्यमंत्री	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग.
43.गिरीश यादव	राज्यमंत्री	नगर विकास, अभाव सहायता एवं पुनर्वास विभाग.
44.बलदेव सिंह औलख	राज्यमंत्री	अल्पसंख्यक कल्याण और सिंचाई विभाग.
45.मनोहर लाल पंथ उर्फ मन्नु कोरी	राज्यमंत्री	श्रम सेवा योजन विभाग.
46.संदीप सिंह	राज्यमंत्री	बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, चिकित्सा शिक्षा.
47.सुरेश पासी	राज्यमंत्री	आवास, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विभाग.

तू पंत मैं निराला की जकड़न में साहित्य

अनंत विजय

काफी दिनों के बाद दिल्ली के साहित्य अकादमी जाना हुआ, वहां हिंदी के एक वरिष्ठ आलोचक से मुलाकात हुई. बातें चलीं तो इन दिनों सक्रिय लेखकों की सृजनात्मकता पर भी बात शुरू हुई. कविता, कहानी आलोचना से लेकर फेसबुक पर चल रही साहित्यिक गतिविधियों पर भी बात हुई. इस बातचीत में उन्होंने कई ऐसी टिप्पणी की, जो समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में सटीक बैठती है. उन्होंने साहित्य की मौजूदा पीढ़ी को हिंदी साहित्य की आत्ममुग्ध पीढ़ी की संज्ञा दी. जब मैंने एतराज जताया तो बोले कि आप जरा वस्तुनिष्ठ होकर विचार करो तो मेरी बात सही लगेगी. उनके तर्क थे कि आज के लेखक अपने वरिष्ठ लेखकों को पढ़कर उनकी रचनाओं से आगे जाने का कोई उपक्रम करते नहीं दिख रहे हैं, वो तो बस अपनी ही पीढ़ी के लेखकों के कंधों पर पांव रखकर आगे निकल जाने की होड़ में शामिल हैं. हर लेखक पुरस्कृत होना चाहता है और उसको लगता है कि वो शेक्सपियर और दस्तावस्की जैसा महान लेखक हो गया है. उन्होंने जोर देकर कहा था कि साहित्य लंबे समय तक चलने वाली एक ऐसी साधना है जिसमें फल मिलने की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है, लेकिन इन दिनों जो लोग कहानी या उपन्यास लिख रहे हैं उनको साधना से कोई लेना देना नहीं है. वे तो तप के पहले ही वरदान के आकांक्षी हुए जा रहे हैं. मैंने उनसे कहा कि इस तरह हवा में बातें ना करें और उदाहरण देकर बताएं. उन्होंने छूटते ही कहा कि साहित्यिक पत्रिका पाखी में कहानीकार-उपन्यासकार अल्पना मिश्रा का साक्षात्कार देख लें. उनके मुताबिक यह साक्षात्कार आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है, जिसमें कोई लेखक अपनी ही रचना को महान बता रहा है और दूसरे की रचना को फ्लॉप करार दे रहा है. यह आत्ममुग्धता नहीं तो और क्या है. मैं अवाक उनको सुन रहा था और वो धाराप्रवाह पाखी के उस इंटरव्यू की धज्जियां उड़ा रहे थे. उस साक्षात्कार में अल्पना जी ने प्रेम भारद्वाज के शब्दों को लेकर खुद को अनकन्वेंशनल लेखक कहा है. मुझे लगता है कि अल्पना मिश्र जी की सारी रचनाएं लगभग पारंपरिक ही हैं, उनकी कहानियां भी और उनका उपन्यास भी.

मुझे लगा कि इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और मैं आलोचक महोदय को लेकर साहित्य अकादमी की कैंटीन की तरफ बढ़ा. मौजूदा पीढ़ी के कहानीकारों पर चर्चा चल रही थी. उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम बताओ कि पिछले दस साल की कितनी कहानियां याद हैं. कहानी के गिरते स्तर को लेकर उनकी चिंता और उसका प्रकटीकरण जारी था. उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले नीलाक्षी सिंह को लेकर बहुत शोर मचा था लेकिन अब वो कहां हैं? उनकी कहानियों को अपने कंधे पर लेकर घूमने वाले संपादक भी नीलाक्षी को साहित्य या कहानी की दुनिया में स्थापित नहीं कर पाए. इन दोनों लेखकों के अलावा उन्होंने कई लेखक व लेखिकाओं के नाम गिनाए. उनका दुख यही था कि वो खूब कहानियां पढ़ते हैं लेकिन लगभग सभी कहानियों को पढ़ने के बाद उनको निराशा होती है. उनका मानना था कि हर युग में अच्छी कहानियां लिखी जाए यह आवश्यक नहीं है लेकिन कहानी को लेकर जो विवेक है, उसका बचना जरूरी है. यही विवेक आज खतरे में है. उनका कहना था कि कहानी भी गीत और गजल की तरह बाजार के जाल में फंसती जा रही है. उनका कहना था कि आज के कहानीकारों के अनुभव बहुत सीमित हैं.

मैं वापस अकादमी के परिसर में लौटा तो मेरे सामने उनकी कई टिप्पणियां थीं जिनपर विचार करना आवश्यक था. उनकी इस बात में तो मुझे दम लगा कि आज के ज्यादातर लेखक अपने समकालीन को तो नहीं ही पढ़ते हैं, अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों की रचनाओं को भी नहीं पढ़ते हैं. उनका तर्क यह होता है कि दूसरों की रचनाओं को पढ़ने से उनकी रचनात्मकता प्रभावित होगी.

मैंने उन्हें और लेखकों के बारे में कुरेदा. मुझे यह जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि समकालीन हिंदी कहानी के सभी लेखकों को वो लगभग पढ़ चुके थे. उन्होंने बताया कि हिंदी की तमाम साहित्यिक पत्रिकाएं उनके पास आती हैं और वो सबको पढ़ते हैं, नए से नए लेखकों से लेकर वरिष्ठ लेखकों तक की रचनाएं. उन्होंने माना कि वो जितनी कहानियां पढ़ते हैं, उतनी ही निराशा बढ़ती जाती है. यह एक आलोचक के अलावा एक गंभीर पाठक का भी दर्द था. उन्होंने यह भी माना कि साहित्य में गंभीर लेखन के प्रशंसकों में कमी आई है. प्रकाशक भी अब चालू और तुरत-फुरत लोकप्रियता हासिल करने वाली फूहड़ रचनाओं को तवज्जो देने में लगे हैं. करीब डेढ़ घंटे तक हमारी बातचीत होती रही. अंत में मैंने उनसे पूछा कि इस वक्त किस महिला कथाकार की रचनाओं में उनको दम नजर आता है. उन्होंने छूटते ही कहा कि इस वक्त अपनी पीढ़ी में मनीषा कुलश्रेष्ठ सबसे समर्थ रचनाकार हैं. उन्होंने मनीषा की कुछ कहानियों के नाम भी गिनाए. जब उनको मंडी हाउस के पास टैक्सी पर बिठाकर विदा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इस वक्त ही साहित्य बजबजा रहा है, लिहाजा इसपर चिंता करना.

मैं वापस अकादमी के परिसर में लौटा तो मेरे सामने उनकी कई टिप्पणियां थीं, जिनपर विचार करना आवश्यक था. उनकी इस बात में तो मुझे दम लगा कि आज के ज्यादातर लेखक अपने समकालीन को तो नहीं ही पढ़ते हैं, अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों की रचनाओं को भी नहीं पढ़ते हैं. उनका तर्क यह होता है कि दूसरों की रचनाओं को पढ़ने से उनकी रचनात्मकता प्रभावित होगी. एक मिनट के लिए अगर इस तर्क को मान भी लिया जाए तो समकालीन रचनाकारों को पढ़ने में क्या दिक्कत है. दरअसल आज की पीढ़ी के कई रचनाकारों में एक खास किस्म का एरोगैंस दिखाई देता है, बदतमीजी की हद तक. वो खुद को विद्वान ही नहीं मानते, बल्कि यह अपेक्षा भी रखते हैं कि दूसरे भी उनको ज्ञानी मानें. यहीं से उनकी रचनात्मकता बाधित होनी शुरू हो जाती है. बाधित रचनात्मकता को जब छद्म विद्वता बोध का साथ मिलता है, तब उससे उपजती है पुरस्कृत होने की चाहत और इस चाहत के वशीभूत होकर शुरू होता है पुरस्कार पाने की गोलबंदी. और तय मानिए कि जब साहित्य में गोलबंदी या घेरेबंदी शुरू हो जाए तो उसका संक्रमण काल शुरू हो जाता है. इस संक्रमण काल को आप उस दौर की रचनाओं में आसानी से लक्षित कर सकते हैं. जरूरत इस बात की है कि आज की आत्ममुग्ध पीढ़ी के रचनाकार अपने समकालीनों और पूर्ववर्तियों को पढ़ें और उनको रचनात्मक स्तर पर चुनौती पेश करें. अगर ऐसा हो पाता है तो समकालीन साहित्य का परिदृश्य बदल सकता है और कुछ अच्छी रचनाएं सामने आ सकती हैं. ■

anant.ibn@gmail.com

आलोक तोमर की पुत्री का अपने स्वर्गीय पिता के नाम पत्र

आलोक तोमर. पत्रकारिता जगत में यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. 27 दिसंबर 1960 को आलोक जी का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रछेड़ गांव में हुआ था. आलोक तोमर ने स्वदेश अखबार से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें एक प्रखर पत्रकार बनाया जनसत्ता अखबार ने. उन्होंने टीवी, प्रिंट, वेब, सिनेमा, एंटरटेनमेंट समेत कई क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य किए. साल 2000 में उन्होंने डेटलाइन इंडिया नाम से एक इंटरनेट न्यूज एजेंसी भी बनाई. केबीसी समेत कई टीवी कार्यक्रमों के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है. 20 मार्च 2011 को उनका निधन हुआ. उनके परिवार में उनकी पत्नी सुप्रिया रॉय तोमर और एक बेटी अद्याशा रॉय तोमर हैं. स्वर्गीय आलोक तोमर के निधन के 6 साल बाद, उनकी पुत्री ने अपने स्वर्गीय पिता के नाम एक बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा है. उस पत्र को हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं.

पापा,

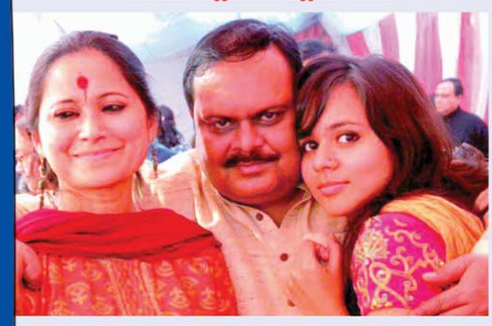

छह साल बीत गए, जब आप हमें छोड़ कर चले गए थे. तब से आज के दौरान, मैंने ड्राइविंग सीख ली. मैं कॉलेज गई, डिग्री भी हासिल कर ली. मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गई. मुझे मेरी पहली और अच्छी नौकरी भी मिल गई. मेरे पास दो पालतू कुत्ते भी हैं, पिक्सी और ओला. अब, मैं 25 साल की हो गई हूं. अब मैं वैसी बेवकूफ नहीं रही, जैसी 18 साल की उम्र में थी और तभी आप मुझे छोड़ कर चले गए थे. तब मैं सोचती थी कि ये दुनिया सिर्फ मनोरंजन और खुशियों से भरी हुई है.

आपके न होने ने मुझे सिखाया कि जिन्दगी कितनी कठिन और तन्हा हो सकती है. लेकिन, आपके न होने ने सिर्फ यही नहीं सिखाया. इसने ये भी बताया कि खुद के लिए और दूसरों के लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है, चाटुकारिता नहीं करनी है, बहुत ज्यादा ईमानदार रहना है और लिखते रहना है. मेरी बड़ी-बड़ी बंगाली आंखें मेरी मां की देन हैं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास जो भी है, सब आपका दिया हुआ है. मैं अच्छा लिख सकती हूं क्योंकि आप अच्छा लिखते थे. मैं अपने लिए और दूसरों के लिए खड़ी हो सकती हूं क्योंकि आप भी ऐसा करते थे.

इसके बावजूद, काश मैं आपको ये बता सकती कि मैं आपसे बेहतर ड्राइव करती हूं. यादें धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन एहसास धुंधले नहीं पड़ते हैं. मैं अब भी आपके कदमों की आहट महसूस कर सकती हूं. अभी भी आपका कुर्ता मुझे याद है. आपका वो पापा वाला मजाक भी याद है, जब मैं आपसे कहती थी कि पापा मैं हंग्री (भूखी) हूं तो आप कहते थे कि ओके, आई एम चेकोस्लोवाकिया. आप निरंतर मेरे साथ हैं, मेरे भीतर हैं और हमेशा बने रहेंगे. मैं नहीं जानती कि जन्नत नाम की कोई जगह होती है या नहीं, लेकिन अगर होती है, तो हम फिर मिलेंगे.

साईं वंदना

जैसा भाव वैसा गुरु

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

अपने सांसारिक ज्ञान के आधार पर आध्यात्मिक कार्य की विवेचना करना मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमी है. आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद सांसारिक ज्ञान का लोक-कल्याण के लिए ज्यादा उपयोग किया जा सकता है. अपर पक्ष में सांसारिक धर्म के नियमों का पालन करने से कोई आध्यात्मिक ज्ञान या स्थिति को प्राप्त करेगा- यह प्राय: संभव नहीं है. हालांकि दोनों मार्ग ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, किंतु सांसारिक मार्ग स्थूल और कुटिल मार्ग है तथा आध्यात्मिक मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य मार्ग है. आम आदमी अपनी इच्छा-शक्ति के प्रयोग से सांसारिक कार्य को संपूर्ण रूप से त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सक्षम नहीं है. यह रास्ता तो केवल गृह-त्यागी संत-साधु एवं जोगियों के लिए है. संत-साधु एवं सन्यासी के रूप में घूमने वाले परान्नोपजीवी (जो दूसरों के दिए हुए अन्न पर निर्भर करते हैं), कपटी और निठल्लों के दिखावे को आधार मानकर शुद्ध आध्यात्मिक-मार्ग का आकलन करना समीचीन नहीं है. फिर भी ज्यादातर लोग प्राय: इस प्रकार के दिखावे और बातों से मुग्ध होकर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं. चूंकि ज्यादातर लोगों का संसार के जंजालों से घिरा हुआ मन अशुद्ध होता है, इसलिए अपने स्वभाव के कारण अन्य अशुद्ध प्राणी-जैसे कि कपटी संन्यासी आदि किसी अन्य की ओर उनका आकृष्ट होना स्वाभाविक है. जिन लोगों के मन में शुद्धता होती है, वे स्वाभाविक रूप से सच्चे संत और संन्यासी की ओर आकर्षित होते हैं. इससे यह पता चलता है कि हर भक्त अपनी इच्छा के अनुरूप व्यक्ति को गुरु मानने को तैयार है और वह भावात्मक एवं सीमित बुद्धि से उनका आकलन करता है.

इससे यह भी प्रमाणित होता है कि जैसा मन वैसा गुरु. जिस व्यक्ति की दृष्टि शुभ हो, उसको हर चीज में शुभत्व दिखाई देगा और जिसकी दृष्टि अशुभ हो, उसे अशुभ दिखाई देगा. आम व्यक्ति क्यों, बड़े-बड़े संत और ज्ञानी भी शुभ और अशुभ दोनों गुणों से बने हुए हैं. पर यह कहा जा सकता है कि जिसके ज्यादातर गुण शुभ होते हैं और जन-कल्याण में लगते हैं, उनको हम महान् मानते हैं, यद्यपि उनके भी कुछ अवगुण शेष रहते हैं. लोग उन लोगों को बुरा मानते हैं, जिनके ज्यादातर गुण दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, यद्यपि उनमें एक-दो गुण अच्छे हो सकते हैं. जैसे हर भक्त अपने अशुभ गुण को त्याग कर शुभ गुण प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उसी प्रकाय जोगी और संन्यासी भी अनेक शुभ गुणों से युक्त होकर भी अपने शेष अवगुणों से ऊपर उठने के लिए हर वक्त प्रयत्न करते हैं. इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में रहने वाले करोड़ों-करोड़ों लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं. इस प्रकार की क्रमिक प्रगति करना ही मानव-जन्म का मूल उद्देश्य है.

धर्म-शास्त्र और मनोविज्ञान-शास्त्र, इस सत्यता पर एक मत हैं कि जो जिस प्रकार की भावना को अपने अन्दर पनपाएगा, वह आगे चलकर उसी प्रकार का बनेगा. निंदक, ईर्ष्यालु या अशुभ दृष्टि वाले व्यक्ति दूसरों की बुराई के बारे में सोच-सोचकर मानव-जीवन के अत्यंत मूल्यवान समय को नष्ट करते रहते हैं और अपने मन को कलुषित करते हैं. ऐसे लोगों को दूसरों के अच्छे गुण के स्थान पर केवल अशुभ गुण ही नजर आते हैं. अपर पक्ष में शुभ दृष्टि-संपन्न व्यक्ति हर अशुभता में भी शुभता को देखते हैं और अपने को गिरने नहीं देते. वे स्वभाव से और अनायास रूप से दूसरों की निंदा कर अपने मन को कलुषित नहीं करते हैं. इस बारे में श्री साईं सच्चरित्र में एक प्रसंग है, जिसमें बाबा ने विष्ठा खाते हुए एक सूअर की ओर इंगित कर एक निंदक से कहा था- देखो वह कितने प्रेमपूर्वक विष्ठा खा रहा है. तुम जी भर कर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के समान है. अनेक शुभकर्मों के परिणाम-स्वरूप ही तुम्हें मानव-तन प्राप्त हुआ है और इसीलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया, तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी?

ये बातें इसीलिए महत्त्वपूर्ण हैं कि दुनिया की राह पर द्वंद्व, कपटपूर्ण सांसारिक नियमों से चलने वाले लोग बहुत आसानी से गलत संगत में पड़कर अशुभ दृष्टि वाले निन्दक या ईर्ष्यालु प्राणी बन जाते हैं. इससे और किसी की हानि हो या न हो, पर वह निंदक व्यक्ति जरूर धीरे-धीरे आध्यात्मिक प्रगति के पथ से दूर होता जाता है और उसका नैतिक पतन होता है. अगर मन में इस प्रकार की भावना कभी भी आए, तो तत्काल बाबा की इस कहानी को याद करना चाहिए और उनका नाम-जाप करना चाहिए, ताकि मन की शुद्धता बच सके. रात में सोने से पहले दिन भर सोचे हुए अशुभ या गलत विचारों के बारे में चिंता कर उससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

आईपीएल में स्टार खिलाड़ियों का जमावड़ा

IPL नए कलेवर में हुआ दसवें सीज़न का आग़ाज़

आईपीएल जब शुरू हुई थी, तब किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि बीसीसीआई की यह कोशिश बड़े पैमाने पर सफल होगी. ललित मोदी के शातिर दिमाग की उपज आईपीएल को माना जाता हो, लेकिन यह भी सच है कि ललित मोदी ने आईपीएल के सहारे खूब पैसे कमाए. बीसीसीआई को जब तक इसकी भनक लगती तब तक ललित मोदी ने अकेले करोड़ों रुपए डकार लिए. इसके बाद बीसीसीआई ने ललित मोदी को बाहर किया. विदेशों में बैठकर बीसीसीआई के खिलाफ ललित मोदी ने मोर्चा खोल रखा है. हालांकि उनके जाने के बाद आईपीएल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है और बीसीसीआई ने इस लीग को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. ललित मोदी को अलग-थलग करने के बाद आईपीएल को दोबारा उसी तरह से चलाने की जिम्मेदारी बीसीसीआई पर थी. हालांकि बीसीसीआई पर इस दौरान कई आरोप भी लगे.

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) यानी दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड, लेकिन लोढ़ा समिति के आने के बाद बीसीसीआई में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है. दरअसल क्रिकेट चलाने वाली संस्था बीसीसीआई के कुनबे में लोढ़ा समिति को लेकर शुरुआती दौर में दहशत का माहौल देखा गया. इस समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद बीसीसीआई को साफ-सुथरा करने की कवायद जोरों से चल रही है. बीसीसीआई की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया आईपीएल भी अब अपने दसवें साल में प्रवेश करने जा रहा है. आईपीएल ने बीसीसीआई को रातों-रात मालामाल कर दिया, लेकिन इसी आईपीएल ने बीसीसीआई के दामन को दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. आईपीएल में हो रहे गोरखधंधे का पर्दाफाश भी हो चुका है. आईपीएल के खेल तमाशे में बोर्ड के कई लोग इसके सहारे अपनी जेब भरने में लगे रहे हैं. इसी आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग जैसे खेल का पता लगता है. इतना ही नहीं, आईपीएल में भाग लेने वाली टीमों के मालिक इस लीग के सहारे खुलेआम सट्टेबाजी को भी बढ़ावा देते रहे. तमाम विवादों को अपने दामन में समेटने वाली आईपीएल इस बार दसवें सत्र में प्रवेश कर गई. पांच अप्रैल से शुरू हुए क्रिकेट के इस मजेदार खेल को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में अलग उत्साह देखा जा सकता है. आईपीएल 2017 के लिए विश्व क्रिकेट के कई धाकड़ खिलाड़ी इस बार अपने बल्ले और गेंद से जौहर दिखाने को बेताब हैं. नीलामी में कई भारतीय खिलाड़ियों को भले मायूस होना पड़ा हो लेकिन विदेशी खिलाड़ियों की एक बार फिर चांदी हुई. इस बार की नीलामी में अफगानिस्तान जैसे देश के खिलाड़ियों को भी अपने हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है. राशिद खान जैसे अफगानी खिलाड़ी को चार करोड़ की भारी रकम में खरीदा गया है. वहीं भारतीय खिलाड़ियों में इरफान पठान जैसे ऑलरांउडर खिलाड़ी को इस बार नीलामी में कोई खरीदने वाला नहीं मिला, जबकि मोहम्मद कैफ भले ही मैदान पर खेलते न दिखें लेकिन अब वह गुजरात लायंस की टीम के सहायक कोच के रूप में एक अलग भूमिका में नजर आएंगे. आठ टीमों के बीच होने वाली इस लीग में कई बड़े खिलाड़ी अपने-अपने देश के मैच विनर खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए नजर आएंगे. इसमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो विश्व क्रिकेट में टी-20 के बेताज बादशाह माने जाते हैं. उनकी पकड़ टी-20 में ज्यादा मानी जाती है. हालांकि बिग ब्रैश जैसी लीग के कई नामी गिरामी खिलाड़ी आईपीएल में भी अपना जलवा दिखाएंगे. कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय टीम में तो नजर नहीं आते हैं लेकिन पैसे बनाने वाली लीगों में उनका रोल बेहद खास रहता है. दूसरी ओर भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो आईपीएल शुरू होने के ऐन मौके पर माही को राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स की कप्तानी से हटा दिया गया. दरअसल माही के ऊपर हाल के दिनों में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी. माही ने भारतीय टीम की कप्तानी भी छोड़ दी थी. हालांकि आईपीएल में धोनी बेहद सफल कप्तान साबित हुए हैं. उनकी कप्तानी में चेन्नई की टीम विजय रथ पर सवार थी. चेन्नई और राजस्थान जैसी टीमें अब आईपीएल में अतीत हो चुकी हैं. आईपीएल में इस बार पिछले साल की विजेता टीम सनराइज हैदराबाद अपने खिताब को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी. इसके अलावा सात और टीमें हैं जो खिताब की तगड़ी दावेदार मानी जा सकती हैं. उनमें सबसे प्रमुख विजय माल्या की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु की टीम है. विराट की कप्तानी वाली यह टीम भले ही खिताब जीतने से महरूम रही हो लेकिन कागज पर यह टीम काफी मजबूत मानी जाती है. गुजरात लायंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुम्बई इंडियंस, दिल्ली डेयरडेविल्स, राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स और किंग्स इलेवन पंजाब जैसी टीमें शामिल हैं जो प्रदर्शन के हिसाब से कमजोर नहीं कही जा सकती हैं.

आईपीएल जब शुरू हुई थी, तब किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि बीसीसीआई की यह कोशिश बड़े पैमाने पर सफल होगी. ललित मोदी के शातिर दिमाग की उपज आईपीएल को माना जाता हो, लेकिन यह भी सच है कि ललित मोदी ने आईपीएल के सहारे निजी फायदे के लिए भी खूब पैसे कमाए. बीसीसीआई को जब तक इसकी भनक लगती तब तक ललित मोदी ने अकेले करोड़ों रुपये डकार लिए. इसके बाद बीसीसीआई ने ललित मोदी को बाहर किया. विदेशों में बैठकर बीसीसीआई के खिलाफ ललित मोदी ने मोर्चा खोल रखा है. उनके जाने के बाद आईपीएल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और बीसीसीआई ने इस लीग को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. ललित मोदी को अलग-थलग करने के बाद आईपीएल को दोबारा उसी तरह से चलाने की जिम्मेदारी बीसीसीआई पर थी. बीसीसीआई पर इस दौरान कई आरोप भी लगे. उनमें आईपीएल को लेकर कई बड़े खुलासे भी हुए. उनमें सबसे प्रमुख रहा फिक्सिंग का खेल. विवाद इतना बड़ा था कि कोर्ट के दखल के बाद मामला ठंडा हुआ. खिलाड़ियों के साथ-साथ टीमों के मालिक भी आईपीएल के सहारे पैसों का ढेर लगाने के लिए उतावले दिखे. खिलाड़ी एक ओर स्पॉट फिक्सिंग जैसे खेलों को बढ़ावा दे रहे थे तो दूसरी ओर टीम के मालिक सट्टेबाजी में अपना भाग्य आजमा रहे थे. मैच के दौरान स्टेडियम में एक अलग ही नजारा होता था. आईपीएल के इस रंगीन क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के तीन खिलाड़ियों ने क्रिकेट को कहीं का नहीं छोड़ा. श्रीसंत, चंदेला और अंकित चौहान ने क्रिकेट की मर्यादा को तार-तार करते हुए स्पॉट फिक्सिंग के नए खेल को इंट्रोड्यूस किया. तीनों को इस करतूत के लिए जेल की हवा तक खानी पड़ी थी. खैर, अब यह सब अतीत का हिस्सा बन चुका है. आईपीएल इस बार नए कलेवर के साथ सामने आ रहा है. दरअसल बीसीसीआई में भारी बदलाव के बाद आईपीएल 2017 शुरू हुआ है. इसमें कुछ नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जबकि कुछ पुराने खिलाड़ी कोच के रूप में शामिल हैं.

बात अगर खिताब की दावेदारी की हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु की टीम तगड़ी मानी जाएगी. टीम के पास कोहली जैसा कप्तान मौजूद है, जबकि गेल का तूफान किसी से छुपा नहीं है. एबी डीविलियर्स की खतरनाक बल्लेबाजी भी इस टीम को मजबूत बनाती है. इस टीम में कई धाकड़ भारतीय खिलाड़ी हैं. उनमें केएल राहुल और केदार जाधव सबसे प्रमुख हैं. हाल के दिनों में दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने बल्ले के पराक्रम से सबको चौंका दिया था. यह बात भी सत्य है कि आईपीएल के इस अजूबे खेल में यह टीम कई मौकों पर बिखरी नजर आई है. पिछले साल यह टीम उपविजेता रही, लेकिन इस बार खिताब के लिए पूरा जोर लगाने को तैयार है. कोलकाता नाइट राइडर्स की चुनौती को भी कम नहीं आंका जा सकता है. इस टीम के पास भी कई बड़े खिलाड़ी हैं जो केवल टी-20 में अपना जलवा दिखा चुके हैं. टीम में गम्भीर का रोल भी अहम है, जबकि यूसुफ पठान का बल्ला अगर चल निकला तो दुनिया के कई गेंदबाजों की शामत आनी भी तय है. टीम का टॉप ऑर्डर अगर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करता है तो इस टीम को रोकना आसान नहीं होगा. रैना के सहारे जीत का सपना देख रही गुजरात लायंस पर क्रिकेट प्रेमियों की खास नजर होगी क्योंकि यह टीम अपने पहले सीजन यानी 2016 के सत्र में बेहद शानदार क्रिकेट का नमूना पेश कर चुकी है. टीम के पास कुछ टी-20 के गजब के खिलाड़ी मौजूद हैं. उनमें कीवियों के शेर वैंडन मैकुलम और फिंच शामिल हैं जबकि मध्यक्रम में भी कई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं. दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम भले ही कमजोर लग रही हो लेकिन वह बड़ी टीमों को हराने का माद्दा रखती है. मुम्बई इंडियंस की टीम भी अच्छी कही जा सकती है. इस बार सबकी नजर रोहित शर्मा पर होगी. दरअसल चोट के चलते रोहित शर्मा क्रिकेट से दूर रहे हैं लेकिन आईपीएल में वापसी करेंगे. किंग्स इलेवन पंजाब की टीम भी खिताब की होड़ में शामिल है. इस टीम के पास ग्लेन मैक्सवेल जैसे तगड़े खिलाड़ी शामिल हैं जो अपने जांबाज खेल से मैच का रुख बदलने का हुनर रखते हैं. टीम के पास कुछ अच्छे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ-साथ कीवी खिलाड़ियों का होना भी टीम को मजबूती देता है. राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स की टीम इस बार धोनी की कप्तानी में आईपीएल में नहीं उतर रही है बल्कि स्टीव स्मिथ की कप्तानी में दिखेगी. ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ बेहद जुझारू कप्तान हैं. ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि वह यहां कैसी कप्तानी करते हैं. दूसरी ओर साल 2016 की विजेता टीम सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पर भी उम्मीदों का बोझ होगा. टीम के पास युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं जो इस फॉर्मेट के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं. ■

आईपीएल में अब तक के विजेता इस प्रकार हैं:

2008	राजस्थान रॉयल्स
2009	डेक्कन चार्जर्स
2010	चेन्नई सुपर किंग्स
2011	चेन्नई सुपर किंग्स
2012	कोलकाता नाइट राइडर्स
2013	मुम्बई इंडियंस
2014	कोलकाता नाइट राइडर्स
2015	मुम्बई इंडियंस
2016	सनराइजर्स हैदराबाद

feedback@chauthiduniya.com

टाइगर जिंदा है में विलेन से होगी सलमान खान की कड़ी टक्कर

सलमान खान-कैटरीना कैफ की फिल्म *टाइगर जिंदा है* आजकल सुर्खियों में है. फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रिया में चल रही है, जहां से कई तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं. यहां फिल्म की कुछ धमाकेदार एक्शन सीन्स भी शूट होने वाली है. फिल्म के एक सीन में सलमान खान भेड़ियों का मुकाबला करते भी दिखेंगे. अभी तक फिल्म के विलेन को लेकर सस्पेंस बना था. लेकिन जानकारी मिली है कि फिल्म में साउथ के हीरो सुदीप निगेटिव किरदार में दिखेंगे और सलमान खान से टक्कर लेंगे.

फिल्म में दोनों के बीच गजब के एक्शन सीन्स होंगे. पता चला है कि फिल्म में सुदीप आईएसआई एजेंट का किरदार निभा रहे हैं, जो पाकिस्तान में रहता है.

बता दें कि इससे पहले अभिनेता सुदीप को रामगोपाल वर्मा की बॉलीवुड फिल्म फूंक में देखा गया था.■

शादी की तैयारी में हैं कंगना!

मुझे लगता है जब आप 20-25 साल की उम्र में होते हैं, तब ऐसा ही सोचते हैं. मुझे याद है मेरी मां हमेशा मुझे कहती थीं, तब मुझे लगता था कि वो मेरी लाइफस्टाइल को नहीं समझती हैं. लेकिन 30 के आसपास की उम्र में जब अंदर से शादी की भावनाएं आती हैं, तब आप काफी अलग तरीके से चीजों को देखने लगते हैं. कंगना आगे कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा उम्र बढ़ने की वजह से या डर से होता है, बल्कि यह सच में काफी अच्छा लगता है, जब कोई आपका इंतजार करे. मुझे लगता है कोई भी अपने रिश्ते में पूरी कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं अपने रिश्ते में पूरी कोशिश करना चाहती हूं.

बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने हाल में अपने बयान से सभी को चौंका दिया कि वह इसी साल शादी कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि वे इन दिनों रिलेशनशिप में हैं. हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी, लेकिन कंगना ने हाल के दिनों में दो इंटरव्यू के दौरान अपनी शादी की बात की है. कंगना ने कहा, *समय आएगा तो मैं शादी जरूर करूंगी और मैं शादी से भागने वालों में से नहीं हूं. मैं कुछ भी नहीं छिपाना चाहती हूं क्योंकि मैं वैसी हूं ही नहीं.*

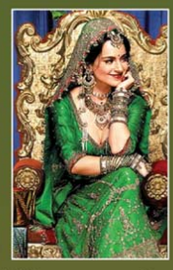

एक इंटरव्यू में कंगना से जब उनकी शादी को लेकर कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा, एक समय था जब मुझे लगता था कि आखिर लोग शादी करते ही क्यों हैं? मुझे लगता है जब आप 20-25 साल की उम्र में होते हैं तो ऐसा ही सोचते हैं. मुझे याद है मेरी मां हमेशा मुझे कहती थीं, तब मुझे लगता था कि वो मेरी लाइफ स्टाइल को नहीं समझती हैं. लेकिन 30 के आसपास की उम्र में जब अंदर से शादी की भावनाएं आती हैं, तब आप काफी अलग तरीके से चीजों को देखने लगते हैं. कंगना आगे कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा उम्र बढ़ने की वजह से या डर से होता है, बल्कि यह सच में काफी अच्छा लगता है, जब कोई आपका इंतजार करे. मुझे लगता है कोई भी अपने रिश्ते में पूरी कोशिश नहीं करता है, लेकिन मैं अपने रिश्ते में पूरी कोशिश करना चाहती हूं.

शादी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह शादी के बाद अपने रिश्ते को पूरी तरह निभाना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सामने वाला भी यही नजरिया रखे. कंगना ने कहा कि उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया है. वे उसे बहुत प्यार करती हैं, पर वे फिलहाल उसे डेट करने के बारे में विचार नहीं कर रही हैं, बल्कि शादी करना चाहती हैं.

बता दें कि कंगना का नाम कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है. सबसे पहले उनका नाम आदित्य पंचोली और अध्ययन सुमन के साथ जुड़ा था. कंगना ने यह भी कहा था कि वह ऋतिक रोशन को भी डेट कर रही हैं. जब कंगना ने ऋतिक को अपना *सिली एक्स* कहा तो उसके बाद इन दोनों के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था.■

अजय-सलमान की दोस्ती ख़तरे में!

प्रदीप कुमार
feedback@chauthiduniya.com

वांटेड फिल्म का यह डायलॉग *एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता.* सलमान खान ने अपने इस डायलॉग को असल ज़िंदगी में सही साबित कर दिया है. फिल्म *बैटल ऑफ सारागढ़ी* से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाते हुए सलमान ने साफ किया कि वह अभी फिल्म के साथ जुड़े हैं और इसे जरूर बनाएंगे. सलमान खान ने कुछ समय पहले ट्वीट करते हुए कहा कि *Don't follow rumors . follow me . ek baar jo maine commitment kar di toh phir..... vry much doing film with @akshaykumar*

-Salman Khan @BeingSalmanKhan

बता दें कि अजय देवगन ने काफी समय पहले ही अपनी होम प्रोडेक्शन फिल्म *सन ऑफ सरदार: द बैटल ऑफ सारागढ़ी* बनाने का ऐलान कर दिया था. फिर बीच में ख़बर आई थी कि करण जौहर भी सलमान खान और अक्षय कुमार को लेकर सारागढ़ी की लड़ाई पर फिल्म बनाने वाले हैं. इसे लेकर अजय देवगन ने अपनी नाराजगी सलमान खान से पहले ही जाहिर कर दी थी. इस नाराजगी को लेकर सलमान खुद अजय की फिल्म बादशाहों के सेट पर उनसे मिलने गए थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा. दोस्ती को ध्यान में रखते हुए सलमान इससे पीछे भी हट गए थे.

लेकिन सलमान ने पिछले दिनों नए ट्वीट से इन अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सलमान और अजय की दोस्ती कितनी कामयाब रह पाती है. वैसे भी इस फिल्म को सलमान खान और करन जौहर मिलकर प्रॉड्यूस कर रहे हैं और इसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में होंगे. सलमान ने कहा है कि वे अक्षय की इस फिल्म का हिस्सा बने रहेंगे.

करण जौहर और अजय देवगन पहले से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं. शायद इसी का नतीजा है कि करण एक बार फिर अजय देवगन से टक्कर लेना चाहते हैं. करण जौहर भी जानते थे कि अजय पहले से ही सारागढ़ी की लड़ाई पर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे है. अगर सारागढ़ी पर दोनों फिल्में बनाते हैं, तो ये टक्कर अजय देवगन को अकेले ही बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान और करण जौहर से लेनी होगी. जो अजय को काफी नुकसान भी पहुंचा सकते है. वैसे फिल्म इंडस्ट्री में ये पहली बार नहीं है, जब दो लोग एक ही विषय पर फिल्म बनाएंगे. इससे पहले भगत सिंह पर चार फिल्में बन चुकी हैं.

बता दें कि सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 में हुआ था. ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 36 जवानों ने अफगान ओराकजई के योद्धाओं के साथ जंग लड़ी थी. ■

फ्लैश बैक

याद आता है वो गुजरा जमाना: लता

भारत रत्न लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था. लता जी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका छह दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है. उनकी आवाज़ ने छह दशकों से भी ज़्यादा समय तक संगीत की दुनिया को सुरों से नवाज़ा है. लता जी ने 20 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं. उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आ गए, तो न जाने कितानी बार सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला. लता जी आज भी अकेली हैं, उन्होंने स्वयं को पूर्णत: संगीत को समर्पित कर दिया है. आइए जानते हैं लता जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य...

1- लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ. उनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे इसलिए संगीत उन्हें विरासत में मिली. लता मंगेशकर का पहला नाम *हेमा* था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता-पिता ने इनका नाम *लता* रख दिया था.

2- लता दीदी महज एक दिन के लिए स्कूल गई थीं. इसकी वजह यह रही कि जब वह पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोसले को लेकर स्कूल गईं, तो अध्यापक ने आशा भोसले को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी. बाद में लता ने निश्चय किया कि वह कभी स्कूल नहीं जाएंगी. हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित छह विश्वविद्यालयों में मानक उपाधि से नवाज़ा गया.

3- लता को अपने सिने करियर में बहुत मान-सम्मान मिला है. वे फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

4- दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने के लिए लता जी का नाम *गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड* में दर्ज है.

5- लता जी गाने की रिकॉर्डिंग पर जाने से पहले कमरे के बाहर अपनी चप्पलें उतारती हैं. वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती हैं.

6- लता की सबसे पसंदीदा फिल्म द किंग एंड आई है. हिंदी फिल्मों में उन्हें त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे और मधुमती पसंद हैं. वर्ष 1943 में प्रदर्शित फिल्म किस्मत उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने यह फिल्म तकरीबन पचास बार देखी थी.

7- लता ने मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत गाए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, जब उन्होंने रफी से बातचीत बंद कर दी थी. लता गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थीं, जबकि मोहम्मद रफी ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की. दोनों का विवाद इतना बढ़ा कि मोहम्मद रफी और लता के बीच बातचीत भी बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गीत गाने से इंकार कर दिया था. हालांकि चार वर्ष के बाद अभिनेत्री नरगिस के प्रयास से दोनों ने एक साथ एक कार्यक्रम में *दिल पुकारे* गीत गाया.

8- वर्ष 1962 में लता 32 साल की थी, तब उन्हें स्लो प्वॉइजन दिया गया था. लता की बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है. हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है.■

लता मंगेशकर ने क्यों नहीं की शादी?

दरअसल घर के सभी सदस्यों की ज़िम्मेदारी मुझ पर थी. ऐसे में कई बार शादी का ख़याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी. बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी. बहुत ज़्यादा काम मेरे पास रहता था. सोचा कि पहले सभी छोटे भाई-बहनों को व्यवस्थित कर दूं, फिर कुछ सोचा जाएगा. बहन की शादी हो गई. बच्चे भी हो गए, फिर उन्हें संभालने की ज़िम्मेदारी आ गई और इस तरह वक़्त निकलता गया.■

याद आता है वो पुराना ज़माना

हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो वह काफी मुश्किल दौर था. एक जगह से दूसरी जगह रिकॉर्डिंग के लिए भागना. बारिश में भीगते हुए, धूप में तपते हुए इधर-उधर जाना. लेकिन जो काम करते थे, उसमें बड़ी संतुष्टि मिलती थी. बहुत मेहनत के साथ जो गाने गाते थे, उन्हें सुनकर बड़ा अच्छा लगता था. मुकेश भैया जैसे लोग बड़े याद आते हैं. वे इतने सज्जन थे कि पूछिए मत और किशोर दा, वो तो कमाल थे. उनके किस्से सुनाने बैठूंगी तो आप हंसते-हंसते पेट पकड़ लेंगे. सच में, बड़ा याद आता है वो ज़माना.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com